

In Pursuit of Truth

वर्ष: 21 | संक: 21
01 से 15 अगस्त 2023
पृष्ठ: 48
मूल्य: 25 रु.

आक्स

पाक्षिक



क्यों आग में जल रहा मणिपुर?

हिंसा... नग्न परेड और शर्मसार होता देश...

जो पहले एक-दूसरे के दुश्मन थे,
आज एक होकर मैतेई से लड़ रहे हैं... क्यों?

मणिपुर के हालात का कौन है असली
गुनहगार... प्रशासन, विपक्ष या सरकार...?

mycem
cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality
Over 150 Years



Send 'Hi'  7236955555

विकास

9

‘कहीं का ईंट,
कहीं का रोड़ा...’

मप्र आज विकास का पर्याय बना हुआ है। इसके पीछे प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का विशेष योगदान है। इन्हीं में से एक हैं प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सुरखी विधानसभा...

राजपथ

10-11

आकांक्षी सीटों
पर लड़ना...

विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारों ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है। खासकर भाजपा में टिकट के दावेदारों की कतार दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। टिकट चाहने वालों में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक...

बिजली

15

रिंग-विंग फेंसिंग
से रुकेगा...

मप्र बिजली के मामले में बीते 19 सालों में तेजी से आगे बढ़ा और आत्मनिर्भर बना है। प्रदेश लालटेन युग से निकलकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। वर्तमान में बिजली का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है। मप्र दिल्ली मेट्रो तक को बिजली बेच रहा है।

विडंबना

18

महंगाई की चपेट
में वंदे भारत ट्रेन

इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। महंगे किराए के कारण यात्रियों ने इस ट्रेन से दूरी बना रखी है। इस ट्रेन में 76.32 प्रतिशत सीटें खाली रहीं। एक माह में इंदौर से भोपाल के बीच...



एक तरफ दावा किया जा रहा है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगभग 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आलम यह है कि मणिपुर में हिंसा, नग्न परेड से देश शर्मसार हो रहा है। राज्य में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई शांति समिति के बाद भी असंतोष और दो गुटों के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।



राजनीति

30-31

गठबंधन की
राजनीति...

संग्रम की जगह इंडिया को जिन राज्यों में दिक्कत हो सकती है उसमें 80 लोकसभा सीटों वाला उप्र, 40 सीटों वाला बिहार शामिल है। यानी कुल 120 सीटें हैं। इसी तरह अंग्रेजी नाम से असहज राज्यों में राजस्थान की 25, मप्र की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें यानि कुल 65 सीटें हैं।

महाराष्ट्र

34

अनोखे गठबंधनों
वाली सरकार

देशभर की राजनीति में महाराष्ट्र अनोखे राजनीति गठबंधनों वाला इकलौता राज्य बन गया है। वहां अब देश के दो बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन दो राजनीतिक दलों के दो गुटों के साथ हैं। भाजपा के साथ शिवसेना का शिंदे गुट है, तो कांग्रेस के साथ उद्धव वाली...

बिहार

37

चक्रव्यूह में
नीतीश

आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कल तक भतीजे को आगे बढ़ाने की बात करने वाले नीतीश कुमार के सामने अब एक नई चुनौती आ गई है। करप्शन, कम्यूनलिज्म और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात...

6-7

अंदर की बात

40

महिला जगत

42

अध्यात्म

43

कहानी

44

खेल

45

फिल्म

46

व्यंग्य



मुफ्त की रेवड़ी राज्यों को बना न दे कंगाल...

कि सी शायर ने क्या खूब लिखा है...

हवा में ताश का महल नहीं बनता,
रोने से बिगड़ा मुकदमर नहीं बनता।

इस बात को हमारे राजनेता कब समझेंगे? दरअसल, जब भी चुनाव आता है, वे ताश के महल बनाने लगते हैं। यानी मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में दो संप्रभु मुल्कों के मुफ्त की रेवड़ी के हालतों पर जरा गौर फरमाइए। कभी अमीर मुल्क कहलाने वाले वेनेजुएला के हुक्मरान फर्रत वोट पाने के लिए मुफ्त की योजनाओं में धन बांट-बांट कर उसे कंगाल बना चुके हैं। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी मुफ्त की रेवड़ी के मकड़जाल में फंसकर तबाह हो चुकी है। वहां का अर्थतंत्र चौपट और दीवालिया हो गया है। लेकिन इनसे हमारे हुक्मरान कब सबक लेंगे। जब भी चुनाव आता है, घोषणाओं का अंबार लगने लगता है। फोकट का चंदन बांटने का यह महारोग योजनाओं में अनुदान, स्वेच्छानुदान के नाम पर नकदी हस्तांतरण, गैस सिलेंडर और मुफ्त की लोक-लुभावनी यानी फ्रीबीज योजनाओं में सर्वाधिक है, जिससे शासकीय खजाने रीते होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में मद्र में भी यही हो रहा है। मद्र में विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकलुभावन घोषणाओं की बौछार करनी शुरू कर दी है। खराबकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस की ओर से लगातार चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। इन चुनावी लॉलीपॉप और झुनझुनों को अगर अमलीजामा पहनाया गया तो करीब 2 खरब 8 अरब रूपए खर्च होंगे। गौरतलब है कि पहले से ही करीब सवा तीन लाख करोड़ रूपए के कर्ज में डूबी सरकार पर यह अतिरिक्त बोझ प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। मद्र में पिछले कई महीनों से चुनावी घोषणाओं का दौर चल रहा है। नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार, चाहे वह सत्तारूढ़ भाजपा की वापसी हो या कांग्रेस सत्ता में आए, को वित्त का प्रबंध करना मुश्किल होगा। पिछले कुछ महीनों में की गई घोषणाओं से सरकारी खजाने पर सालाना 17 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मद्र सरकार का औसत मासिक खर्च करीब 22 हजार करोड़ रूपए है, जो हालिया घोषणाओं और कार्यान्वयन के कारण प्रतिमाह 23 हजार 822 करोड़ रूपए के करीब हो जाएगा। एक जानकारी के मुताबिक मद्र सरकार इस साल 6 महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि, 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का यह दूसरा कर्जा है। गौरतलब है कि मद्र सरकार पर वर्तमान में करीब 3 लाख 30 हजार करोड़ का कर्ज है। उसके बावजूद लगातार चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। राज्य सरकार पहले से वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है और इन घोषणाओं की बढ़ौलत सरकार के राजकोष पर और बोझ पड़ने वाला है। फिर भी चुनावी साल में मद्र सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए हैं। इससे यह बात तो तय है कि घोषणा करने वालों को इसका लाभ मिले या न मिले, लेकिन जनता पर आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा। दरअसल, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जब भी चुनाव आता है, वह पार्टियों की तरफ इस आशा से देखने लगती है कि उन्हें कुछ न कुछ चुनावी सौगात जरूर मिलेगी। लेकिन यह सौगात कितनी महंगी होगी, यह महंगाई की मार के बाद उन्हें पता चलता है।

- राजेन्द्र आगाल

प्राधिकृत
अक्षर

वर्ष 21, अंक 21, पृष्ठ-48, 1 से 15 अगस्त, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MP/PL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संपादकता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी

075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुत्री

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन खुर्वशी, खुर्वशी कॉलोनी, इंदौर,

मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वातंत्र्यकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



टिकट के लिए दौड़

मप्र में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी दलों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। कई नेता टिकट के लिए भागा-दौड़ी भी कर रहे हैं।

● रोहन सिंह, इंदौर (म.प्र.)

मणिपुर में बवाल

मणिपुर में चल रही हिंसक घटनाओं को लेकर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मणिपुर की जनता सश्रौफ में है। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां सबकुछ सामान्य हो जाए।

● प्रियांशी यादव, भोपाल (म.प्र.)

घोटाले की जांच हो

केंद्र सरकार ने गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, ताकि गरीब परिवारों को परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन प्रदेश के एक घोटाले ने इस योजना पर दाग लगा दिया है। सरकार को इस मामले से सख्ती से निपटना चाहिए।

● पंकज मिश्रा, ग्वालियर (म.प्र.)



हंगामे की विधानसभा

विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। विधायक चुने जाने वाले नेता ही विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाकर उस पर चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर सरकारें नियम व कानून बनाती है। लेकिन मप्र की विधानसभा में विधायक जनता के मुद्दों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बहस करने में मशगूल नजर आते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में बहस के लिए जाता है, लेकिन वहां न किसी मुद्दे पर ठीक तरह से बात होती है और न ही किसी मुकाम पर पहुंचा जाता है। यहां पर होने वाले सवाल-जवाबों के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था होती है, लेकिन अब प्रदेश में स्थितियां अलहदा होती जा रही हैं।

● अमृता खेन, जबलपुर (म.प्र.)

यूसीसी से लड़कियों को फायदा

समान नागरिक संहिता एक अच्छा कदम है। इससे सभी वर्गों को सामान्य अधिकार मिलेंगे। इसके लागू होने से सबसे बड़ा फायदा लड़कियों को होगा। इससे लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, ताकि वह ग्रेजुएट हो जाएं, और किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहें, खुद आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार का ध्यान रखें। ग्राम स्तर पर शादी के पंजीकरण की सुविधा होगी। बिना पंजीकरण सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी। पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार होंगे। बहु-विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।

● कुसुम साहू, नई दिल्ली



चीतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं

सितंबर 2022 में नामीबिया और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया था। देशभर के पर्यटकों के लिए विदेश से मप्र के कूनो अभयारण्य में कुल 20 चीतों को लाया गया था, ताकि पर्यटकों को लुभाया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभयारण्य का माहौल चीतों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इससे आए दिन किसी न किसी चीते की मौत की खबर सुनने को मिल रही है। सरकार को उनकी देखभाल के लिए उन्हें कहीं ओर शिफ्ट करना चाहिए।

● अनुराग सोनी, इयोपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



एनडीए का बढ़ेगा कुनबा

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ा रही है। अब एनडीए में दो और दलों के शामिल होने की संभावना है। इनमें एक पार्टी बिहार से और दूसरी उप्र से शामिल हो सकती है। बिहार में भाजपा की चर्चा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और उप्र में महान दल से हो रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बिहार भाजपा के दो नेता मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं उप्र में भाजपा ने महान दल से भी संपर्क किया है। उप्र में भाजपा के पास भारी वोट शेयर है और बिहार में भी अच्छा मत प्रतिशत है, लेकिन दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों को जगह दे रही है। गौरतलब है कि अभी एनडीए में 38 पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से कई ने अपनी स्थापना के बाद से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती है। इनमें 10 पार्टियां ऐसी हैं, जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 15 दलों ने चुनाव लड़ने के बावजूद संसद के किसी भी सदन में कोई सांसद नहीं है। 26 विपक्षी दलों ने जब एक संयुक्त मोर्चे का ऐलान किया, इसके बाद एनडीए का भी विस्तार हुआ है। भाजपा ने एनडीए की बैठक बुलाई। पिछले कुछ सालों में संस्थापक सदस्यों शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना जैसे दलों ने साथ छोड़ दिया था।

अभी और टूटेगा शरद कुनबा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद दिग्गज शरद पवार को और भी सियासी झटके लग सकते हैं। अटकलें हैं कि हाल ही में सीनियर पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक का हिस्सा रहे तीन विधायक अजित पवार के संपर्क में हैं। खबर है कि तीनों ने महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। हालांकि अब तक इसे लेकर अजित या शरद कैंप की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, विधायक चेतन तुपे और सुनील भुसारा हाल ही में अजित से मिले थे। इनमें टोपे, भुसारा और अजित के बीच बैठक हुई है। बहरहाल तीनों ही विधायक यह कहते रहे हैं कि वे सीनियर पवार के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा यशवंतराव चव्हाण केंद्र में आयोजित बैठक का भी हिस्सा रहे थे। लेकिन ताजा सियासी घटनाक्रम ने चर्चाएं तेज कर दी हैं। दरअसल अजित कैंप को दल-बदल कानून से बचने के लिए करीब 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस को 40 विधायकों के समर्थन की सूची भी दे दी है। लेकिन अजित की बैठक में 32 विधायक ही शामिल हुए थे। ऐसे में चर्चा है कि अजित कुछ और विधायकों को अपने पाले में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।



राजस्थान में सबकुछ ओके

राजस्थान में गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान अब गंभीरता से जुट गया है। 29 मई को हुई बैठक को इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। आलाकमान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गहलोत और पायलट के बीच चल रहा झगड़ा सुलझ गया है। इसके उलट सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो कथा पोस्ट की उसने फिर संदेह खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में पायलट आम जनता के साथ नजर आ रहे हैं। पर, न तो कांग्रेस का चुनाव निशान कहीं नजर आता है और न ही पायलट के अलावा पार्टी का कोई दूसरा नेता इसमें है। इससे यह सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या पायलट ने अपनी अलग पार्टी बनाने का इरादा छोड़ा नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आपसी विवाद को तो भाजपा भी मुद्दा बनाना चाह रही है।

इस बार रावण भी मैदान में

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। खबर है कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें जयंत चौधरी के उस बयान के बाद से लगाई जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही चंद्रशेखर संसद के अंदर होंगे। उन्होंने यह बात जंतर-मंतर पर भीम आर्मी प्रमुख की ओर से आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कही है। इस रैली में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी को न्यौता दिया था। जयंत न सिर्फ रैली में शामिल हुए बल्कि वहां जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हुआ हमला केवल उन पर नहीं था, बल्कि यह हमला अनुसूचित जाति के लोगों को शांत करने और डराने के लिए हुआ। लेकिन आप डरना मत। आप आगे बढ़ना और दुनिया को ये बता देना की इस देश का संविधान भी आप में से ही एक ने कभी लिखा था।

धामी कैबिनेट में बदलाव की आहट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीते दिनों चार दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद से राज्य में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाएं हैं कि आने वाले कुछ दिनों में धामी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। इन चर्चाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर संगठन ने मंत्रियों की परफॉर्मंस रिपोर्ट भी मांगी थी। ऐसे में उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जिसके बाद से ही संभावना जताई जा रही है कि धामी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। यही नहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के चौथे दिन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया था, वहीं जब मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की तो इस बात को अधिक बल मिलने लगा कि कैबिनेट विस्तार पर हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है कि खाली पड़े चारों मंत्री के पदों को भरा जाएगा या कुछ पदों को ही भरा जाएगा।

कौन कहता है मप्र गरीबों का प्रदेश है...

देश के हृदय प्रदेश मप्र की तासीर ही कुछ ऐसी है कि लोग इसे जिस चश्मे से देखते हैं, वैसा दिखता है। कोई इसे गरीब, तो कोई समस्याग्रस्त राज्य के रूप में देखता है। दरअसल, प्रदेश की अधिकांश आबादी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मप्र गरीब नहीं है। यह हम नहीं बल्कि यहां के अफसरों की कमाई और उनकी अचल संपत्ति को देखकर दावा किया जा सकता है। मप्र हो या देश का कोई भी कोना प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स निवेश करने में किसी से पीछे नहीं हैं। ताजा नजारा वेस्टर्न हाईवे के आसपास देखने को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि होशंगाबाद से शुरू होकर राजधानी से होते हुए इंदौर तक जाने वाले इस वेस्टर्न हाईवे के किनारे प्रदेश के मालदार अधिकारियों ने जमकर निवेश किया है। बताया जाता है कि हाईवे के दोनों तरफ अधिकांश जमीनों इन अफसरों ने मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली हैं। सूत्रों का कहना है कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अफसरों ने यह निवेश किया है और आने वाले समय में और अफसर बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि राजधानी भोपाल हो या फिर व्यवसायिक राजधानी इंदौर, यहां बड़ी से बड़ी निजी परियोजनाओं में अफसरों ने बड़े स्तर पर निवेश किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मप्र की अधिकांश आबादी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, ऐसे में अफसरों की कमाई कैसे बढ़ रही है।

ABCD की जुगाड़... सब खुशहाल

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, साहब ने अपने जुगाड़ डॉट कॉम से पुलिस विभाग के 85 फीसदी लोगों को खुश कर दिया है। जब साहब के इस फॉर्मूले की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बताया जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एक ही स्थान पर 3 साल या उससे अधिक समय से पदस्थ पुलिस वालों में हड़कंप मच गया है। सबको इस बात का डर सताने लगा कि न जाने कहां उनका तबादला होगा। ऐसे में कानोंकान यह बात पुलिस मुख्यालय भी पहुंच गई। इस खबर को सुनते ही एडिशनल डीजी स्तर के एक साहब की बांछें खिल गईं। साहब ने सबको खुश करने के लिए फॉर्मूला निकाला कि किसी को तबादले के नाम पर सजा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जासूसों के माध्यम से यह खबर फैला दी कि जो जहां चाहता है, उसे वहीं पदस्थ किया जाएगा। बताया जाता है कि साहब ने इसके लिए ए, बी, सी, डी चार कैटेगिरी भी बना रखी थी। उस कैटेगिरी के हिसाब से पुलिस वालों को मनचाही जगह पदस्थ कर खुश कर दिया गया। बस उन्हें कैटेगिरी के हिसाब से फीस चुकानी पड़ी। बताया जाता है कि साहब ने अपनी जुगाड़ डॉट कॉम स्कीम के लिए अपने पद का भरपूर दुरुपयोग किया।



लक्ष्मीपुत्र अफसरों की कंस्ट्रक्शन कंपनी

शीर्षक पढ़कर आप जो सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अफसरों ने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोली है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जरूर ऐसी है, जिसमें लक्ष्मीपुत्र अफसरों की भरपूर काली कमाई लगी हुई है। प्रदेश के हृदय प्रदेश में स्थित इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर विगत दिनों जब आयकर विभाग का छापा पड़ा था तो यह तथ्य सामने आया था कि कंपनी में अफसरों की काली कमाई लगाई गई है। सूत्रों का कहना है कि जहां इसमें अफसरों की काली कमाई लगी है, वहीं शहर और प्रदेश के कई धनाढ्यों का भी पैसा लगा हुआ है। इनमें से एक मंत्री के खासमखास भी हैं। इन्होंने राजधानी के पास स्थित एक जिले में एक होटल खोल रखा है। यह होटल अफसरों की सैरगाह बना हुआ है। वहीं जिन व्यक्ति की यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वे भी अफसरों को रिझाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते हैं। जानकारों का कहना है कि अक्सर वे रात को पार्टियां देते हैं, जिसमें शहर के हर तरह के लोग शामिल होते हैं। बताया जाता है कि इसी पार्टी में काली कमाई निवेश करने के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ये बिल्डर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खासमखास भी हैं। ये साहब सीएस की दौड़ में भी शामिल थे। बताया जाता है कि जिस दिन सीएस का नाम फाइनल होना था, उस दिन रातभर बैठकर इन लोगों ने जमकर लॉबींग भी की थी। लेकिन बात नहीं बन पाई।

कमाई का नायाब तरीका

कभी-कभी कुछ अफसर ऐसा कर जाते हैं, जिसके कारण वे चर्चा में बने रहते हैं। विंध्य क्षेत्र में पदस्थ एक डीआईजी इन दिनों अपने लक्ष्मी कमाने के फॉर्मूले के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जाता है कि जब साहब की शासन-प्रशासन की ओर से पूछ-परख नहीं होती है तो वे अपने पर उतर आते हैं। फिर क्या वे अपना फॉर्मूला लगाते हैं और मातहतों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर देते हैं। साहब की विभागीय जांच का यह असर होता है कि किसी न किसी गोरखधंधे में लिप्त रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी साहब की परिक्रमा करने लगते हैं। अफसरों की परिक्रमा को देखकर साहब भी गदगद हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है माल बटोरने का सिलसिला। साहब तथाकथित जांच को दबाने के लिए मोलभाव पर उतर आते हैं। उसके बाद दबाव बनाने का सिलसिला शुरू होता है और साहब उनसे अपनी मर्जी के हिसाब से रकम बटोर लेते हैं। जानकारों का कहना है कि साहब के इस फॉर्मूले की खबर ऊपर तक पहुंच गई है। अब देख यह है कि उन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।

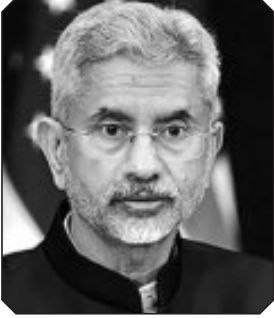
यह फॉर्मूला सबको भाया

ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले से आने वाले एक मंत्रीजी ने अपना खुद का खजाना भरने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। यहां बता दें कि जिस मंत्रीजी की यहां बात हो रही है उनके पास सरकार का आधा विभाग है। यानी माननीय जिस बड़े विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग की हैसियत प्रदेश के आधे विभागों के बराबर की है। बताया जाता है कि जबसे माननीय इस विभाग के मंत्री बने हैं, तबसे उनकी चांदी कट रही है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के पास जब भी विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, वे उसे गंभीरता से लेते हैं और उस शिकायत पर तत्काल नोटिस जारी कर देते हैं। इससे विभाग में हड़कंप मच जाता है। इस हड़कंप के बाद मंत्रीजी के खास लोग वसूली अभियान में जुट जाते हैं। जिस पर जैसा आरोप लगा रहता है, उससे उस हिसाब से रकम वसूली जाती है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी का यह पूरा उपक्रम केवल वसूली अभियान तक ही सीमित रहता है, क्योंकि वे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।



महात्मा गांधी ने नारा दिया था- अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज का मंत्र है- भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। यह क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा।

● नरेंद्र मोदी



विपक्ष केवल हंगामे पर उतारू है। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। मेरा कहना है कि राजनीति अलग रखें। संसद में हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि विपक्ष हंगामा छोड़ काम की बात करे, लेकिन लगता नहीं है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा। ऐसे में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है।

● एस जयशंकर



भारत की क्रिकेट टीम आज विश्व की सबसे मजबूत टीम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टीम का हर सदस्य अपना बेहतर देने की कोशिश करता है। जडेजा और अश्विन हमेशा से बैटिंग में टीम की स्ट्रेंथ रहे हैं। खास तौर पर जडेजा जिस तरह पिछले कुछ समय से बैटिंग कर रहे हैं, उससे भारतीय टीम और मजबूत हुई है। भारतीय बेंच भी काफी मजबूत है।

● राहुल द्रविड़



सरकार ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। यह ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनने जैसा है। हमें याद रखना है कि यह लक्ष्य सभी के सहयोग से ही पाया जा सकता है।

● निर्मला सीतारमण



मैं कैटरीना कैफ की तरह दिखती हूँ। इसकी वजह से मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे हमेशा कैटरीना की हमशक्ल की तरह देखा गया। इंडस्ट्री में मेरा खुद का कोई वजूद नहीं रह गया। दरअसल, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। इसलिए जब लोग कैटरीना के साथ तुलना करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी फिल्म इंडस्ट्री से शिकायत है कि यहां लोगों को टैलेंट नहीं बल्कि यारी-दोस्ती से काम मिलता है। इन सबके बावजूद मैं लगातार काम की तलाश में लगी रहती हूँ। उम्मीद है एक न एक दिन कहीं न कहीं अपने दम पर कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा।

● जरीन खान

वाक्युद्ध



कल तक मणिपुर से परहेज करने वाली कांग्रेस इस समय अपने आपको मणिपुर का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां मणिपुर की आग में राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। इसलिए कांग्रेसी सहानुभूति के लिए दिखावा बंद करें।

● संबित पात्रा

मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी डबल इंजन की भाजपा सरकार है। जिस समय मणिपुर में दंगे-फसाद शुरू हुए, अगर सरकार उसी समय इसे गंभीरता से लेती तो स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। प्रधानमंत्री ने खुद मामले की गंभीरता को नहीं समझा और जब हालात हाथ से निकल गए तो मुंह खोला।

● रणदीप सुरजेवाला



म प्र आज विकास का पर्याय बना हुआ है। इसके पीछे प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का विशेष योगदान है। इन्हीं में से एक हैं प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सुरखी विधानसभा में विकास कार्यों की कमी नहीं है। यहां सबसे कम समय में सबसे अधिक विकास कार्य किए जा रहे हैं। सड़क, बिल्डिंग, अस्पताल, स्टेडियम, पुल-पुलिया निर्माण से लेकर घर-घर पानी पहुंचाने सहित पूरी विधानसभा में विकास कार्य प्रगति पर है। वहीं मंत्री राजपूत विपक्षी कांग्रेस को घेरने का भी कोई मौका नहीं चूकते हैं। अभी हाल ही में विपक्ष ने जो इंडिया अलाइंस बनाया है, उस पर कटाक्ष करते हुए मंत्री राजपूत ने कहा कि पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने लहंगा जोड़ा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। राजपूत ने कहा कि ये पहले यूपीए की सरकार थी। तब 2जी, 3जी, 4जी जैसे अनेक घोटाले हुए। 10 वर्ष एक पांव की सरकार चली। अब एनडीए के सामने इनका मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एनडीए की सरकार बेहतर ढंग से चल रही है। आज तक इस सरकार पर कोई दाग नहीं है। विपक्ष के इस प्रकार के गठबंधनों से कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी।

गौरतलब है कि विभागीय कार्यों में दक्षता के साथ राजपूत सुरखी विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर कभी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि भाजपा की सरकार में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से क्षेत्र के विकास के लिए जो मांग की है, उसे उन्होंने सहज ही स्वीकार कर लिया। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी मांग मानते हुए सुरखी विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41 किलोमीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी सड़क की सौगात दी, जो दो विधानसभाओं को आपस में जोड़ रही है। जिसमें से अधिकांश हिस्सा सुरखी विधानसभा में आता है। वृहद पुलों का विकास पर्व के तहत भूमिपूजन हो रहा है, जिससे सुरखी विधानसभा के सैंकड़ों गांव आपस में जुड़ जाएंगे। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

मंत्री राजपूत के नेतृत्व में राजस्व विभाग कितना बेहतर काम कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मप्र के 15 जिलों के कलेक्टरों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में बेस्ट परफॉर्मर्स के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बधाई देते हुए उनके कार्यकाल में मिली इस उपलब्धि के लिए उनकी तारीफ की।



‘कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा...’

बड़े महादेव मंदिर में लगाया जाणा भव्य मेला



जैसीनगर की बड़े महादेव मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत उपस्थित रहे। धर्म सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि सभी के सहयोग से बड़े महादेव मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और सभी विद्वानों की सहमति से 24 अगस्त से 28 अगस्त तक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा भव्य आयोजन होगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रावण माह में सभी की सहमति से महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े महादेव मंदिर परिसर प्रांगण में एक विशाल मेले का आयोजन होगा। साथ ही बड़े महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस नेता दिलीप पटेल ने महादेव मंदिर में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समक्ष अपने साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। दिलीप पटेल पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजस्व विभाग के अफसरों, मैदानी अमले और राजस्व मंत्री की देखरेख में किए गए कार्यों का परिणाम है। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 15 जिले के कलेक्टरों का सम्मानित होना मप्र के राजस्व विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में बेहतर कार्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में सम्मानित होने वाले राजस्व विभाग के अफसरों को बधाई देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि मेरे द्वारा विभाग में किए गए नवाचार और अफसरों की सतत् लगनशीलता और मेहनत का परिणाम है कि हमारे प्रदेश के 15 जिलों को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है।

यही नहीं राजपूत की लोकप्रियता का आलम यह है कि गत दिनों उनके कार्यालय में सुरखी के मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित लगभग 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी लोगों को भाजपा का गमछ पहनाकर स्वागत किया एवं मिठाई खिलाई। इस अवसर पर राजपूत ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी में बिना भेदभाव सब को मान सम्मान मिलता है। यह विकास करने वाली पार्टी है, जिसका संकल्प सबका साथ सबका विकास है। अपनी जनकल्याणकारी रीति-नीतियों के कारण भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। सभी के सहयोग से सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर विकास कार्य हो रहे हैं और यह विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी। हर व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाना हमारा संकल्प है। मैं और मेरा पूरा परिवार सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं।

● कुमार राजेंद्र

मद्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति तय हो चुकी है। गत दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। इसमें विजय संकल्प यात्रा की संपरेखा तय की गई। यह यात्रा सितंबर में उज्जैन से निकल सकती है। करीब चार घंटे चली बैठक में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति समेत एक दर्जन से ज्यादा समितियों के विस्तार व उनके प्रमुखों की जिम्मेदारी तय करने का फैसला हुआ। सूत्रों का कहना है कि बैठक में टिकट वितरण के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है।

विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारों ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है। खासकर भाजपा में टिकट के दावेदारों की कतार दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। टिकट चाहने वालों में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पिछला चुनाव हारने वाले, संगठन पदाधिकारी तो हैं ही, कई सांसद भी जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकारों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सांसदों के लिए फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत इस बार उन्हीं सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा जो आकांक्षी सीटों यानी कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे।

दरअसल, प्रदेश भाजपा के 28 सांसदों में से कईयों के ऊपर सांसदी का टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सांसदों ने सुरक्षित सीट की तलाश कर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस कारण एक विधानसभा सीट पर कई-कई दावेदार हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए भाजपा के रणनीतिकारों ने टिकट वितरण का जो फॉर्मूला बनाया है, उससे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सांसदों के होश उड़ गए हैं।

मद्र में भाजपा पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने अबकी बार 200 पार के नारे के साथ चुनाव जीतने का फुल प्रूफ फॉर्मूला तैयार किया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के टिकट कटने की आशंका से घिरे भाजपा सांसदों द्वारा विधानसभा की टिकट जुगाड़ने की कोशिश के बीच केंद्रीय नेतृत्व से ऐसा संदेश मिला उससे उनके होश फाख्ता हो गए हैं। इस बार उसी सांसद को विधानसभा की टिकट मिलेगी, जो अपने लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस द्वारा जीती सीट से मैदान में उतरेगा। मतलब, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले सांसद एक तरफ कुंआ तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति में फंस गए हैं। मद्र में इस बार कई भाजपा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उसका

आकांक्षी सीटों पर लड़ना होगा चुनाव



फूंक-फूंक कदम रख रही भाजपा

भाजपा हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। पार्टी ने मिशन 2023 को लेकर छह माह पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं जिसमें हारी हुई सीटों पर फोकस किया गया। उन्हें आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया गया, उसकी जिम्मेदारी सत्ता या संगठन के एक बड़े पदाधिकारी को दी गई। क्षेत्र की हर परिस्थिति को संगठन के सामने रख रहे हैं। पिछली बार कहा चूक हुई इसकी भी जानकारी दे रहे हैं ताकि इस बार सुधार किया जा सके। भाजपा में सत्ता-संगठन ने अलग-अलग बहानों से गली-गली, घर-घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसके तहत सरकार ने जहां मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान फेज-2 के तहत प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर हर गली तक दस्तक दी, तो अब भाजपा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर माहभर का विशेष संपर्क अभियान शुरू किया है। इसमें 5 करोड़ लोगों के साथ 30 हजार विशेष परिवार और 100 विशेष प्रभावशील लोग भी फोकस पर हैं। कोशिश है कि ये 100 लोग यदि भाजपा की विचारधारा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करते हैं, तो उससे उनके दायरे के लोग भी प्रभावित होंगे।

प्रमुख कारण है इस बार टिकट कटने की संभावना। राज्य में तीन से चार बार के भाजपा सांसदों की संख्या अधिक है। लिहाजा, इस बार उन्हें फिर दोहराया जाने की संभावना कम है। इसलिए जिन पर खतरा मंडरा रहा है ऐसे सांसद विधानसभा टिकट की जुगाड़ में लग गए हैं। इन सांसदों की इच्छा भांपते ही केंद्रीय नेतृत्व ने एक फॉर्मूला दिया है। इच्छुक सांसदों को अपने लोकसभा की उन सीटों से लड़ाया जाएगा जहां कांग्रेस मजबूत है।

गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणामों की समीक्षा में 124 सीटें ऐसी थीं जिन्हें आकांक्षी की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। लेकिन 2018 से अब तक हुए 34 सीटों के उपचुनाव ने बाजी पलट दी। भाजपा को इन 34 उपचुनावों में से 21 सीटों को जीतने में कामयाबी मिली। ऐसे में 103 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें आकांक्षी सीटों की श्रेणी में रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि कुछ सांसदों को कांग्रेस की जीत वाली इन सीटों पर फोकस करने का इशारा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा में कुछ ऐसे सांसदों को भी संकेत दे दिया गया है, जो विधानसभा टिकट की लाइन में नहीं हैं। वह इससे परेशान हैं कि उन्हें पता है कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना आसान है। लोकसभा इसलिए आसान रहेगी कि 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रभावी

रहेगा। मोदी के नाम पर वोट पाकर जीतने के स्थान पर विधानसभा चुनाव की मशक्कत से वह बचना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि ऐसे सांसद स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या का कारण बताकर खुद को विधानसभा चुनाव से दूर रखने की जुगत में लग गए हैं।

भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मप्र विधानसभा चुनाव पर कोई चूक नहीं रखना चाहता। इसलिए पहले की तरह मनमानी टिकट का बंटवारा भी नहीं होगा। यदि कोई नेता किसी के टिकट की सिफारिश करेगा, तो उसे उस सीट पर जीत की गारंटी लेनी होगी। दो दशक से सत्ता में काबिज भाजपा नेतृत्व को पता है कि इस बार का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। इसलिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर शाह द्वारा हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखी जा रही है। भाजपा से निष्कासित नेताओं की वापसी के अलावा राज्य के कद्दावर नेताओं का आपसी समन्वय शाह की उसी रणनीति का हिस्सा है। इस बार विधानसभा चुनाव में केवल सांसद नहीं, भाजपा के हर जनप्रतिनिधि (महापौर, जिला पंचायत, जनपद) की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की परीक्षा ली जाएगी।

मिशन 2023 के लिए भाजपा ने 103 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जिन्हें पार्टी हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी। इनमें श्योपुर, सबलगाढ़, सुमावली, मुर्ना, दिमनी, भिंड, लहार, गोहद, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, डबरा, सेंवड़ा, करेरा, पिछोर, चाचौड़ा, राघोगढ़, चंदेरी, देवरी, बंडा, महाराजपुर, राजनगर, छतरपुर, बिजावर, पथरिया, दमोह, गुनौर, चित्रकूट, रैगांव, सतना, सिंहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम, शहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, बैहर, लांजी, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट, लखनादौन, गोटेगांव, तेंदूखेड़ा, गाडरवारा, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा, परसिया, पांडुर्णा, मुलताई, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही, उदयपुरा, विदिशा, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, भोपाल मध्य, ब्यावरा, राजगढ़,



खिलचीपुर, सुसनेर, आगर, शाजापुर, कालापपीपल, सोनकच्छ, बुरहानपुर, भीकनगांव, बड़वाह, महेश्वर, कसरावद, खरगोन, भगवानपुरा, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, अलीराजपुर, झाबुआ, थांदला, पेटलावद, सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, देपालपुर, इंदौर-1, राऊ, नागदा, तराना, घटिया, बड़नगर, सैलाना और आलोट हैं। इन सीटों पर पार्टी जितारू उम्मीदवारों की खोज कर रही है। इन्हीं सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सांसदों को टिकट मिलेगा।

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का फोकस 2018 की उन विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा है जहां बहुत कम अंतर से हार मिली थी। जिसके लिए पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है। इसी कड़ी में प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट भाजपा संगठन को सौंपी गई है। इस जमीनी फीडबैक को लेकर भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। राव का कहना है कि हारी हुई सीटों और अन्य क्षेत्रों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से हमारा कैंडर मैनेजमेंट काम कर रहा है, सभी जिलों में लोगों को तैनात कर रहे हैं। हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी जल्दी घोषित होंगे। वह कहते हैं कि कांग्रेस प्रभाव वाली सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। जहां हम मजबूत हैं और जीत के

करीब वाली सीटों की अलग-अलग प्लानिंग है। नए लोगों को भी मौका देंगे।

गौरतलब है कि उपचुनाव वाली 32 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद की स्थिति बनेगी। हालांकि पार्टी का टिकट वितरण का फॉर्मूला पूरी तरह से साफ है। पार्टी उन्हें ही टिकट देगी जो जितारू हैं। जिन सीटों पर भाजपा को बड़ी मार्जिन से जीत मिली है, पार्टी वहां किसी भी प्रकार का बदलाव करने का नहीं सोचेगी। ऐसे में ये तय माना जा सकता है कि उपचुनाव वाली 32 सीटों में से 21 सीटों पर भाजपा उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में दोबारा उतारेगी जिन्हें जीत मिली थी। बाकी बची 11 सीटों पर पार्टी को थोड़ा मंथन करना होगा। हालांकि पार्टी को भांडेर विधानसभा में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि यहां भाजपा प्रत्याशी रक्षा सनोरिया भले ही जीत गई हों लेकिन जीत का अंतर महज 161 वोटों का ही था। वहीं जिन सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था पार्टी वहां फिर उन्हें रिपीट करने पर विचार कर सकती है। इसमें रघुराज सिंह कंधाना, इमारती देवी और मनोज उटवाल के नाम शामिल हैं। ये तीनों ही कम मार्जिन से चुनाव हार थे।

● कुमार विनोद

केंद्र के काम और प्रदेश के विकास पर फोकस

चुनावी मैदान में भाजपा केंद्र सरकार के काम और प्रदेश सरकार के विकास पर फोकस कर रही है। यानी जनता को मोदी सरकार के 9 साल के काम, प्रदेश में भाजपा सरकार के विकास कार्य बताए जाएंगे। कांग्रेस की विफलता बताई जाएगी। पार्टी ने प्रदेश में 100 प्रभावशाली लोगों तक विशेष तौर पर संपर्क अभियान में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी और डॉक्टर के घर पहुंचे। फिर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले या प्रभावशील गैर-राजनीतिक लोगों के यहां भाजपा नेता पहुंचेंगे। इस बार कांग्रेस भी प्रदेश में जीत की बड़ी आस लगाए हुए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि भारत जोड़ी यात्रा के चलते पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के पहले दावा किया है कि मप्र में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी। राहुल ने यह दावा ऐसे ही नहीं किया, बल्कि उनका यह स्वयं का आंकलन है, इसमें भारत जोड़ी यात्रा के दौरान मिला फीडबैक भी शामिल है। यात्रा के दौरान राहुल ने उरो मत के नारे के साथ ऐलान किया कि वे वर्तमान सियासत से उपजे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। कर्नाटक में इसका असर दिखा अब उम्मीद मप्र से है। राहुल का दावा सच साबित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। एक-एक सीट का आंकलन किया गया है। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास है।

जबलपुर के बाद ग्वालियर-चंबल अंचल में प्रियंका गांधी की सभा से संकेत मिलते हैं कि प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी कांग्रेस का राष्ट्रीय चेहरा होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री

कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आप तो मप्र को गोद ले लें। सभा से पहले शहरभर में लगे होर्डिंग्स में राहुल गांधी कम नजर आए। प्रियंका गांधी सभा में पूर्ण सादगी के साथ पहुंचीं और आम

महिलाओं की तरह नजर आईं। उनके भाषण का हर शब्द आम जनता से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मेला ग्राउंड में सभा से संकेत मिले कि कांग्रेस कर्नाटक की तरह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाएगी। लोगों को बताएगी कि कैसे जनादेश से 2018 के चुनाव में बनी कांग्रेस सरकार को भाजपा ने गिराया। इसके साथ सस्ती बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों का कर्जा माफ, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भेजने जैसी योजनाओं का प्रलोभन देगी।

कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को कर्नाटक में भुना चुकी है। अब पार्टी मप्र के चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर पूरी ताकत लगा देगी। यह जीत कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत आधार प्रदान करेगी और विपक्षी गठजोड़ में सम्मानजनक भूमिका दिलाने का काम भी करेगी। ग्वालियर के मेला ग्राउंड की सभा में प्रियंका गांधी वाड़ा के भाषण से प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए स्पष्ट दिशा नजर आ रही थी। प्रियंका गांधी 35 मिनट के भाषण में इसी मुद्दे पर बोलीं। जनता से जुड़े मुद्दों से दाएं-बाएं जाने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हालांकि अन्य वक्ता जरूर इधर-उधर की बातों पर ताल ठोकते नजर आए।

यह तो पहले से तय है कि दिग्विजय सिंह का उपयोग कांग्रेस सार्वजनिक मंचों पर नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ही होंगे। प्रियंका गांधी की सभा में सूत्रधार दिग्विजय सिंह नजर आए। मंच पर बैठे भी, लेकिन भाषण नहीं दिया। यानी चुनाव में दिग्विजय पदों के पीछे रहेंगे। भाजपा आरोप लगाती रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ भले ही थे, किंतु सरकार पदों के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे थे। प्रदेश में ग्वालियर-चंबल अंचल को कांग्रेस अपना गढ़ मानती आ रही है। अभी तक अंचल में महल के कारण कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहता था। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से महल के प्रभाव से मुक्त हो गई है। ऐसे में अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए

प्रियंका गांधी चुनावी चेहरा



सिंधिया का नाम तक नहीं लिया

जब से सिंधिया ने पाला बदला है वे कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहे हैं। लेकिन सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने करीब 30 मिनट के भाषण के दौरान जहां मप्र सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। भाषण के दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई हमला नहीं किया। प्रियंका गांधी ने नकारात्मक राजनीति की बजाय जनता के मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और प्रियंका के पिता राजीव गांधी करीबी मित्र थे। ज्योतिरादित्य भी जब तक कांग्रेस में थे, प्रियंका के बेहद करीब थे। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद से सियासत पूरी तरह बदल गई, लेकिन प्रियंका ने इसे रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। अब सवाल यह है कि प्रियंका ने पुराने रिश्तों का मान रखा या भविष्य के संबंधों की नींव रखी।

कांग्रेस ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जिस पीजी फॉर्मूले के सहारे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, उसका इस्तेमाल मप्र में भी शुरू कर दिया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना सिंधिया के कांग्रेस पीजी फॉर्मूला से अपना गढ़ बचा पाएगी? गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के पीछे 'पीजी' फॉर्मूला का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस इसे मप्र में भी दोहराना चाह रही है। 'पी' मतलब प्रियंका गांधी और 'जी' मतलब गारंटी यानी वादे। जबलपुर के बाद ग्वालियर में भी कांग्रेस के 'पीजी' फॉर्मूले का पूरा प्रभाव दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने 6 गारंटी दी। जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना, महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट पर बिल आधा किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। कांग्रेसियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद मप्र में भी 'पीजी' फॉर्मूला काम करने लगा है।

प्रियंका गांधी 40 दिन में दूसरी बार मप्र

पहुंचीं और ग्वालियर में कांग्रेस ने अपना पूरा दम दिखाया। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ग्वालियर से अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहती है। सिंधिया राजवंश ने एक समय ग्वालियर की तत्कालीन रियासत पर शासन किया है। यहां पार्टी पर सिंधिया परिवार कांग्रेस के साथ नहीं हैं। ऐसे में संगठन के सामने उसी मजबूती से खड़े रहने की चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी 2020 के बाद इस इलाके में खास फोकस कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा, तो ये जिम्मेदारी संगठन ने ग्वालियर-चंबल इलाके के दिग्गज और अनुभवी नेता गोविंद सिंह को सौंपी। गोविंद सिंह भिंड जिले की लहार सीट से 7 बार के विधायक हैं। इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के ग्वालियर-चंबल में फोकस रखने की एक और वजह है। पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव हों या 2020 का उपचुनाव या फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, इन सभी फॉर्मेट के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर-चंबल के 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 7 और बसपा को 1 सीट मिली थी।

● अरविंद नारद

म प्र के विधानसभा चुनाव 2023 जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे यहां की सियासत गरमा रही है। इसी साल दिसंबर में वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

इससे पहले ही मप्र में चुनाव होने संभव हैं। इन चुनावों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से सत्ता

छोटे दलों की बड़ी भूमिका

छीनने वाली भाजपा की मप्र में इस बार भी बुरी तरह हार होगी। इस कयास को भाजपा के कुछ नेताओं के कांग्रेस में जाने से और हवा मिली है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस की ओर से जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। दोनों ही दल एक-दूसरे को घेरने में लगे हैं तथा दोनों ही दलों की नजर आदिवासी, दलित और पिछड़े वोटों पर है। वहीं, दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय छोटे दल और दूसरे राज्यों के प्रमुख दल भी इस चुनाव में समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में हैं।

मप्र में जहां आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से ज्यादातर सीटों पर मैदान में उतरने का मन बना रही है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस), स्थानीय दलों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस), भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) आदि भी इस बार के चुनावों में दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के वोटों में संध लगाएंगे। राजनीतिक लोग मान रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सरकार बनाने में छोटे-छोटे दलों की बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह की चुनावी तैयारी की है, उससे उसे बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। दोनों दलों के कुछ समर्थक दल हैं ही, जो पहले भी समर्थन में रहे हैं, उनको छोड़ दें, तो बाकी दलों की मदद कांग्रेस को शायद ही पड़े। पर यह तय है कि भाजपा मौका मिलने पर हर तरह के गठबंधन से लेकर दूसरे दलों के विधायकों को अपने साथ लाकर सरकार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।

भाजपा नेताओं ने भी मप्र में आवाजाही शुरू कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्रदेश का दौरा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री 27 जून भोपाल पहुंचे। वहां उन्होंने दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उनका यह दौरा पूरी तरह चुनावी रहा। उसके बाद 1 जुलाई को शहडोल पहुंचे। माना जा रहा है कि भाजपा को इस बार दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अलावा सवर्णों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए यह एक मौका है कि वह अच्छा प्रदर्शन करे और कर्नाटक



शिवराज सरकार का विरोध

हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली भाजपा की शिवराज सरकार ने महाकालेश्वर कॉरिडोर में लगाई मूर्तियों से ही साबित कर दिया कि वह कितनी हिंदू हितैषी हैं। बागेश्वर धाम के जरिए हिंदुओं को साधने के प्रयास में लगी शिवराज सरकार महाकालेश्वर कॉरिडोर मामले में बैकफुट पर आ गई है। इसके अलावा शिवराज सरकार और कई मुद्दों पर लोगों का विरोध झेल रही है। केवल शिवराज सरकार के इस कार्यकाल में ही उसका खूब विरोध हुआ है। आदिवासियों ने अपनी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को तेज किया है, क्योंकि प्रदेश में आदिवासियों से इन प्राकृतिक संसाधनों को छीनने के लिए शिवराज सरकार ने कई पैतरे चले हैं। इसी साल जनवरी में करणी सेना भी शिवराज सरकार का विरोध कर चुकी है। करणी सेना के इस विरोध प्रदर्शन में 2,00,000 से अधिक सवर्णों ने भाग लिया। इसी साल फरवरी में मप्र की राजधानी भोपाल में भीम आर्मी शक्ति प्रदर्शन करके शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल चुकी है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जन्म स्थान महु (इंदौर) में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें दलितों, आदिवासियों व पिछड़ी जातियों ने भागीदारी की। इस आयोजन में शिवराज सरकार में दलितों, आदिवासियों हो रहे अत्याचारों को लेकर विरोध दर्ज हुआ।

व हिमाचल प्रदेश की तरह भाजपा के खिसकते वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश करे। फिलहाल मप्र के चुनावी मौसम को समझने के लिए कुछ बातों को समझना होगा। मप्र में जीतने के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश में सभी दल लगे हैं। भाजपा इसे लेकर अपना पुराना हिंदुत्व कार्ड खेलेगी, जिसके लिए वह मप्र के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का इस्तेमाल कर सकती है। इस बार के चुनाव में यही एक पैतरा है, जिसके दम पर भाजपा को लग रहा है कि वह हिंदुओं के ज्यादातर वोटों को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से साध

लेगी। वहीं कांग्रेस इससे हटकर लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और शिवराज सरकार के घोटालों जैसी समस्याओं को उठा रही है। कांग्रेस ने मप्र चुनाव 2023 की तैयारी भाजपा के खिलाफ उसके घोटालों को लेकर मोर्चा खोलकर की है। पिछले चुनावों से ज्यादा सक्रिय दिख रही कांग्रेस के कई बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रचार के लिए जबलपुर में एक रैली की। यह कांग्रेस की पहली बड़ी शुरुआत रही। प्रियंका गांधी ने इस रैली में शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और नौकरियों न दे पाने के आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के 220 महीनों के शासन में ही 225 घोटाले हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है, लेकिन हम भी जोर-शोर से मैदान में हैं। बता दें कि कांग्रेस ने शिवराज सरकार के करीब 400 कथित घोटालों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें छपवाकर कांग्रेस नेता लोगों में बांटेंगे। इसी बीच एक और घोटाले का आरोप शिवराज सरकार पर लगा है। कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार में अब दिव्यांग भर्ती घोटाला हुआ है। आरोप है कि 77 लोगों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है।

गौरतलब है कि मप्र में दो ही दल कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य रूप से जीतते रहे हैं। यहां 2013 में जहां भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा के 15 साल के शासन को ध्वस्त करके सरकार बनाई। पर 109 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 15 महीने के भीतर ही कांग्रेस की कमजोर कड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को तोड़कर करीब डेढ़ साल बाद ही अपनी सरकार बना ली। अब एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो सकती है।

● सुनील सिंह

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में शिकायतों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का सिलसिला तेज हो गया है।

इसके बाद भी अभी 1500 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। इनमें सबसे पुराने प्रकरण 2008 के हैं, यानी 13 साल बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां एक ओर ईओडब्ल्यू में शिकायतों की भरमार है, वहीं जांच में देरी की बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसी के पास स्वीकृत हमले में से 60 प्रतिशत की कमी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना संक्रमणकाल में लॉकडाउन की वजह से भी कार्य प्रभावित हुआ है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि जांचों की संख्या बढ़ी है।

गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू में शिकायतों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है। पिछले वर्षों में प्राथमिकी का आंकड़ा औसतन 50 से 60 के बीच रहता था। 2021 में 91 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 2022 में यह संख्या 110 तक पहुंच गई थी। जांच एजेंसी के पास हर वर्ष पांच से सात हजार शिकायतें पहुंचती हैं। शिकायतों का परीक्षण (स्कूटनी) किया जाता है। इनमें अधिकतम 10 प्रतिशत पर ही जांच शुरू हो पाती है। साक्ष्य के अभाव में या फिर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित नहीं होने से बाकी शिकायतों पर ईओडब्ल्यू जांच करने की जगह संबंधित विभाग को भेज देता है। इस वर्ष 400 शिकायतों पर जांच शुरू हो चुकी है।

आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने वाली मप्र सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी ईओडब्ल्यू के पास जांच के लिए अफसरों की भारी कमी है। ईओडब्ल्यू से अफसरों के तबादले तो किए गए, लेकिन उनके बदले में नए पदस्थ नहीं किए गए। भोपाल-इंदौर सहित तकरीबन सभी रैंज के दफ्तरों में जांच के लिए अफसर नहीं हैं। खूब प्रयास किए गए, तब कुछ डीएसपी तो मिल गए, लेकिन निरीक्षक स्तर के अफसर अभी भी नहीं मिले हैं। यह स्थिति तब है, जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईओडब्ल्यू में अफसरों की तैनाती के आदेश दे चुके हैं। ईओडब्ल्यू में डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी काफी लंबे समय से पदस्थ थे। लिहाजा गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर डीएसपी स्तर के अफसरों को हटा दिया था। बाद में इसी दलील के साथ पीएचक्यू ने निरीक्षक स्तर के अफसरों को ईओडब्ल्यू से वापस बुला लिया था। स्थिति यह हो गई कि अफसरों के ठिकानों पर बड़े आर्थिक घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी के पास पड़ताल करने के लिए अफसर नहीं बचे। सामान्य तौर पर होता यह है कि अगर किसी दफ्तर से अफसर हटाए जाते हैं, तो उस जगह पर नए अफसरों की तैनाती भी कर दी जाती है। ईओडब्ल्यू इस मामले में अपवाद है। ऐसा



ईओडब्ल्यू में जांच के लिए नहीं स्टाफ

अक्टूबर में तबादले के बाद नहीं मिले आईओ

एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है। हालांकि, यह अपने स्तर पर काम करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह वर्तमान में केवल आधे कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। इसके पास कई मामले लंबित हैं, जबकि नई-नई शिकायतें भी आती रहती हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण अधिकारी इन पर गौर करने में असहाय हैं। दरअसल, अक्टूबर 2022 में, जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में काम करने वाले 25 इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारियों को ईओडब्ल्यू से स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से ये पद खाली पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार, विभाग में 130 आईओ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन लगभग 80 आईओ काम कर रहे थे। इनमें से 25 आईओ के तबादले के बाद एजेंसी आधे स्टाफ से भी काम नहीं चला रही है। इस कारण मामलों की जांच रुकी हुई है और अधिकारियों की कमी के कारण एजेंसी की तलाशी या छापेमारी नहीं की जा रही है।

इसलिए कि ईओडब्ल्यू से अफसरों को हटाए हुए तकरीबन आठ महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और उनकी जगह पर तैनाती नहीं की गई।

विभागीय अफसरों की मानें तो अफसरों की कमी का असर यह है कि सितंबर 2022 के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से भ्रष्टों पर एक भी छाप नहीं मारा गया है। सूत्रों की माने तो ईओडब्ल्यू के अफसरों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक से चर्चा की थी। डीएसपी स्तर के अफसरों की तैनाती गृह विभाग से होती है। डीएसपी स्तर के अफसर के तबादले की फाइल गृहमंत्री से होते हुए मुख्यमंत्री तक जाती है। पत्राचार और मेल-मुलाकातों के बाद शासन ने डीएसपी स्तर के कुछ अफसरों की

तैनाती तो कर दी, लेकिन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों की जांच एजेंसी को अभी भी दरकार है। ईओडब्ल्यू में निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों की भारी कमी है। अफसरों की कमी का असर यह है कि सितंबर 2022 के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से भ्रष्टों पर एक भी छाप नहीं मारा गया है। ऐसा इसलिए कि ज्यादातर मामलों की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों के पास रहती है। भोपाल और इंदौर के ईओडब्ल्यू दफ्तर अफसरों की कमी से खासे प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर सागर दफ्तर में है। सागर के ईओडब्ल्यू दफ्तर में एक महिला इंस्पेक्टर और एक महिला सब इंस्पेक्टर हैं। उनके अलावा डीएसपी स्तर के अफसर भी तैनात नहीं हैं। अफसरों की कमी की वजह से पूरे प्रदेश में जांच प्रभावित हो रही है और शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है। ईओडब्ल्यू में पदस्थ अधिकारियों को जब हटाया गया था, तो विकल्प के तौर पर अफसरों की नई तैनाती नहीं की गई। यह बात सही है कि जिन अफसरों को हटाया गया है, वे लंबे समय से ईओडब्ल्यू में पदस्थ थे। बहरहाल गृह विभाग और पीएचक्यू की जिम्मेदारी यह भी है कि अगर किसी अधिकारी को वहां से हटाया जा रहा है, तो विकल्प भी देना था।

ईओडब्ल्यू में अफसरों की नई पदस्थापना करने के लिए डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के कुछ अफसरों के नाम भी भेजे गए हैं, लेकिन उनके आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। दो दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों की जांच लंबित प्रदेश में ईओडब्ल्यू के पास अभी देश के सबसे चर्चित ई-टेंडर घोटाले से लेकर कन्यादान घोटाला, प्याज घोटाला, राशन घोटाला, जबलपुर के पूर्व बिशप पीसी सिंह, जबलपुर आरटीओ संतोष पाल की अनुपातहीन संपत्ति का मामला, महिला बाल विकास विभाग का आयुषन प्रेम घोटाला, बालाघाट के बिजली कंपनी के सहायक यंत्री दयाशंकर प्रजापति की अनुपातहीन संपत्ति का मामला, भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी के घर भारी मात्रा में मिली नगदी सहित दो दर्जन गंभीर मामलों की जांच है।

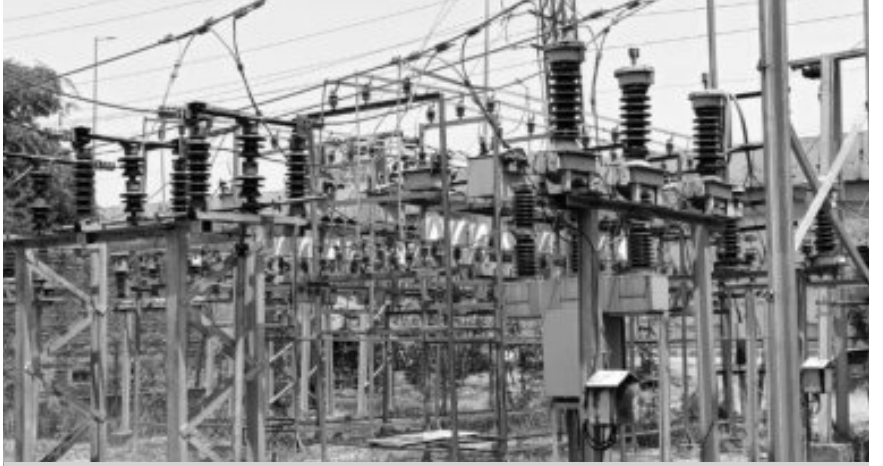
● प्रवीण सक्सेना

म प्र बिजली के मामले में बीते 19 सालों में तेजी से आगे बढ़ा और आत्मनिर्भर बना है। प्रदेश लालटेन युग से निकलकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। वर्तमान में बिजली का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है। मप्र दिल्ली मेट्रो तक को बिजली बेच रहा है। बिजली भरपूर मिलने से मप्र की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर चार गुना हो गई। औद्योगिक विकास दर भी 23 फीसदी तक बीते दो दशकों में बढ़ी है। यही कारण है कि केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जनवरी महीने में पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी थी। बधाई की सबसे बड़ी वजह यह थी कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से लाइनलॉस कम हुआ है। पहले जहां 41.47 प्रतिशत लाइनलॉस होता था, वह जनवरी में 20 फीसदी हो गया था। वर्तमान में लाइनलॉस 17 प्रतिशत हो गया है।

दरअसल, मप्र सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रदेश का ऊर्जा विभाग बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। बिजली संग्रहण के लिए जहां कैपेसिटर बैंक बनाया जा रहा है, वहीं फीडर सेप्रेसन पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए रिंग-विंग फेंसिंग योजना बनाई जा रही है। इससे लाइनलॉस और कम होगा। इस योजना के तहत विद्युत प्रदाय योजना को मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा। अभी उपभोक्ता के पास एक तार से बिजली सप्लाई हो रही है, अगर तार में विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तो उपभोक्ता के घर अंधेरा छा जाता है। इसलिए अब उपभोक्ता को बिजली मुहैया कराने के लिए दो जगह से सप्लाई होगी। इससे अगर एक तार की बिजली कट भी जाती है तो दूसरे तार से उपभोक्ता को बिजली मिलती रहेगी।

मप्र की इस विद्युत वितरण व्यवस्था से उद्योगों को सबसे अधिक फायदा होगा। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि अगर बिजली गुल होती है तो कई प्रकार के उद्योग ऐसे हैं, जिससे उनका काम पूरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए नई व्यवस्था के तहत अगर किसी उद्योग को दी जा रही विद्युत सप्लाई की एक लाइन बंद होती है तो दूसरे से उसको बिजली मिलती रहेगी। जानकारी के अनुसार मप्र की इस विद्युत वितरण व्यवस्था का 10-11 जुलाई को अधिकारियों ने नई दिल्ली में प्रेजेंटेशन दिया था। इस अवसर पर कई राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। मप्र की इस विद्युत वितरण व्यवस्था को सभी राज्यों के अधिकारियों ने सराहा। बताया जाता है कि दिल्ली में प्रेजेंटेशन के बाद मप्र की इस व्यवस्था को देखने के लिए अभी तक 17 राज्यों के अधिकारी-कर्मचारी मप्र का दौरा कर चुके हैं और इस व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। अधिकारियों की मानें तो आने वाले समय में मप्र

रिंग-विंग फेंसिंग से रुकेगा लाइनलॉस



सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास से बिजली बना रहा मप्र

मप्र में बिजली उत्पादन और आपूर्ति के मामले में भाजपा की शिवराज सरकार ने अनुकरणीय पहल की है। सरकार के सतत प्रयासों से मप्र दो दशकों में आज बिजली दूसरे प्रदेशों को बेच रहा है। यह स्थिति बीते 10 सालों से है। प्रदेश में 365 दिन बिजली सरप्लस होती है। वर्तमान में 17 हजार 170 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन इकाईयां ही करीब 6 हजार मेगावाट का उत्पादन कर रही हैं। मप्र में बिजली उत्पादन केवल बड़े प्लांटों से ही नहीं हो रहा, बल्कि शिवराज सिंह सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा है कि प्रदेश में 2840 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से तैयार हो रही है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा से भी इतनी ही बिजली मिल रही है। लघु जल विद्युत ऊर्जा सहित बायोमास ऊर्जा से भी ढाई सौ मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। मप्र में प्रदेश में 17,170 मेगावाट मांग आपूर्ति है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1280 यूनिट है। प्रदेश में 5943 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं। इनमें सौर ऊर्जा 2840 मेगावाट, पवन ऊर्जा 2844 मेगावाट, लघु जल विद्युत ऊर्जा 124 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा 135 मेगावाट है। इससे प्रदेश में 112 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। अनुमानतः प्रदेश साल 2030 तक 20 हजार मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

विद्युत उत्पादन के साथ ही विद्युत वितरण व्यवस्था में भी अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा।

उधर, भोपाल के घरों, दफ्तरों, दुकानों में जल्द ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। बिजली चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कवायद की जा रही है। इन मीटरों के लगने के बाद उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करवाकर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें बिजली चोरी के साथ ही मीटर रीडिंग का भी झंझट नहीं होगा। केंद्र सरकार की रिवेण्ड रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (आरआरडीएस) के तहत यह काम होगा। अभी बिजली कंपनी की तकनीकी टीम द्वारा इसके लिए मोबाइल एप बनाया जा रहा है। इसके अलावा पेमेंट के इंटीग्रेशन को लेकर तैयारी चल रही है। केंद्र द्वारा 2025 तक देशभर में ऐसे मीटर लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने बजट में भी इसका प्रावधान किया है। मीटर मौजूदा बिजली मीटर तथा

डिजिटल मीटर्स की जगह लगाए जाएंगे। इनमें प्री-पेमेंट बिजली भुगतान का विकल्प भी रहेगा। इसके तहत पहले बिजली का भुगतान करना होगा, उसके बाद बिजली दी जाएगी। नए स्मार्ट मीटर लगाए जाने के लिए पुराने स्मार्ट मीटर को उखाड़ा जाएगा। इनके स्थान पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगेंगे। इसको लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि प्री-पेड मीटर लगाए जाने के बाद पुराने स्मार्ट मीटर को उखाड़कर सुरक्षित रखा जाएगा। इन मीटरों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मीटर लगाए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे उखाड़े गए स्मार्ट मीटर का उपयोग हो जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत प्रदेशभर में प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत राजधानी में भी प्री-पेड मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

● राजेश बोरकर

6

कर्नाटक चुनाव के परिणाम बताते हैं कि वहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने में ओबीसी के तीन बड़े समुदाय लिंगायत, कुसबा और वोक्कालिगा का अहम रोल था। कांग्रेस अब मद्र में कर्नाटक के फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी में है। मद्र में कांग्रेस का दलित, आदिवासी वोट बैंक मजबूत रहा है। यहां अड़यन हमेशा से ओबीसी वोटर है, क्योंकि यह वर्ग भाजपा के साथ खड़ा रहता है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश की बागडोर सभाल चुके उमा भारती, बाबूलाल गौर और अब शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। ओबीसी वोटर को अपने पाले में करने के लिए खास रणनीति के तहत अब कमलनाथ लोधी सहित अन्य समाजों पर फोकस बढ़ा रहे हैं।

जातीय गणना पर राजनीति



देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दरअसल, इस बार मद्र में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले बिहार सरकार भी इस तरह का सेंसस करा रही थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी।

पिछले कुछ समय में जातीय जनगणना राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इसको तक्ज्जो दी गई थी। इस बीच में हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर मद्र में क्या हुआ है? राज्य में कास्ट सेंसस की घोषणा की वजह क्या है? जातिगत जनगणना को लेकर अलग-अलग राज्यों में क्या हुआ है। कब किसने जनगणना कराई, उसके नतीजे क्या रहे? बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है उसका क्या स्टेटस है? राज्य सरकारों को जनगणना को लेकर क्या अधिकार है? जातिगत जनगणना के पीछे की राजनीति क्या है?

भोपाल के रविंद्र भवन में मद्र पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मद्र में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 प्रतिशत है, भाजपा सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रही कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने

पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि हमारे समाज में गरीब व्यक्ति कितने हैं। उनकी क्या सहायता की जा सकती है। ताकि पिछड़े वर्ग की जातियों को वास्तविक संख्या का पता चल सके। उन्होंने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान कराने के लिए नियम बनाए जाएंगे और ओबीसी वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा।

मद्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। दरअसल, प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। जिसका 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख दल ओबीसी वर्ग का खुद को हितैषी बता रहे हैं। इसके पहले 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने पर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराया गया था। हालांकि, बाद में इस बड़े हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

1951 के बाद से हर जनगणना में जाति सर्वे की मांग उठती रही है। कई राज्यों ने जाति सर्वे या जनगणना का प्रयास भी किया, लेकिन अधिकांश असफल रहे। 2011 में ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) को अंजाम देने की योजना बनाई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य किया

जाति जनगणना बना मुद्दा

कर्नाटक के बाद अब मद्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जाति जनगणना को मुद्दा बना लिया है। मद्र में पिछले चार साल से ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फायदा देने की हिमायती बनकर कांग्रेस-भाजपा श्रेय लेना चाहती हैं। इसकी वजह है कि प्रदेश में आधी आबादी (49 फीसदी) ओबीसी वर्ग की ही है। जब 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया था, तभी भाजपा सतर्क हो गई थी। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में इसका असर देखने को भी मिला था। अब पहली बार है कि विधानसभा चुनाव में दलित-आदिवासी से ज्यादा फोकस पिछड़ों पर होगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने तय रणनीति के तहत ओबीसी वोटर्स की संधमारी की है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं बताने का मुद्दा ओबीसी के अपमान से जोड़कर उठाया। उधर, भाजपा ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की टिप्पणी को ओबीसी का अपमान बताकर कांग्रेस को घेरा, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इसलिए अब कांग्रेस ने मद्र में भी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर बाजी मारने की कोशिश की है।

और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में इसका संचालन किया। जाति संरचना के बिना एसईसीसी डेटा 2016 में दो मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित किया गया था। जाति डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया था, जिसने डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। हालांकि, अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार के तहत कर्नाटक ने एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तब सर्वेक्षण का उद्देश्य यह बताया गया कि यह सर्वे 127वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, ओबीसी के आनुपातिक आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए किया गया था।

रिपोर्टों के अनुसार, यह सर्वे 2015 में अप्रैल और मई के दौरान 1.6 लाख गणनाकारों के साथ किया गया था। एच कंधाराज की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित इस सर्वे में लगभग 1.3 करोड़ घरों को कवर किया गया। रिपोर्ट जून 2016 तक प्रस्तुत की जानी थी। हालांकि, रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। 2021 में, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पिछड़े वर्गों (बीसी) के बीच जाति संरचना के सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। प्राथमिक योजना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एससीआई), सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएसएस), ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और सेंटर फॉर गुड गवर्नंस जैसी कई विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करने की थी। हालांकि, इस प्रक्रिया का क्या हुआ, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया।

ओडिशा ने भी हाल ही में पिछड़ी जाति समुदायों की शैक्षिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए 1 मई से अपना जाति-आधारित सर्वे शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वे में आजीविका और बुनियादी ढांचे तक पहुंच से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। यह प्रक्रिया 27 मई को पूरी हुई। राज्य कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरकार की मानें तो यह केवल पिछड़ी जाति समुदायों के लिए आनुपातिक योजनाओं और कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है।

बिहार सरकार ने दो चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करने का ऐलान किया था। पहला फेज जनवरी में पूरा हो गया था। फिर 15 अप्रैल से दूसरे फेज की शुरुआत हुई, जिसे 15 मई तक पूरा होना था। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती की गई। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक जनगणना का काम शुरू हुआ। इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी (प्राइवेट, सरकारी, गजटेड, नॉन-गजटेड आदि), गाड़ी



जातिगत जनगणना से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, बल्कि एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। यदि कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी तो भाजपा कमजोर नजर आएगी, भले ही भाजपा का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने पर कहा गया था कि आदिवासी वोटबैंक को साधने के लिए यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा है। इस मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पकड़ा था। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था। बाद में विधानसभा ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी भी दे दी थी। मामला आगे बढ़ता, उससे पहले ही मप्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने स्टे दे दिया। तब से ही मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ओबीसी समुदाय को राज्य में अभी 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। अब दोनों ही दल चाहते हैं कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27 प्रतिशत हो जाए, लेकिन श्रेय खुद लेना चाहते हैं। ओबीसी वर्ग का साथ किसको मिलेगा? यह विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर पता चलेगा।

(कैटेगरी), मोबाइल, किस काम में दक्षता है, आय के अन्य साधन, परिवार में कितने कमाने वाले सदस्य हैं, एक व्यक्ति पर कितने आश्रित हैं, मूल जाति, उप जाति, उप की उपजाति, गांव में जातियों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सवाल पूछे गए। दूसरा चरण 15 मई तक चलना था। जिस पर चार मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 21 जुलाई को कोर्ट ने कहा, पटना उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बिहार सरकार की जातीय जनगणना पर रोक लगाते वक्त पटना हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि राज्य के पास जाति-आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा कि जिस तरह से यह अब चलन में है, जो जनगणना की तरह होगा, इस प्रकार संसद की विधायी शक्ति का उल्लंघन होगा। वहीं, कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय है कि चूंकि जनगणना प्रक्रिया संघ सूची के अंतर्गत

आती है, इसलिए राज्यों को इसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। वे केवल जनसंख्या के आंकड़े या डेटा एकत्र कर सकते हैं।

बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी यह मांग तेज हो चली है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर दांव चला है। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के समय एकत्रित किए गए जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग रख दी। कांग्रेस पार्टी ने जितनी आबादी, उतना हक, नारा दे दिया है। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की बात करें तो जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी पार्टी इसी बहाने विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि वह अपने इस दांव से सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को साध सकती है। गौरतलब है कि सपा, बसपा, राजद, जदयू, डीएमके समेत कई दल इसके समर्थन में हैं। नीतीश ने कांग्रेस को विपक्ष का सर्वसम्मत मुद्दा ढूंढने की सलाह दी थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा था।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। महंगे किराए के कारण यात्रियों ने इस ट्रेन से दूरी बना रखी है। इस ट्रेन में 76.32 प्रतिशत सीटें खाली रहीं। एक माह में इंदौर से भोपाल के बीच 26 दिन चली वंदे भारत ट्रेन में 3262 यात्रियों ने ही सफर किया। इसमें एसी चेर कार श्रेणी (सीसी) में 3037 और एकजीक्यूटिव चेर कार श्रेणी (ईसी) में 225 यात्रियों रवाना हुए। वंदे भारत में दोनों श्रेणी में 530 सीटें हैं। इसके अनुसार 13780 यात्रियों को सफर करना था। भोपाल से भी करीब 3400 यात्री इंदौर के लिए रवाना हुए। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की कमी को देखते हुए सभी रेलवे जोन को किराया कम करने का निर्णय करने के अधिकार दिए हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन के किराए की समीक्षा की जा रही है। संभावना है कि जल्द ही किराए में कमी आ सकती है। 20 से 25 प्रतिशत किराए में कटौती हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से इंदौर-भोपाल वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था। 28 जून से इंदौर से नियमित ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। ट्रेन को शुरुआत से ही यात्रियों का टोटा है। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन से यात्रियों की दूरी महंगे किराए के कारण है। इंदौर से भोपाल के बीच सीसी श्रेणी में 810 रुपए और ईसी श्रेणी में 1510 रुपए किराया है। इसमें नाश्ता भी शामिल है। भोपाल से इंदौर में खाने के साथ किराया सीसी में 910 और ईसी में 1610 रुपए है। इंदौर से वंदे भारत सुबह 6.30 बजे और पांच मिनट बाद 6.35 बजे इंटरसिटी रवाना होती है। इंटरसिटी में सीसी का किराया 365 और सामान्य में 100 रुपए किराया है। इंदौर-भोपाल के बीच वंदे भारत चलते हुए एक महीना पूरा हो गया है। इस दौरान यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 30 प्रतिशत भी नहीं भर पा रही है। अत्यधिक किराए के कारण इसे यात्रियों ने नकार दिया है। फिलहाल ट्रेन का किराया घटने को लेकर असमंजस बरकरार है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आगामी दिनों में इसका विस्तार और किसी स्टेशन तक होगा या नहीं?

कभी ट्रेन के ग्वालियर तक विस्तार की बात सामने आती है, तो कभी नागपुर तक। पिछले दिनों इंदौर आए रेलवे बोर्ड के चेरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, बैठक में उन्होंने वंदे भारत का समय कम करने और उसके ग्वालियर तक विस्तार की चर्चा जरूर की थी, लेकिन उनसे जब पत्रकारों ने ट्रेन का किराया घटाने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कोई

महंगाई की चपेट में वंदे भारत ट्रेन



बस सुविधा भी चैलेंजर

इंदौर और भोपाल के बीच 100 से ज्यादा बसें रोज चलती हैं। इनका किराया भी लगभग आधा है। एआईसीटीएस की सुविधायुक्त एसी बसें साढ़े तीन घंटे में भोपाल पहुंचा देती हैं। वह भी 435 रुपए में। यानी इसका किराया भी वंदे भारत से कम है। यह बसें आधे-आधे घंटे के अंतर से उपलब्ध हैं। स्टॉपेज भी एक ही होता है, जहां नाश्ता किया जा सकता है। इसके अलावा इंदौर और भोपाल में इन बसों में बैठने के लिए कई साधन और पिकअप पॉइंट्स उपलब्ध हैं। साधारण बसों की बात करें तो हर दस मिनट में बसें चलती हैं। इतना ही नहीं, इंदौर-भोपाल के बीच चलने वाली टैक्सी भी यात्रियों के बीच खासी लोकप्रिय है। इंदौर से भोपाल के लिए चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की क्षमता 530 यात्रियों की है। एकजीक्यूटिव श्रेणी के कोच में 52 की क्षमता है। रेलवे से जुड़े जानकारों का मानना है कि ज्यादा किराया और कम स्टॉपेज के कारण इस ट्रेन में यात्रियों को बिठा पाना थोड़ा टेढ़ी खीर ही साबित होगा। दरअसल, इंदौर से भोपाल आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 6.35 बजे निकलती है। उसका किराया 100 रुपए है। वह उज्जैन के अलावा मक्सी, शुजालपुर, सीहोर व अन्य स्टेशनों पर भी स्टॉपेज लेती है। जबकि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ उज्जैन में रुकेगी। कई यात्री सीहोर में भी उतरते हैं। यदि वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाते हैं तो इस ट्रेन को ज्यादा यात्री मिल सकते हैं। इसके अलावा किराया भी कम करना होगा। किराए को लेकर रेलवे के रतलाम मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित टाकुर कहते हैं कि ट्रेन में कई अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। उसके हिसाब से किराया तय किया गया है। ट्रेन में ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिलेगा। वह भी किराए में शामिल है।

संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सूत्रों की मानें तो रेलवे बोर्ड ने किराया 25 प्रतिशत तक घटाने के अधिकार संबंधित जोन को सौंपे हैं, लेकिन इसके लिए एक महीने की रिपोर्ट का इंतजार करना था। इंदौर वंदे भारत ने अभी एक महीना पूरा किया है, इसलिए अगस्त में किराए को लेकर कोई फैसला हो सकता है।

जहां इंदौर-भोपाल इंटरसिटी की एसी चेरकार का किराया 365 रुपए है, वहीं इंदौर-भोपाल वंदे भारत की एसी चेरकार का किराया 810 और एकजीक्यूटिव चेरकार का किराया

1510 रुपए है। वापसी में यानी भोपाल से इंदौर आते समय यह और भी बढ़ जाता है। दोनों श्रेणियों में बुकिंग के लिए यात्रियों को क्रमशः 910 और 1600 रुपए चुकाने पड़ते हैं। हालांकि, इंदौर से जाते समय ट्रेन में नाश्ता और भोपाल से इंदौर आते समय रात का खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी शुल्क अत्यधिक है। इंदौर-भोपाल रूट पर चलने वाली चार्टर्ड वॉल्वो बस 435 रुपए में इंदौर से भोपाल पहुंचाती है। रेलवे इस प्रतियोगिता से भी निपट नहीं पा रहा है।

● जितेंद्र तिवारी

सूचना आयोग में आयुक्त के 8 पद खाली हैं। आयुक्त की कमी के कारण अपील के लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। आमजन के पास सूचना पाने का सशक्त हथियार है सूचना का अधिकार। नौकरशाहों और सरकार के लिए यह परेशानी भी है। ऐसे में जानकारी देने के बजाय अफसरों का प्रयास जानकारी छुपाने में ज्यादा रहा है। हालांकि इसमें उन्हें कामयाबी कम ही मिल पाती है। दूसरी ओर आयोग में काम का बोझ लगातार बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी आना है।

गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग में 10 आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त का सेटअप है। मौजूदा स्थिति में राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या घटते-घटते दो रह गई है। एक सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडेय का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। आयोग में एक साल से आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नवंबर 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। 121 दावेदारों ने आवेदन किए। इनमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, कई रिटायर्ड जज से लेकर पत्रकार भी शामिल हैं। आयोग में पिछले एक साल में चार आयुक्तों के पद खाली हुए हैं। इनमें रिटायर आईएएस डीपी अहिरवार, राजकुमार माथुर, रिटायर आईपीएस सुरेंद्र सिंह, रिटायर आईएएस गोल्ला कृष्णमूर्ति शामिल हैं। इन सभी सूचना आयुक्तों का कार्यकाल वर्ष 2021 में पूरा हुआ। अरुण कुमार पांडेय का कार्यकाल बीते 20 जुलाई को पूरा हो गया। सूचना आयुक्तों में संभाग स्तर पर कामकाज की जिम्मेदारी की व्यवस्था है। अब सिर्फ दो आयुक्त विजय मनोहर तिवारी और राहुल सिंह ही कार्यरत हैं।

मप्र राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा आयुक्तों के 10 पद हैं, जिनमें से 8 खाली हैं। डेढ़ साल से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नवंबर 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए थे। 121 दावेदारों ने आवेदन किए। इनमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, कई रिटायर्ड जज से लेकर पत्रकार भी शामिल हैं। लेकिन आवेदन जमा होने के पूरे डेढ़ साल बाद भी कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से जीएडी के अधीन है। इसमें आयोग का कोई दखल नहीं है। भारत में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिलाने की सबसे पहली पहल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में इसके लिए कानून बनाए जाने से भी 30 साल पहले की गई थी। तब वर्ष 1976

सूचना आयुक्त के 8 पद खाली



सूचना छुपाने में मप्र दूसरे नंबर पर

गौरतलब है कि सूचना के अधिकार के तहत जनहित से जुड़ी जानकारियां देने में जानबूझकर लापरवाही के मामले में मप्र के अफसर कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बीते एक साल में आरटीआई एक्ट के उल्लंघन पर मप्र के 222 अफसरों पर 47.50 लाख रुपए की पेनाल्टी राज्य सूचना आयोग ने लगाई है। पेनाल्टी की यह राशि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच की है। यह राशि कर्नाटक के बाद सर्वाधिक है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मप्र में आरटीआई में जानकारी नहीं दिए जाने की 9005 शिकायतें और अपीलों का निराकरण किया गया है। वहीं इस अवधि में 8413 नई सेकंड अपीलें भी दायर हुई हैं। वर्तमान में आरटीआई की 5929 सेकंड अपीलें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। सतर्क नागरिक संगठन के मुताबिक मप्र में अपीलों के निराकरण की रफ्तार को देखा जाए, तो मौजूदा अपीलों के निपटारे में अभी 8 महीने का वक्त लगेगा। नई अपीलों की सुनवाई का नंबर इनके बाद ही आ सकेगा। अफसरों पर पेनाल्टी लगाने के मामले में कर्नाटक देशभर में अग्रणी है। कर्नाटक ने 1265 अफसरों पर 1.04 करोड़ की पेनाल्टी एक साल में लगाई है। हरियाणा 161 अफसरों पर 38.81 लाख के साथ मप्र के बाद तीसरे स्थान पर है।

में राजनारायण बनाम उप्र सरकार मामले में न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि लोग तब तक कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वे जानेंगे नहीं। इसी कारण सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। इसी प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, लोग मालिक हैं, इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें, जो उनकी सेवा के लिए हैं, क्या कर रही हैं? न्यायालय का तर्क था कि प्रत्येक नागरिक करदाता है। नागरिकों के पास यह जानने का अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार खर्च हो रहा है। मप्र में शिवराज सिंह

चौहान सरकार द्वारा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बावजूद सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बड़ी मेहनत से दबाई गई सड़ांध को सामने लाती रही। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर के युवा अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि उनके पास भी कई बार ऐसे प्रकरण विधिक सलाह के लिए आए हैं, जिनसे लगता है कि सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, उसकी भावनाओं के साथ ही आयोग को प्राप्त शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है। वे जोड़ते हैं कि राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार है, जो अधिनियम में उसे प्राप्त अधिकारों और शक्तियों से परे जाकर न तो अधिनियम की व्याख्या कर सकता है और न ही अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अनुशंसा कर सकता है।

एक अन्य अधिवक्ता का कहना है कि यह सही है कि सूचना का अधिकार एक अनियंत्रित अधिकार नहीं है। खुद अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के साथ ही धारा 8, धारा 9 और धारा 11 में मांगी गई जानकारियों को नियंत्रित करने के प्रावधान किए गए हैं। मगर, चूँकि सूचना को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, इसलिए अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि लोकहित में प्रत्येक जानकारी का प्रकटन किया जा सकता है। लोगों को सूचनाएं दिलवाने के लिए सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। मप्र सूचना आयोग में नियुक्त प्रत्येक सूचना आयुक्त को प्रतिमाह 2 लाख 25 हजार रुपए वेतन के रूप में देय होगा। यदि पहले से नियुक्त व्यक्ति को कोई पेंशन मिलती है तो वेतन से उसे घटा दिया जाएगा। महंगाई भत्ता भी नियमानुसार दिया जाएगा। मप्र सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को विधि, समाज सेवा, प्रबंध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, जनसंपर्क, माध्यम या शासन प्रशासन में व्यापक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो। मप्र राज्य सूचना आयोग में नियुक्त सूचना आयुक्त किसी संसद, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, न ही किसी राजनीतिक दल का सदस्य होगा न कोई कारोबार करेगा।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

दिल्ली में लागू मोटर व्हीकल एक्ट ने मप्र सहित कई राज्यों को पसोपेश में डाल दिया है। इस एक्ट के तहत 10 साल से अधिक पुरानी बसें प्रदेश से दूसरे राज्यों में आवागमन नहीं कर सकतीं। इस एक्ट के कारण जहां बस ऑपरेटर्स को बड़ी क्षति पहुंचेगी, वहीं सरकार को भी करोड़ों रुपए की राजस्व हानि होगी। ऐसे में बस ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर सकती है। हालांकि एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि यात्री सुरक्षा को देखते हुए 10 साल तक पुरानी बसों को ही इंटर स्टेट चलाने का नियम लागू कर रखा है।

दिल्ली में लागू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर मप्र सरकार अपने यहां भी वैसा ही प्रावधान लागू करती है तो हर साल 10 साल पुरानी करीब 200 बसें बाहर होंगी। ऐसा हुआ तो बस ऑपरेटर्स समेत शासन को भी राजस्व की हानि होगी। अभी प्रदेश में 2202 बसें सभी तरह के परमिट पर चल रही हैं। इनमें से 200 बसें जल्द ही एक्ट के दायरे में आ जाएंगी। प्रदेश में परिवहन कार्यालयों में रजिस्टर्ड कुल बसें 35,882 हैं। 10 साल से ज्यादा पुरानी पर 15 से कम 10,589 बसें हैं। बाकी बसें जिनमें 25,293 स्कूल बस भी शामिल हैं। 10 साल तक पुरानी बसों की संख्या 832 हैं। दूसरे राज्यों तक आवागमन करने वाली, अस्थाई परमिट वाली 1370 बसें हैं। वहीं दूसरे राज्यों तक आवागमन करने वाली कुल इंटर स्टेट बसें 2202 हैं। मैकेनिकल विशेषज्ञ मैनिट डॉ. आरके द्विवेदी का कहना है कि कोई भी 15 साल से पुरानी बस है, तो वह प्रदूषण तो फैलाएगी। उसका मेंटेनेंस समय-समय पर होता रहे तो वह प्रदूषण कम करेगी।

जानकारी के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 साल से अधिक पुरानी बसें प्रदेश से दूसरे राज्यों में आवागमन नहीं कर सकतीं। गौरतलब है कि दिल्ली पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले अपने यहां 10 साल से ज्यादा पुरानी बस को इंटर स्टेट चलाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि राजस्थान, उप्र और कुछ अन्य राज्यों में 15 साल पुरानी बसों को स्टेज कैरेज परमिट पर इंटर स्टेट बस के रूप में चलाने का नियम है। लेकिन मप्र में परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 77 के तहत सिर्फ 10 साल पुरानी बसों को इंटर स्टेट बस की तरह चलाने की अनुमति दे रखी है। परिवहन विशेषज्ञ व पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके त्रिपाठी का कहना है कि मप्र में स्टेज कैरेज 10 साल पुराने होने पर परमिट नहीं दिया जा रहा है। यह सुरक्षा के लिए सही निर्णय है।

हाल ही में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने झांसी के एक ऑपरेटर की उप्र के स्टेट कैरेज



एक्ट की फांस में इंटर स्टेट बसें

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू

राज्य शासन के आदेश के बाद प्रदेश में 2019 के पहले के वाहनों में भी वाहन डीलर्स द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोई भी वाहन जिसमें एचएसआरपी नहीं लगी है वह अपने वाहन डीलर के पास जाकर अपने वाहन में नंबर प्लेट लगवा सकता है। इसके लिए उसे तय शुल्क चुकाना होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश दिए थे। इसके तहत 21 जनवरी 2012 को मप्र में वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने लिंक उत्सव प्रा.लि. कंपनी से 15 साल के लिए अनुबंध किया था। अप्रैल 2012 से कंपनी ने काम शुरू किया। लेकिन कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद परिवहन विभाग ने 17 अक्टूबर 2014 को अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद लंबे समय तक शासन और कंपनी के बीच कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 6 दिसंबर 2018 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से वाहन निर्माता कंपनी ही डीलर को एचएसआरपी देगी और डीलर इसे तैयार कर वाहनों पर लगाएंगे। इसके चलते 1 अप्रैल से नए वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो गया, लेकिन इसके पहले के वाहनों को नंबर प्लेट नहीं मिल पाई।

परमिट पर मप्र में आवागमन करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि भले ही उग्र के परिवहन विभाग ने इंटर स्टेट संचालन के लिए 15 साल की अवधि तय कर रखी हो परंतु इन्हें मप्र में नहीं चलाया जा सकता। हालांकि पूर्व में कुछ ऑपरेटर्स ने अलग-अलग कोर्ट में याचिकाएं लगाईं, लेकिन अब वे सब खारिज हो चुकी हैं। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य दीपक वर्मा का कहना है कि शासन ने नियम में संशोधन नहीं किया तो बस ऑपरेटर्स को आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही शासन को राजस्व की क्षति पहुंचेगी।

स्टेज कैरेज बसें ए श्रेणी की बसें फिक्स बस स्टैंड से चलती हैं। स्टॉपेज, रूट और दूरी सब फिक्स होता है। इन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट के रूप में चलाया जाता है। 15 साल तक इनके संचालन का नियम लागू है। बी श्रेणी में इंटर स्टेट बसें भी आती हैं। इनका संचालन दो राज्य आपस में परस्पर करार के तहत करते हैं। 10 साल वाला नियम इस श्रेणी पर ही लागू है। निजी बसें ए श्रेणी लिमिटेड एरिया या किमी में एयरपोर्ट, प्राइवेट कंपनियों में अटैच बसें इस श्रेणी में आती हैं। ये बसें भी प्रदेश में 20 साल तक चल सकती हैं। स्कूल-कॉलेज बस को बी श्रेणी में शामिल किया गया है। यह भी 20 साल तक चल सकती हैं। कांटेक्ट कैरेज ए श्रेणी में इन्हें ऑल इंडिया परमिट लेकर संचालित किया जाता है। संचालन बस स्टैंड से नहीं होता। इन पर भी 10 साल वाला नियम लागू होता है। इसी प्रकार बी श्रेणी की बसों को व्यक्ति यात्रा के लिए बुकिंग, तीर्थ दर्शन बस के रूप में अस्थाई ऑल इंडिया या दो स्थान विशेष के बीच परमिट लेकर संचालित किया जा सकता है। 10 साल अवधि तक की पुरानी बस ही चल सकती है।

● राकेश ग्रोवर

मप्र में जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं नए जिलों की घोषणा की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनावी साल में अभी तक 2 नए जिलों-मऊगंज और नागदा की घोषणा कर चुके हैं।

संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में जिस तरह अलग-अलग जिलों की मांग की जा रही है, उससे इस चुनावी साल में कुछ और जिलों की घोषणा हो सकती है। वहीं दो और जिलों की घोषणा कमलनाथ सरकार के समय से फाइलों में दबी है।

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में मप्र में 56 से अधिक जिले हो सकते हैं।

गौरतलब है कि जब भी चुनाव आते हैं अलग-अलग जिलों की मांग होने लगती है। वर्तमान में 16 और जिलों की मांग हो रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव तक जिलों का गणित फिर करवट ले सकता है। 52 जिलों वाला मप्र 56 तक पहुंच सकता है। चुनावी साल में हर बार जिलों की सियासत वोटबैंक साधने के लिए होती है। मप्र के गठन के समय 1956 में 43 जिले थे। छत्तीसगढ़ बनने के समय 2000 में 45 जिले थे। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनावी कनेक्शन ने हर बार जिले बढ़ा दिए। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, नए जिलों का गठन किया जाता है। इस बार मप्र में दो नए जिलों की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को मऊगंज को जिला गठन करने का ऐलान किया। फाइलें चल पड़ी हैं। रीवा जिले से अलग कर इसका गठन होगा। वहीं 20 जुलाई को नागदा को जिला बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। जल्द गठन की फाइलें चलेंगी। यह उज्जैन से अलग होकर बनेगा। इन दोनों जिलों के गठन से मप्र में जिलों की संख्या 54 हो जाएगी। 2003 में भाजपा ने आते ही तीन नए जिले अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर बनाए। मुख्यमंत्री उमा भारती थीं। कुल जिले 48 हुए। 2008 में चुनावी साल होने के कारण फिर दो जिले अलीराजपुर, सिंगरौली बनाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे। इससे कुल जिले 50 हो गए। 2013 में अगस्त में शाजापुर से अलग कर आगर-मालवा गठित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ही थे। तब जिले 51 हो गए। 2018 में ठीक चुनाव के एक महीने पहले अक्टूबर में ठीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ही थे। कुल जिले 52 हो गए। चुनाव तक दो जिले और बन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या तो मैहर व चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणा कर इनके गठन की बाजी पलट सकते हैं या अन्य मांगों को लेकर विचार हो सकता है। मैहर व चाचौड़ा को लेकर भी फाइलें सीमित तौर पर चल चुकी हैं, इसलिए ये मसला आगे उलझेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागदा, मैहर, चाचौड़ा को

मप्र में होंगे 56 जिले!



अब इनको जिला बनाने की मांग

प्रदेश में कई अन्य जिलों का बंटवारा कर नए जिले बनाने की मांग हो रही है। ओंकारेश्वर, बड़वाह, सोनकच्छ, सिरोंज, बीना, कन्नौद, खातेगांव, बागली, लवकुश नगर, जावरा को जिला बनाने की मांग की जा रही है। देवास के बागली को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। दीपक जोशी ने इसे उठाया था। हाटपिपलिया उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी। सिरोंज व गंजबासौदा को भी जिला बनाने की मांग हो रही है। 2013 में यह मुद्दा बना था। सागर जिले की खुरई तहसील को अलग जिला बनाने की मांग की जा रही है। नए जिले बनाने से जहां नफा है तो नुकसान भी कम नहीं है। नए जिले के लिए बजट, स्टाफ, प्लानिंग, विकास अलग होगा। कलेक्टर-एसपी सहित अन्य अफसर अलग से रखे जाएंगे। विकास पर फोकस योजनाओं में अलग पात्रता होगी। दूसरी ओर ताबड़तोड़ जिले बनने से लंबे समय तक कई जिलों को अमला नहीं मिलता है। कम स्टाफ, शुरुआत में कम संसाधन, पांच से दस साल एक जिले को अमला व अन्य सुविधाएं पाने में लग जाते हैं। पूर्व सीएसएस सीसी बेहार का कहना है कि जिले का गठन प्रशासनिक और जनता की जरूरत से होना चाहिए, इसे राजनीति के लिए नहीं बनाना चाहिए। मप्र में ऐसा हुआ कि घोषणा कर दी गई, लेकिन आपत्तियां इतनी आईं कि जिले नहीं बन सके। मापदंड तय कर देखना चाहिए कि जिला बनाने पर पर्याप्त संसाधन व सुविधाएं तुरंत मिल सकें।

जिला बनाने की घोषणा की थी। फाइलें चलीं लेकिन, अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। नागदा में कांग्रेस काबिज है। मैहर, चाचौड़ा का गणित उलझा है। मैहर को अलग जिला बनाने भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोर्चा खोल रखा है। पार्टी भी बना ली है। मैहर अभी सतना में है। चाचौड़ा को गुना से अलग कर जिला बनाने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह मुहिम चला रहे हैं। दोनों जिलों का गठन सियासी गणित में भाजपा के लिए मुफीद नहीं है।

मप्र को 15 अगस्त के दिन 53वें जिले की सौगात मिल जाएगी। रीवा से अलग होकर बना मऊगंज जिला अगले महीने से अस्तित्व में आ जाएगा। जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। अब तक प्रदेश में 52 जिले थे। मप्र के नए जिले मऊगंज को बनाने के लिए प्रारूप की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस जिले में चार तहसीलें शामिल होंगी। जिसमें नईगढ़ी, हनुमना और मऊगंज शामिल रहेगी। इसके अलावा देवतालाब उप तहसील को नई तहसील बना दिया जाएगा। ऐसे में नवागत जिले में चार तहसीलें हो जाएंगी। हालांकि मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर विकासखंडों की संख्या तीन ही रहेगी। जबकि जिले में दो

विधानसभा सीटें मऊगंज और देवतालाब आएंगी। बता दें कि मऊगंज को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। बता दें कि अब तक मऊगंज रीवा जिले की एक तहसील थी। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश नए जिले में शामिल होने पर थाने और पुलिस चौकी के साथ राजस्व और अनु विभागों की स्थिति भी साफ हो गई। नए जिले में 5 थाने, 5 चौकियां, 230 पुलिस बल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मऊगंज का जिला मुख्यालय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के भवन शुरुआती दिनों में लगेगा, साथ ही इसी भवन को कलेक्टर कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मऊगंज जिले की सीमा उप्र के मिर्जापुर और पूर्व में सीधी जिले से लगेगी। जबकि इसके उत्तर में रीवा जिला एवं उप्र का प्रयागराज है, वहीं पश्चिम में रीवा जिला रहेगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने नवीन जिला मऊगंज के संबंध में आम लोगों से 30 दिन का समय अपने दावे व आपत्ति के लिए दिया है। 15 अगस्त के बाद जिले में कलेक्टर और एसपी पदभार ग्रहण कर लेंगे।

● लोकेंद्र शर्मा

देश में सबसे ज्यादा बाघों के साथ टाइगर स्टेट कहे जाने वाला मप्र अपना यह दर्जा कायम रखते हुए बहुत आगे निकल गया है। 29 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 785 बाघ मप्र में हैं। इसके बाद 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे और 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। टाइगर-डे पर देशव्यापी बाघ गणना के आंकड़े जारी हो गए, जिसमें 165 बाघों के साथ बांधवगढ़ मप्र में अव्वल है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में अभी प्रदेश में बाघों की संख्या का जिक्र हुआ है। बांधवगढ़ ग्रोथ रेट के मामले में अव्वल रहा है। वर्ष 2018 की गणना में भी बांधवगढ़ बाघों की ग्रोथ रेट में मप्र में अव्वल रहा था।

बता दें कि हर चार साल में देशभर में राज्यवार बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इससे पहले साल 2018 में आंकड़े जारी हुए थे, तब मप्र में 526 बाघ थे। जो देशभर में सबसे ज्यादा संख्या थी। इस बार यह संख्या बढ़कर 785 हो गई है और मप्र को टाइगर स्टेट का तमगा फिर मिल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई देते हुए कहा है कि अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेशवासियों के सहयोग और वन विभाग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, चार वर्षों में हमारे प्रदेश में जंगल के राजा बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को, वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण में उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आइए हम सब मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का पुनः संकल्प लें।

मप्र ग्रोथ रेट में अव्वल रहने की वजह है बांधवगढ़ की सभी 139 बीट में बाघों की मौजूदगी के निशान पाए गए हैं। बांधवगढ़ में पिछले 1 साल में 2100 से ज्यादा कैटल किल की घटनाएं हुई हैं। बांधवगढ़ में बाघों के द्वारा मनुष्य पर हमले की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर वर्ष 40 से 50 नए शावक देखे गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर ही 150 से ज्यादा बाघ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बांधवगढ़ की सभी बीट में बाघ होने के संकेत मिले थे। एक ही क्षेत्र में सात से आठ बाघ घूमते हुए देखे जा रहे हैं। जबकि बांधवगढ़ से लगे हुए जंगलों में बीस से ज्यादा बाघ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह बाघ भी बांधवगढ़ के जंगल में आते-जाते रहते हैं। इस तरह अकेले बांधवगढ़ और इससे लगे जंगल में ही पिछले चार साल में लगभग 50 बाघों के बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

सिर्फ बांधवगढ़ ही नहीं पूरे सर्किल में बाघों की भरमार है। शहडोल सर्किल में घुनघुटी, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, अनूपपुर का जंगल



मप्र फिर बना टाइगर स्टेट

4.65 प्रतिशत ग्रोथ रेट डाउन

वर्ष 2010 में बाघों की ग्रोथ रेट 20.90 प्रतिशत थी। वर्ष 2014 में ग्रोथ रेट 30.58 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2018 में ग्रोथ रेट 32.38 प्रतिशत हो गई। जबकि वर्ष 2022 के बाघ स्टीमेशन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ रेट महज 27.73 प्रतिशत ही है। यह ग्रोथ रेट पिछले स्टीमेशन यानी वर्ष 2018 के मुकाबले में 4.65 प्रतिशत कम है। इसकी वजह अब वे अफसर बताएंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपयों को जंगल में खर्च करते हैं। 2006 में बाघ संरक्षण प्रयासों को गति दी गई थी। इसके बाद से लगातार बाघों की संख्या बढ़ ही रही है। 2006 में 300 बाघों के साथ मप्र सबसे अधिक बाघों वाला राज्य था। इसके बाद 2010 में यह घटकर 257 हो गए और तब मप्र का टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक ने छीन लिया था।

शामिल है। इस पूरे क्षेत्र में बाघ दिखाई देते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि बाघों का संसार टाइगर रिजर्व की सीमाओं के बाहर भी बढ़ रहा है। टाइगर रिजर्व में तो बाघों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन रेग्युलर फॉरेस्ट में बिना ऐसे किसी बजट के बाघों की मौजूदगी ने मप्र को एक बार फिर बाघों से उन्नत प्रदेश बनने की संभावना से भर दिया है। यह जानकारी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के उस रिसर्च में भी सामने आई थी जो प्रदेश में हुई चार वर्षीय गणना के विभिन्न स्तर को लेकर किया गया था।

शहडोल जिले के घुनघुटी के जंगल में पहले भी बाघ दिखाई देते थे और इस बार भी यहां बाघ होने के चिन्ह पाए गए हैं। सीधी, ब्यौहारी, अमरकंटक, डिंडौरी सहित कई अन्य जंगलों में भी बाघ दिखाई दिए हैं। रिसर्च के अनुसार इस बार की गणना में सतना जिले के जंगल में टाइगर दिखाई दिए और अनुमान है कि यहां 6 से 8 टाइगर हैं।

चार वर्षीय बाघ आंकलन की 9 अप्रैल को जारी हुई रिपोर्ट ने वन्य प्राणी प्रेमियों को चौंका दिया था। 9 अप्रैल को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की ग्रोथ रेट बुरी तरह से डाउन हुई है। वर्ष 2022 में हुए स्टीमेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस बार महज 200 बाघ बढ़े हैं। जबकि वर्ष 2018 के स्टीमेशन में पूरे देश में 741 बाघ बढ़ गए थे। यह चिंतन का विषय है कि आखिर देश में बाघों की ग्रोथ रेट किन वजहों से इतनी ज्यादा गिर गई है।

वर्ष 2006 में देश में महज 1411 बाघ थे। वर्ष 2010 में 295 बाघ बढ़ गए और बाघों की संख्या 1706 हो गई। वर्ष 2014 के स्टीमेशन की रिपोर्ट जारी हुई तो वह पहले से ज्यादा खुशियां लेकर आई क्योंकि इस साल देश में 520 बाघ बढ़े थे और देश में बाघों की संख्या 2226 हो गई थी। इससे ज्यादा खुशियां वर्ष 2018 की गणना में तब आई जब देश में 741 बाघ बढ़े और बाघों की संख्या 2967 हो गई। वर्ष 2022 में हुए स्टीमेशन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें महज 200 बाघ ही बढ़े हैं जो पिछले कई सालों की बढ़त से काफी कम है।

● सिद्धार्थ पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश को एक नए बांध की सौगात मिल सकती है। इसके लिए तेजी से कवायद की जा रही है। यह बांध पूर्व से स्वीकृत केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत बनाया जाना है। सूत्रों का कहना है कि इस बांध की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

खुद रख सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से कवायद की जा रही है। दरअसल पानी संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड अंचल के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। यह पूरी कवायद इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है।

राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही चाहती हैं कि इस परियोजना पर चुनाव से पहले तेजी से काम शुरू हो जाए, जिससे पार्टी को चुनाव में इसका सियासी फायदा मिल सके। यही वजह है कि पन्ना और छतरपुर के कलेक्टरों को अगस्त तक गांवों के विस्थापन के निर्देश देते हुए पुनर्वास के लिए 221 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं। उधर, जल संसाधन विभाग ने ढोढन बांध निर्माण की निविदा के दस्तावेज भी तैयार कर लिए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में निविदा जारी की जा सकती है। बांध की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) पर रखने की तैयारी है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इससे मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।

हाल ही में भोपाल आए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें परियोजना से जुड़े मप्र और उप्र के अधिकारी शामिल हुए। पन्ना-छतरपुर कलेक्टर सहित कुछ और अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के कलेक्टरों से कहा कि अगस्त तक हर हाल में गांवों के विस्थापन का काम पूरा कर लें। हमें सितंबर में काम शुरू करना है। बैठक में एकीकृत भूमि शमन योजना (इंटीग्रेटेड लैंड मिटिगेशन प्लान) पर भी चर्चा हुई। करीब 3 हजार करोड़ की इस योजना में कारिडोर निर्माण से लेकर अन्य काम होने हैं।

वन विभाग ने परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवेदन किया है। इसके साथ ही दोनों जिलों के कलेक्टरों ने भी 3500 हेक्टेयर राजस्व भूमि चिन्हित कर ली है, जो वन भूमि के बदले दी जानी है। दरअसल

मप्र को मिलेगा एक और बांध!



विस्थापन क्षतिपूर्ति के लिए मिले 1114 करोड़

केन-बेतवा लिंक परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना, राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कवायद के साथ ही विस्थापन के लिए अब छतरपुर प्रशासन को 1114 करोड़ रुपए मिले हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना अर्थो रिटी (केबीएलपीए) ने परियोजना के लिए 4400 करोड़ रुपए मप्र को दिए हैं। इस राशि में से 1114 करोड़ रुपए खर्च कर परियोजना के मुख्य बांध ढोढन में प्रभावितों के विस्थापन का काम किया जाएगा। इसके साथ ही 3286 करोड़ रुपए खर्च कर बांध में पन्ना टाइगर रिजर्व के वन को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। इस दौरान मप्र के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और उप्र के रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकारों ने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति दी थी। पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को पारदर्शी और समय पर पूरा करने की देखरेख करने के लिए पुनर्वास व पुनर्स्थापन समिति के गठन के प्रस्ताव को बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। परियोजना के भू-भाग प्रबंधन योजना (एलएमपी) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के क्रियान्वयन के लिए एक वृहद पन्ना भू-भाग परिषद का भी गठन किया जा रहा है।

परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही 6017 हेक्टेयर वनभूमि की भरपाई राजस्व भूमि देकर करनी है। कलेक्टरों ने इसी वर्ष 5439 हेक्टेयर भूमि दे दी थी, शेष 578 हेक्टेयर भूमि और और देनी थी। इस बीच पता चला है कि जिस भूमि को राजस्व बताकर दिया गया है, उसमें से 3500 हेक्टेयर पहले से वन भूमि ही है।

परियोजना की टेक्निकल बिड बीते रोज खुल चुकी हैं। इसमें देश की 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों के अधिकारियों ने बांध के निविदा दस्तावेज देखे और धरोहर राशि 10 करोड़ से कम रखने सहित कई सुझाव दिए। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अर्थो रिटी के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का काम छह साल में पूरा करना होगा। अब निविदा का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। कंपनियों के अधिकारियों ने तकनीकी मूल्यांकन समिति को धरोहर राशि 50 करोड़ रुपए से कम कर 10 करोड़ रुपए करने और बैंक गारंटी परफॉर्मिस राशि पांच से घटाकर तीन प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। अब समिति सुझावों पर विचार करेगी और दस्तावेजों में संशोधन कर निविदा

जारी की जाएगी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए दूसरे चरण में वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के पहले सीमित क्षेत्र में निर्माण शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए विगत महीने राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात भी की है। मप्र में विधानसभा चुनाव से पहले लिंक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने आम बजट में परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार प्रोजेक्ट के लिए 4400 करोड़ रुपए दे चुकी है। जिसमें से 1114 करोड़ रुपए छतरपुर जिले को विस्थापन कार्य के लिए दिए गए थे। इधर, उप्र और मप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी देने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी की एक साल से चल रही प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के पूरे होने से पहले निर्माण शुरू करने की योजना बनाई गई है।

● श्याम सिंह सिकरवार



क्यों आग में जल रहा मणिपुर?

हिंसा...नग्न परेड और शर्मसार होता देश...

जो पहले एक-दूसरे के दुश्मन थे,
आज एक होकर मैतेई से लड़ रहे हैं... क्यों?

मणिपुर के हालात का कौन है असली
गुनहगार...प्रशासन, विपक्ष या सरकार...?

एक तरफ दावा किया जा रहा है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगभग 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आलम यह है कि मणिपुर में हिंसा, नग्न परेड से देश शर्मसार हो रहा है। राज्य में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई शांति समिति के बाद भी असंतोष और दो गुटों के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

● राजेंद्र आगाल

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हो रही हिंसा और उपद्रव को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व समुदाय चिंता में है, लेकिन स्थिति इतनी विकट है कि मैतेई और कुकी समुदाय एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रदेश सरकार मणिपुर की आग को शांत

करने में पूरी तरह विफल हो गई है। हिंसक भीड़ में शासन-प्रशासन, किसी का खौफ नहीं दिख रहा। तमाम प्रयासों के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मणिपुर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? मैतेई समुदाय या नगा-कुकुकी समुदाय... या फिर प्रशासन, विपक्ष या सरकार? सबसे हैरानी

की बात तो यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की ही सरकार है, फिर भी हिंसा पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। मणिपुर में स्थिति इतनी विकट है कि महिलाओं की कब अस्मत् लूट ली जाए, कब किसका घर जला दिया जाए, कब किसको गोलियों से भून दिया जाए, कोई नहीं बता सकता।

मणिपुर में शांति बहाली के लिए अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं, सभी विफल साबित हुए हैं। अब स्थिति यह है कि इस हिंसा की आग पर राजनीतिक रोटियां भी सेंकी जाने लगी हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद राज्य का दौरा करके आए हैं और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग कर रहे हैं। उधर, भाजपा मणिपुर की बात करने की बजाय पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ घटित अपराधों को उछालकर अपना दाग धोने की कोशिश कर रही है। उधर, लड़कियों को नग्न कर घुमाने के वीडियो को स्वतः संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं।

हिंसा के दो प्रमुख कारण

मणिपुर हिंसा में हिंसक भीड़ के सामने जो आता है, उस पर हमला बोल दिया जाता है। चाहे मैतेई समुदाय हो या नगा-कुकी समुदाय, सब एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मणिपुर हिंसा के दो मुख्य कारण सामने आए हैं। पहली वजह- मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध और दूसरी वजह- राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और अफीम की खेती पर शिकंजा कसना। कोर्ट के आदेश के बाद तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया और पूरा राज्य इसी हिंसा में जलने लगा है। इसके बाद मैतेई समुदाय के विरोध में कुकी समुदाय के लोग आ गए हैं। आपको बता दें कि एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर मैतेई समुदाय ने 3 मई को प्रदर्शन किया था। इसके विरोध में कुकी समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोग 4 मई को आमने-सामने आ गए और पूरे राज्य में हिंसा फैल गई। इसके बाद बढ़ती हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों के अलावा सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को तैनात किया गया। हिंसा की आग में अब तक कई लोगों की जिंदगियां समा गईं और कई परिवार अपना सबकुछ छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। मणिपुर की कुल आबादी 3 करोड़ है। मैतेई समुदाय की आबादी करीब 53 फीसदी है, जबकि नगा और कुकी समुदायों की संख्या 40 फीसदी है। मैतेई समुदाय की संख्या ज्यादा होने के बाद उनका दबदबा राज्य के 10 प्रतिशत भूभाग पर ही है और वे इफाल घाटी में निवास करते हैं। वहीं, कुकी समुदाय के लोग पर्वतीय जिलों में रहते हैं। नगा और मैतेई लोगों को ही मणिपुर का मूल निवासी माना जाता है। बाकी समुदाय यहां बाद में आए। कुकी लोगों का मणिपुर में आगमन 1844 से शुरू हुआ। कुकी बर्मा यानी म्यांमार से आकर यहां की



उपद्रवियों के पास विदेशी हथियार

मणिपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पास अच्छी खासी संख्या में विदेशी हथियार होने की बात सामने आ रही है। उपद्रवी समूहों ने इन हथियारों का इस्तेमाल आपसी संघर्ष में करने के अलावा सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी किया है। मणिपुर में मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, उन्हें इस बात का पता तब चला, जब उपद्रवियों की ओर से आई गोली, बुलेटप्रूफ वाहन और जैकेट को भेद गई। बाद में मालूम हुआ कि वह तो स्टील बुलेट थी। इसका इस्तेमाल भारत में किसी भी सुरक्षा बल के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा खुलासा यह हुआ है कि मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पंगेई से उपद्रवियों द्वारा लूटे गए करीब 4500 हथियार और 6.5 लाख कारतूसों में से जो 30 फीसदी हथियार व गोला बारूद वापस जमा हुआ है, उनमें कई जंग लड़ चुके हथियार भी शामिल हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि उपद्रवियों के हाथ में ऐसे हथियार हैं, जो मणिपुर पुलिस और कमांडो तक के पास में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, चुड़ाचांदपुर, कांगपोकपी और बिशनपुरा और कई हिल क्षेत्रों में विदेशी हथियारों की मौजूदगी बताई जाती है। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद जब सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच मुठभेड़ हुई, तो यह बात पता चली थी। स्टील की गोलियां यानी आर्मर पियर्सिंग इन्सेंडरी (एपीआई) का निर्माण चीन में होता है। वहां से ये गोलियां, म्यांमार के रास्ते मणिपुर तक पहुंची हैं। 2017 में जम्मू कश्मीर में पुलवामा के लेथपोरा में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने आर्मर पियर्सिंग इन्सेंडरी का इस्तेमाल किया था। स्टील की गोली का वार झेलने की क्षमता लेवल-4 बुलेटप्रूफ कवच में होती है। भारत में आर्मी या किसी अन्य फोर्स में आर्मर पियर्सिंग इन्सेंडरी का इस्तेमाल, गैर-कानूनी है। नाटो ने भी स्टील की गोलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन और पाकिस्तान में ये गोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ समय पहले पुंछ में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने इन्हीं गोलियों का इस्तेमाल किया था। 7.62 एमएम स्टील कोर की गोलियां चीन में बनी थीं।

पहाड़ियों में बसते रहे। उनका आगमन जारी है। जो कुकी मणिपुर आ चुके हैं वे अपने लिए अलग स्थान और प्रशासन चाहते हैं।

मणिपुर में दो महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से यौन हिंसा की अमानवीय घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना के बाद राज्य में मैतेई एवं कुकी के बीच नए सिरे से तनाव भड़कने की आशंका है। मणिपुर में मैतेई और 34 जनजातियां सदियों से साथ रह रही हैं। मणिपुर मुख्य रूप से पर्वतीय राज्य है। मैदानी क्षेत्र के करीब 10 प्रतिशत में मैतेई और 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। कई त्योहारों के संस्कार ऐसे हैं जो मैतेई और जनजातियों के प्रगाढ़ संबंधों को प्रमाणित करते हैं। मैतेई शासन में उस समय परिवर्तन आया, जब 18वीं शताब्दी में राजा पामहैबा वैष्णव बन गए। परिणामस्वरूप अधिकांश मैतेई वैष्णव मतावलंबी हो गए। 1891 में अंग्रेजों के हाथों मणिपुर की पराजय हुई और फिर 1945 में वह

द्वितीय विश्व युद्ध का साक्षी बना। इस युद्ध के बाद लोकतांत्रिक तरीके से महाराजा बोधचंद्र के नेतृत्व में मणिपुर एक्ट, 1947 बना। जब भारत आजाद हुआ, तब मणिपुर एक स्वतंत्र क्षेत्र था और उसका अपना संविधान था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से मणिपुर की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां बदलीं। 1949 में मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र और भारत सरकार के बीच एक संधि के तहत मणिपुर स्टेट का भारत में विलय हुआ। 1956 में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 34 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता मिली। मणिपुर में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं, जो अपने को न कुकी मानती हैं और न ही नगा। मणिपुर में इस्लाम मानने वाले भी हैं, जिन्हें मैतेई पांगल कहते हैं। नेपाल, बिहार के अलावा जैन समुदाय के लोग भी यहां हैं।

नगा और मैतेई लोगों को ही मणिपुर का मूल



निवासी माना जाता है। बाकी समुदाय यहां बाद में आए। कुकी लोगों का मणिपुर में आगमन 1844 से शुरू हुआ। कुकी बर्मा यानी म्यांमार से आकर यहां की पहाड़ियों में बसते रहे। उनका आगमन जारी है। जो कुकी मणिपुर आ चुके हैं, वे अपने लिए अलग स्थान और प्रशासन चाहते हैं। चूड़चंदपुर पर कुकी अपना दावा करते हैं, जबकि इसे मैतेई महाराजा चुड़ाचांद के नाम पर बसाया गया था। बाद में इस क्षेत्र से ही मैतेई लोगों को भागना पड़ा। मणिपुर में एक संप्रदाय का दूसरे से संघर्ष और सहअस्तित्व भी रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में नगा-कुकी, मैतेई-मैतेई पांगल और कुकी-पाइते के बीच दंगे हुए। 1993 में नगा-कुकी के बीच हुए दंगों के बाद दोनों में समझौता मैतेई समुदाय ने कराया।

आरक्षण से निकली आग

हाल में मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच सांप्रदायिक संघर्ष की शुरुआत 3 मई को तब हुई, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा देने की पहल के खिलाफ रैली निकाली। चूड़चंदपुर की रैली में जब कुछ बंदूकधारी शामिल हो गए तब हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा की एक वजह राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के साथ अफीम की खेती के विरुद्ध चलाया गया अभियान भी माना जा रहा है। इस अभियान से चूड़चंदपुर और काड़पोक्मी जिले में असंतोष उपजा।

28 अप्रैल को चूड़चंदपुर में मुख्यमंत्री को एक जिम के उद्घाटन के लिए आना था। इसके एक दिन पहले कुकी समुदाय के एक संगठन ने बंद की घोषणा कर दी और जिम को नष्ट कर दिया। इससे तनाव फैला। इसी तनाव के बीच हाईकोर्ट का यह आदेश आया कि सरकार मैतेई को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे। इससे माहौल और बिगड़ा। चूड़चंदपुर और मोरे में मैतेई लोगों पर हमले शुरू हो गए। उनके घर और मंदिर जलाए जाने लगे। हजारों मैतेई लोगों को भागना पड़ा। पुलिस हिंसक भीड़ को काबू नहीं कर पाई। मैतेई लोगों पर हमले की

सरकार फेल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए

मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर इस समय संसद से लेकर सड़क तक गतिरोध जारी है। विपक्ष के सांसदों का एक डेलिगेशन मणिपुर राज्य के दौरे पर भी गया था। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान सांसदों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए वहां की जमीनी हकीकत को मीडिया के सामने रखा। इस डेलिगेशन में शामिल लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने मीडिया के सामने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। 29 जुलाई को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वहां हिंसा ग्रस्त इलाके में लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले मीडिया बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। इस वजह से यहां स्थिति खराब हो रही है। जल्द से जल्द शांति बहाल की जानी चाहिए, सद्भाव और न्याय बनाए रखना आवश्यक है। हम मांग करेंगे कि राज्यपाल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करें। यह सरकार की विफलता है। राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राज्यपाल राष्ट्रपति को सही रिपोर्ट भेजकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं।

प्रतिक्रिया में इंफाल पूर्व-पश्चिम, विष्णुपुर, थोबाल आदि में चिन कुकी, मिजो, ह्यार लोगों के घर-दुकान लूटे-जलाए जाने लगे। बाद में मैतेई लोगों के गांवों पर पहाड़ों से गोलियां बरसाई जाने लगीं और पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर भी हमले शुरू हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि सेना की मौजूदगी में भी हिंसा क्यों हो रही है?

पुलिस और सुरक्षा बलों पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की चार दिवसीय मणिपुर यात्रा के बाद लोगों में आशा जगी कि अब हिंसा थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंसा के 39वें दिन राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में 51 सदस्यों की एक शांति समिति बनी। इसके सदस्यों में मतभेद के चलते इस समिति की एक बैठक तक नहीं हो पाई। हिंसा को लेकर राजनीति भी हो रही है। मणिपुर सरकार के 10 कुकी विधायक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कुकी लोगों का दावा है कि मैतेई संपन्न हैं और सरकारी नौकरियों में भी उनकी संख्या ज्यादा है, पर सच तो यह है कि कुकी लोगों की संख्या भी कम नहीं है।

मणिपुर में ड्रग्स का कारोबार खूब फैला है। यहां अफीम की बढ़ती खेती को देखते हुए लोगों को डर है कि कहीं मणिपुर ड्रग्स का गढ़ न बन जाए। एक डर म्यांमार से बड़ी संख्या में आ रहे कुकी लोगों को लेकर भी है। वे अफीम की खेती करते हैं। कुकी उग्रवादी संगठन म्यांमार से हेरोइन का व्यापार करने के लिए सीमावर्ती शहर मोरे पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। म्यांमार का चिन नेशनल आर्मी उग्रवादी समूह भी मणिपुर के पहाड़ी जिलों और सीमांत इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करता है। इंफाल के एक कुकी इलाके में ड्रग्स बनाने वाली एक मोबाइल लैब मिल चुकी है। ड्रग्स के कारोबार में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग भी संलिप्त हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं, जो बंदूकधारियों के सहारे चुनाव भी जीत जाते हैं। एक उग्रवादी समूह हथियारों के सहारे कुकी होमलैंड का सपना देख रहा है।

मणिपुर में तमाम लोग कुछ समय पहले अच्छी जिंदगी जी रहे थे, वे हिंसा के बाद अचानक सड़क पर आ गए हैं। कितनों ने अपनों को खोया है। हिंसा और तनाव के बीच म्यांमार से होने वाली घुसपैठ थमी नहीं है। कुकी समूहों के हथियारबंद तत्व अब भी बेकाबू हैं। मणिपुर की हिंसा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। नहीं तो देर हो जाएगी।

हिंसा में तबाह हो रहा मणिपुर

मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके हैं। 460 से अधिक घायल हो चुके हैं। लगभग 6,745 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। 5,995 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगजनी के 5,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। कुकी तथा नगा समुदाय की जनजाति एकता रैली निकालने पर 3 मई से मैतेई समुदाय के हमले से हिंसा फैली। राज्य में करोड़ों की निजी तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। 9-10

जुलाई की रात को मणिपुर के पश्चिम कांगपोकपी क्षेत्र में हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया तथा 10 लोग घायल हो गए। राज्य के चुड़ाचांदपुर जिले की एक्सिस बैंक से हिंसक भीड़ द्वारा 1 करोड़ से अधिक नकदी तथा अन्य सामान की लूट हुई है। हिंसा रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दखल देनी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में मौजूद सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही राज्य के लोगों से ऐसे भाषण देने से बचने को कहा है, जिनसे राज्य में हिंसा भड़क सकती है। अल्पसंख्यक कुकी समुदाय वाले इलाकों में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांगों पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश के इतिहास में पिछले 70 साल में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना को इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है। यह वास्तविकता भी है कि मणिपुर में भड़की हिंसा को रोकने में भाजपा की डबल इंजन की केंद्र तथा राज्य की सरकारें नाकाम हैं। इस हिंसा की चपेट में आम लोग, पुलिस, सेना, सरकारी सेवाएं देने वाले भी हैं। सैन्य संगठनों पर हमले हो रहे हैं। लगभग 45,000 पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा के लिए दो धड़ों में बंटे हैं। मैतेई समुदाय के पुलिसकर्मी इफाल घाटी में जा रहे हैं, जहां मैतेई समुदाय की संख्या अधिक है तथा कुकी-नगा समुदाय के पुलिसकर्मी कुकी-नगा समुदाय बहुल पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं।

आईपीएस राजीव सिंह मणिपुर के पुलिस प्रमुख बने, तो उन्होंने पाया कि लगभग 1,200 पुलिसकर्मी ड्यूटी से ही गायब हैं। इसका मतलब पुलिस वाले भी भयभीत हैं। सरकार भी पुलिस वालों पर ही हिंसा का गुस्सा उतारती दिख रही है। आरोप है कि पुलिस ने हिंसा को समय पर नहीं रोका। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग से भड़की हिंसा धार्मिक हिंसा में बदल चुकी है। हिंसा के लिए कुकी समुदाय को अधिक दोषी बताने की राजनीति हो रही है। हो सकता है कि इसकी वजह मैतेई समुदाय की संख्या अधिक होना हो, जो हिंदू समुदाय है। परंतु इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने कुकी समुदाय के लोगों से उन्हें गुमराह करने के लिए माफी मांगी है। इधर लोगों ने भाजपा के खिलाफ मशाल रैली निकाली है। सैनिकों पर भी तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे बचने तथा हिंसा रोकने के लिए सैन्य संगठनों ने इन क्षेत्रों में सेना के एक अधिकारी तथा एक मजिस्ट्रेट को तैनात करने की मांग की है। अब सुरक्षा बलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम-1958 (अफस्पा) के



घिनौनी घटना

आपसी वैमनस्य और जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें सार्वजनिक रूप से घुमाने, उनके साथ वहशी व्यवहार करने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सभ्य समाज को क्षुब्ध और लज्जित करने वाली है। इस घिनौनी घटना ने मणिपुर के साथ देश को भी शर्मिंदा करने का काम किया है। इस घटना की समवेत स्वर में भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं पर भी मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना न घटे। ऐसा तभी हो सकता है, जब ऐसी किसी भी वीभत्स घटना के लिए जिम्मेदार तत्वों को जितनी जल्दी संभव हो सके, कठोरतम सजा का भागीदार बनाया जाए। यह उचित और अपेक्षित ही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपना क्षोभ व्यक्त करने के साथ यह संकल्प व्यक्त किया कि राष्ट्र को नीचा दिखाने वाली इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह हेरानी की बात है कि मई के पहले सप्ताह में घटी इस खौफनाक घटना से राज्य सरकार तत्काल अवगत नहीं हो सकी। इससे मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था की नाकाम और दयनीय दशा का ही पता चलता है।

तहत अशांत अधिसूचित 19 थाना क्षेत्रों में हिंसा रोकने में कठिनाई आ रही है। यह कानून सेना को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में यह कानून म्यांमार से घुसपैठ रोकने तथा सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटनाएं रोकने के लिए लगाया गया था। परंतु इस कानून से आम लोगों की हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। इसी अफस्पा कानून को हटाने की मांग करने पर मणिपुर की आंदोलनकर्ता इरोम शर्मिला को बहुत प्रताड़ित किया गया था। कई

साल के संघर्ष के बाद उनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों ने हमेशा अफस्पा कानून का विरोध किया है। अब सेना अफस्पा हटे क्षेत्रों में दोबारा अफस्पा कानून लगाने की मांग कर रही है। सेना का यह भी आरोप है कि उसके खिलाफ मीडिया तथा सोशल मीडिया पर निराधार आरोप लग रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने मणिपुर बार एसोसिएशन के जनता के उत्पीड़न के साक्ष्य साझा करने तथा सेना के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराने के बयान पर चिंता जताई है। इधर मणिपुर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि राज्य में भारी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हिंसा की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए घुसपैठ रोकी जाए। कुछ विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि मिजोरम तथा मणिपुर के रास्ते रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके चलते हिंसा भड़की हुई है। केंद्र सरकार ने लोगों की जानकारी का ब्यौरा तैयार कराने के निर्देश जारी किए हैं।

शासन इतना अक्षम कैसे

आखिर किसी राज्य का शासन इतना अक्षम कैसे हो सकता है कि सार्वजनिक स्थल पर इतनी घृणित घटना घट जाए और उसे कुछ पता न चले? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि मणिपुर सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरह नहीं कर पा रही है। शायद यही कारण है कि वहां लंबे समय तक बड़े पैमाने पर हिंसा के साथ आगजनी होती रही। इस हिंसा में अनेक लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान भी कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय से स्थितियां नियंत्रण में आती दिख रही हैं, लेकिन उन कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की आवश्यकता है, जिनके चलते उपद्रवियों ने

पुलिस एवं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के साथ उनके हथियार भी लूटे। मणिपुर के मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंसा में दोनों पक्ष शामिल हैं और दोनों ही पीड़ित हैं। जिसे जहां मौका मिला, उसने वहां मनमानी की। यह समझ आता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए राक्षसी क्रूर से सुप्रीम कोर्ट भी कुपित है और विपक्षी दल भी। विपक्षी नेता सड़क से लेकर संसद तक अपना आक्रोश व्यक्त करने के साथ सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह घटना ही ऐसी है कि सभी को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस बेहद गंभीर मामले पर संसद में गहन चर्चा हो और सरकार जवाब दे तो फिर उसे अपने हंगामे पर विराम लगाना होगा। आखिर ऐसी निकृष्ट घटना पर हंगामा करने से कुछ हासिल होगा या फिर व्यापक चर्चा करने से?

हालांकि निष्पक्षता से अगर कहें, तो अभी तक मणिपुर हिंसा में स्थानीय मुसलमानों अथवा रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने के साक्ष्य नहीं हैं। परंतु अगर मुसलमान इस हिंसा का हिस्सा बने, तो इसका रूप बदल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि मणिपुर में आरक्षण को लेकर फैली जातीय हिंसा हिंदू-ईसाई हिंसा से होते हुए हिंदू-मुस्लिम हिंसा का रूप ले ले। इसलिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को इसे तत्काल रोकना चाहिए। अगर हिंसा रोकना उनके वश से बाहर है अथवा संभव नहीं है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। परंतु सार्वजनिक रूप से मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री मोदी कतरा रहे हैं, जाना तो दूर वह मणिपुर का नाम तक लेने से बच रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों की मांग है कि नैतिकता के तौर पर मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए तथा गृहमंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अब मणिपुर हिंसा रोकने में उनकी नाकामी की चर्चा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा दूसरे देशों ने चिंता जताई है कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने ही देश के एक राज्य के हालात ठीक करने में नाकाम साबित हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि मणिपुर हिंसा मानवीय चिंता का विषय है। यदि स्थिति से निपटने के लिए भारत मदद मांगे, तो अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के दावे उनके मंत्री करते रहे हैं, परंतु आज वह मणिपुर हिंसा तक नहीं रोक पा रहे हैं। क्या यह खुद प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात नहीं है? अफसोस की बात है कि मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकाम भाजपा नेता पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पश्चिम बंगाल



भारत में ऐसे जाति बनती है जनजाति

साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट में फैसला हुआ कि जब तक किसी राज्य सरकार या यूटी से किसी जाति को जनजाति में शामिल करने का रिकमेंडेशन नहीं आता तब तक फैसला नहीं किया जाएगा। मणिपुर के मामले में राज्य सरकार को मणिपुर हिल कमेटी की मंजूरी लेना भी जरूरी है। राज्य सरकार अगर रिकमेंड करती है तो पहले संसद कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल के पास ये प्रस्ताव जाएगा। ये दोनों ही होम मिनिस्ट्री में आते हैं। रजिस्ट्रार जनरल अपनी रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल ट्राइब को भेजेगा, जो एक विशेषज्ञ समिति बनाएगा। इस विशेषज्ञ कमेटी में सोसियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दूसरे विषयों के जानकर हर पहलू पर विचार करके जनसुनवाई करेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करके जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय विचार के बाद एक कैबिनेट नोट तैयार करेगा और फिर मामला कैबिनेट को जाएगा। कैबिनेट विचार करके उचित समझती है तो संसद में प्रस्ताव लाएगी। संसद से प्रस्ताव पास करके अगर राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो कानून बनेगा, तब वो जाति शिड्यूल ट्राइब में शामिल होगी। साल 1965 में अनुसूचित जातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने की समीक्षा के लिए लोकुर समिति का गठन हुआ, तब भी आश्चर्यजनक रूप से मैतेई का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि मणिपुर में खोनजाई, नगा, मारिंग्स और मिजोस जैसी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुशंसित किया गया था। कहीं-कहीं पर उल्लेख मिलता है कि साल 1949 में भारत में विलय से पहले मैतेई जनजाति माने जाते थे।

में पंचायत चुनावों में हुई हिंसक झड़पों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने वहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि मणिपुर के दो महीने से अधिक समय से हिंसा में जलने, असम में एनआरसी के दौरान हिंसा भड़कने, उग्र में 67 प्रतिशत सीटों पर मतदान न कराने तथा पहलवान बेटियों पर अत्याचार होने के दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ थी? ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले दो साल में 154 टीमों ने दौरा किया है।

मणिपुर हिंसा की अगर बात करें तो वहां मैतेई समुदाय को बल मिला हुआ है। राज्य की लगभग 38 लाख की आबादी में लगभग 53 प्रतिशत मैतेई हैं तथा 40 प्रतिशत नगा व कुकी हैं, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। राज्य के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक भी मैतेई समुदाय से ही हैं, बाकी 20 विधायक ही नगा तथा कुकी समुदायों के हैं। राज्य में अब तक के शासन में कुल 12 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से दो

ही अनुसूचित जनजाति से रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से हैं। हिंसा में शामिल गुटों में मैतेई गुट में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटी, अरम्बई टेंगोल, मैतेई लिपुन तथा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसे गुट शामिल हैं। वहीं कुकी गुट में कुकी नेशनल आर्मी, जोमी रिवाल्व्यूशनरी आर्मी, कुकी रिवाल्व्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन गुट शामिल हैं। हालांकि जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद मैतेई मणिपुर के 10 प्रतिशत राज्य 80 प्रतिशत जनसंख्या में हैं, जबकि राज्य का 90 प्रतिशत क्षेत्र नगा, कुकी बहुल है। बस इसी 90 प्रतिशत क्षेत्र में मैतेई समुदाय अधिकार चाहता है, जहां आधिपत्य के लिए इस समुदाय के लोगों को जनजाति में शामिल होने का रास्ता समझ आया है, जिसके चलते हिंसा भड़की। कुकी तथा नगा जनजातियों को लगता है कि अगर मैतेई समुदाय को भी जनजाति का दर्जा मिल गया, तो कुकी तथा नगा समुदाय के नौकरियों के बचे हुए अवसर भी उनके हाथ से निकल जाएंगे।

देश में 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पतझड़ का मौसम शुरू हो गया। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं और देश के पॉलिटिकल मैप से कांग्रेस का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कई राज्यों में सरकार होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी देशभर में खुद को सबसे ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में मानती है, लेकिन क्या 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिटर्न होगी? यह एक बड़ा सवाल है।

इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी अपने कामकाज के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग एक साल से भेंट मुलाकात के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्र के 3-3 गांव घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 80 के आसपास विधानसभा क्षेत्र कवर कर लिया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग के विधानसभा में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में डेढ़ दशक से सत्ता पर काबिज भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब रही थी। तब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए दो बड़े दावेदार भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सामने आए थे। आखिरकार, भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी गई। उस दौरान खूब चर्चा थी कि पार्टी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की मंजूरी दी है, मगर खुलकर कभी भी किसी नेता ने इसका खुलासा नहीं किया। अब 2023 में लगभग पांच महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के दोनों ताकतवर नेताओं को फिर से मैदान में उतार दिया है। सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री पद देकर साफ कर दिया गया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव भी दोनों नेताओं की जुगलबंदी में ही लड़ा जाना है। पार्टी के इस दांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कई चुनौतियों के दरवाजे खुल गए हैं।

जाहिर है, बघेल और सिंहदेव फिर चुनावी रथ की कमान संभालने जा रहे हैं। आने वाले समय में बघेल और सिंहदेव दोनों को ही अपने-अपने कार्यक्रम सावधानीपूर्वक तैयार करने होंगे। अपने साथ आने वाले नेताओं की पहचान करनी होगी, उन मुद्दों पर भी निर्णय लेने होंगे जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में संबोधित किया जाना है। स्वाभाविक है पार्टी का यह निर्णय बघेल के लिए चुनौती से कम नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रायपुर में

बघेल की चुनौतियां



घोटालों में घिरी सरकार

छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से चल रही ईडी अपनी कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के घर तक पहुंची है। इसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर कोयला के कारोबार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वहीं ईडी की रेंज विधानसभा चुनाव के नजदीक आते-आते लगातार बढ़ रही है। इसका चुनावी असर भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में फोकस बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर उतर रही है। इसके अलावा पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की मानें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था।

कांग्रेस महाधिवेशन के सफल आयोजन से बघेल का कद पार्टी में लगातार बढ़ा है। वे आज सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में बघेल की आज अलग छवि है। फिर भी सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से कई नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। ऐसे में बघेल के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की है।

आज बघेल नरम हिंदू विचारों के बड़े नेता माने जाते हैं। उग्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की शरण में हैं तो बघेल भी माता कौशल्या का आंचल थामे हुए हैं। वे माता कौशल्या का मंदिर बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस चुनाव में बघेल भाजपा के धर्म का खवाला होने की भूमिका और भ्रम को भेदने जा रहे हैं। इसे भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के बड़े-छोटे नेता कांग्रेस की जमीन भेदने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भाजपा के पास नेताओं और प्रचारकों की पूरी फौज है जो विभिन्न अभियानों में एक साथ हिस्सा लेती है और राज्य में कई जगह सभाओं को संबोधित कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के इस आक्रमण और घेराबंदी से जूझने में अब बघेल को अकेले ही ज्यादातर समय लगाना पड़ सकता है।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज्य में लगभग एक वर्ष से भ्रष्टाचार संबंधी जांच कर रही है। इन कार्रवाईयों में ज्यादातर कांग्रेसियों पर ही फंदा कसा जा रहा है। ईडी की जांच की आंच बघेल के लिए चुनौतियों से भरी दिख रही है। बघेल सरकार के मोर छत्तीसगढ़ मोर माटी, मोर महापौर मोर द्वार, मोर सरपंच मोर द्वार, मोर विधायक मोर द्वार जैसे कार्यक्रमों से लोगों को जोड़े रखने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। कई मायनों में ऐसे कई कार्यक्रम यहां के लोगों को छत्तीसगढ़िया होने का एहसास भी करा रहे हैं। भाजपा हर हाल में चुनाव के दौरान इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश में है। वह कांग्रेस के इस छत्तीसगढ़िया गौरव के एहसास को तोड़कर लोगों को भ्रष्टाचार-मुक्त, गुंडागर्दी-मुक्त, भय-मुक्त नया छत्तीसगढ़ देने की बात कर रही है। बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मोर छत्तीसगढ़ मोर माटी को बचाने की है। ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता या तो मोर छत्तीसगढ़ मोर माटी पर मोहर लगाएगी या फिर उन नेताओं को सबक सिखाने जा रही है जो बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक हैं। इन सभी विधायकों को 2023 में रिपोर्ट करना, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हर विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही जीतने वाले प्रत्याशियों पर ही दांव लगा सकती है।

● रायपुर से टीपी सिंह

6

मोदी सरकार के दसवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही मानों अगली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने की संभावना धुंधली होने लगी है। यही कारण है कि एक ओर जहां विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में इकट्ठा होने का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी की ओर से भी एनडीए के पुनर्जीवन के प्रयास शुरू हो गए हैं। 18 जुलाई को दिल्ली से दूर बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने जहां मोदी को हराने की रणनीति पर विचार किया, वहीं दिल्ली में एनडीए के तहत 38 दलों को इकट्ठा कर गठबंधन की राजनीति के नए दौर की शुरुआत की है।



गठबंधन की राजनीति का नया दौर

सं प्रग की जगह इंडिया को जिन राज्यों में दिक्कत हो सकती है उसमें 80 लोकसभा सीटों वाला उप्र, 40 सीटों वाला बिहार शामिल है। यानी कुल 120 सीटें हैं। इसी तरह अंग्रेजी नाम से असहज राज्यों में राजस्थान की 25, मप्र की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें यानि कुल 65 सीटें हैं। प्रखर भारतीय अस्मिता वाले राज्य तेलंगाना से लोकसभा की 17 सीटें हैं। बिहार से लगे हिंदीभाषी राज्य झारखंड से 14, हरियाणा से 10, दिल्ली से 7, उत्तराखंड से 5, हिमाचल से 4 सीटों के मतदाता संप्रग की जगह इंडिया वाले नामकरण से कैसे लुभाए जाएंगे इस चुनौती से एकजुटता में दरार को आशंका बनी रहेगी।

विपक्षी एकता की इस दूसरी बैठक से बिहार के नेताओं को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थीं। शायद इसलिए भी ज्यादा निराशा मिली। उम्मीद की वजह विपक्षी एकता के अग्रणी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा से जुड़ी रही। गठबंधन के नए नामकरण की बजाय उनको लग रहा था कि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम पर सहमति बनेगी। नीतीश कुमार स्वयं संयोजक के उम्मीदवार थे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का ऑफर मिले। इससे बेटे तेजस्वी यादव के बिहार

के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता निकलेगा। मगर इस पर कोई निर्णायक घोषणा ही नहीं हुई।

संयोग से यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब गठबंधन की राजनीति का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। आज से ठीक 25 साल पहले 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस (एनडीए) नामक राजनीतिक मोर्चे का गठन हुआ था। इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। बाबरी विध्वंस के बाद राजनीतिक रूप से लगभग अछूत बना दी गई भाजपा को इससे न सिर्फ संजीवनी मिली बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले अटलजी के नेतृत्व में देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। वास्तव में गठबंधन की राजनीति का ध्येय सर्वसमावेशी है। यह बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की ओर बढ़ने का माध्यम है। लेकिन गठबंधन की राजनीति के अंतर्विरोध भी खूब हैं। गठबंधन में शामिल छोटे-छोटे दलों के नेता व्यक्तिगत स्वार्थों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन का नेतृत्व करने वाले दल पर दबाव बनाकर अपने निजी हितों की पूर्ति करना चाहते हैं।

राजनीतिक विविधताओं से भरे भारत में गठबंधन की सरकारें हकीकत भी हैं और फसाना भी। शायद इसीलिए

इंडिया का नामकरण दे सकता है तीसरे मोर्चे को ताकत

क्या जन्म के साथ ही नए अवतार वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंकलूसिव एलायंस यानी इंडिया के नाम को लेकर विपक्ष के नेता असहज होने लगे हैं? क्या यह असहजता इतनी बढ़ेगी कि एक बार फिर से यह तीसरे मोर्चे की वजह बन जाएगी? यह सच है कि संयुक्त प्रजातांत्रिक गठबंधन यानी संप्रग का अंग्रेजी नामकरण इंडिया हिंदी पट्टी के नेताओं को कम लुभा रहा है। क्या यही एक वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुजुर्ग लालू प्रसाद के साथ फाइल बैठक से पहले ही बेंगलुरु से रवाना हो गए? इनकी तरह ही उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा प्रो. रामगोपाल के साथ गठबंधन के ऐलान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच से नदारद रहे। भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में घेरने के लिए संयुक्त विपक्षी गठबंधन की यह दूसरी बैठक दक्षिण के राज्य कर्नाटक में थी। इसलिए यहां गठबंधन का अंग्रेजी नाम इंडिया रख पाना संभव हुआ। इस पर पड़ोसी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश व बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं का तत्काल कोई ऐतराज उभरकर सामने नहीं आया। शायद यह विपक्षी एकता की पटना वाली पहली बैठक में संभव नहीं हो पाता। अंग्रेजी वाले नाम को लेकर हिंदी समर्थक नेताओं की असहजता स्वाभाविक है। उप्र में स्व. मुलायम सिंह की पूरी राजनीति प्रखर हिंदी समर्थक के बल पर खड़ी थी। कांग्रेस संग किसी चुनावी एलायंस की गंभीर पहल से बचते रहे अखिलेश यादव को इंडिया नाम कितना पसंद आया यह आने वाले दिनों में नजर आएगा।

9

आजादी के बाद से ही मिली-जुली सरकारों को देश के लिए अभिशाप बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने कांटे से कांटा निकालने की तर्ज पर वर्ष 2004 में यूपीए गठबंधन को अमलीजामा पहनाया और गठबंधन के बूते लगातार 10 साल तक रायसीना हिल्स पर राज किया। लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के बाद छोटे दलों की अहमियत वह नहीं रही जो 90 के दशक में थी। पिछले 9 वर्षों में विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें हुईं पर नतीजा सिफर ही रहा। अब जबकि 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर गठबंधन पर सबका जोर है।

पिछले दिनों पटना में बैठ चुके 15 विपक्षी दल चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए बैंगलुरु में फिर से बैठे हैं। वहीं स्पष्ट बहुमत के गुमान में छोटे सहयोगी दलों की अनदेखी के आरोपों से घिरे सत्ताधारी दल के कर्ता-धर्ता भी विपक्षी एकता के बरक्स राज्यों के छोटे-छोटे दलों को मिलाकर अपने गठबंधन का आकार बड़ा करने में दिन-रात जुटे हुए हैं। यानी कि 25 साल पहले जहां से गठबंधन की राजनीति चली थी, एक बार फिर उसी मोड़ पर आ पहुंची है। जहां तक देश में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन कर चुनावी मोर्चा तैयार करने की बात है तो यह आजादी के बाद से ही विभिन्न स्वरूप में सामने आता रहा है।

सदन के भीतर विपक्षी दलों के गठबंधन की बात पहली लोकसभा 1952 के गठन के साथ ही शुरू हो गई थी। कुल 499 सदस्यों वाली संसद में कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत हासिल की थी। सत्तापक्ष के विरुद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ, हिंदू महासभा, अकाली दल, गणतंत्र परिषद को एक साथ लाने में सफल रहे और सदन में इनकी संख्या 32 तक पहुंच गई थी। उसी दौर में दूसरा गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) का बना तब इनके सदन में 28 सदस्य थे। केएमपीपी की स्थापना आचार्य जीबी कृपलानी ने कांग्रेस से असंतुष्ट होने के कारण की थी। तीसरा गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टियों का था जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के 7 में से 6 सदस्य एवं आधे दर्जन से ज्यादा स्वतंत्र सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा एक चौथा गठबंधन जयपाल सिंह के नेतृत्व में बना जिसमें झारखंड पार्टी के तीन सदस्यों के अलावा चार राजा, तीन जागीरदार व एक बड़े व्यवसायी का नाम शामिल था। सदन के भीतर बने इस गठबंधन के किसी भी समूह के पास सदन के कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत हिस्सा नहीं था ताकि विपक्ष के नेता के लिए सदन की मान्यता हासिल हो सके।

सदन के बाहर 1971 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था। इसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। इसे स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का



नए बने गठबंधन में क्या जुड़ा और क्या घटा ?

2004 में अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि एनडीए चुनाव जीतेगा। सर्वेक्षणों ने ही नहीं, बल्कि सभी एविजट पोल ने भी एनडीए को 250 से ज्यादा सीटें दिखाई थीं। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कोई चेहरा नहीं था। चुनावों से पहले के कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था। उदारीकरण की नीतियां ट्रेक पर आ गई थीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, जो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा और भारत के लिए एक रिकॉर्ड था। फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग का प्रचार था। लेकिन एगिजट पोल्स की 250 सीटों के मुकाबले एनडीए 181 पर अटक गया था। भाजपा 182 से घटकर 138 पर आ गई, और कांग्रेस 114 से बढ़कर 145 हो गई। इसकी वजह यह थी कि डीएमके, टीडीपी, लोजपा और रालोसपा एनडीए छोड़ गई थीं। ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद कांग्रेस के सहयोगी सिर्फ 73 सीटें जीत सके थे, जिनमें सबसे ज्यादा आरजेडी की 24 और डीएमके की 16 और एनसीपी की 9 सीटें थीं। इसलिए न एनडीए को बहुमत मिला था, न कांग्रेस गठबंधन को। चुनाव के बाद यूपीए बना, जिसमें कांग्रेस के पुराने सहयोगियों के अलावा पीडीपी, टीआरएस, एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा, केरल का जनता दल डेमोक्रेटिक, एमडीएमके, टीआरएस, पीएमके और बसपा शामिल हुए। लेकिन इन सब की संख्या भी कुल मिलाकर 218 ही हुई थी, तब वामपंथी दलों के 59 सांसदों और समाजवादी पार्टी के 36 सांसदों के बाहरी समर्थन से यूपीए की सरकार बनी थी।

पहला पूर्ण गठबंधन कहा जाता है। सन् 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस (ओ), भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल सहित पूरा विपक्ष मिलकर 1977 चुनाव में उतरा और दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस (इ) को उखाड़ फेंका। इसके बाद वर्ष 1989 में जनता दल के नेता वीपी सिंह ने तेलुगू देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था।

यह मोर्चा सरकार बनाने में तो सफल हुआ लेकिन जल्दी ही बिखर गया। आगे चलकर जनता दल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। वर्ष 1999 में हुए 13वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 16 दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन किया। वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस गठबंधन में नेशनल काँग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित कुछ अन्य छोटे दल भी जुड़े। वर्ष 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी यूपीए का गठन किया।

हालांकि नीति कार्यक्रम और सिद्धांत के आधार पर सबसे लंबा गठबंधन पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का रहा है लेकिन चूंकि अब वे न तीन में रह गए हैं न तेरह में, इसलिए उनकी गिनती तो छोड़िए चर्चा तक बेमानी हो गई है। हाल के वर्षों में केंद्र से लेकर राज्यों तक समय-समय पर बनने वाले गठबंधनों को देखकर लगता है कि गठबंधन बनते ही हैं बिगड़ने के लिए। विडंबना यह है कि गठबंधन बनाते समय जोर चेहरे पर रहता है, चाल और चरित्र पर नहीं। कई बार जनता को दिखाने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी बनाया जाता है पर वास्तव में साझा कार्यक्रम सत्ता की बंदरबांट का ही होता है।

● विपिन कंधारी

महाराष्ट्र में पवार परिवार में घमासान है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित ने पार्टी से बगावत कर दी है। अब पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। दोनों ही गुट विधायकों को अपने-अपने पाले में करने में लगे हैं। देश में इससे पहले भी बड़े राजनीतिक दलों में टूट हुई है और उसकी वजह भी परिवार या चाचा-भतीजे भी बने हैं। इन सियासी घटनाक्रमों का नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़ा है।

महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी पार्टी एनसीपी बिखर गई है। चाचा-भतीजे (शरद पवार और अजित पवार) की जंग अब और तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। दोनों ही गुट चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और पार्टी, सिंबल पर दावा ठोक दिया है।

फिलहाल, सुलह की उम्मीदें दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि, देश की राजनीति में परिवार में विवाद और पार्टियों में दोफाड़ होने का यह पहला घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले भी राजनीति के दिग्गजों के बीच रिश्तों में दगाबाजी देखने को मिली है। चाहे सोनिया-मेनका विवाद हो या सिंधिया और चौटाला परिवार के बीच विद्रोह। परिवारों में फूट-बगावत और दगाबाजी से सियासत गरमाती रही है।

हाल ही में शरद पवार और अजित पवार का विवाद सुर्खियों में है। लेकिन, इससे पहले चाचा-भतीजे चिराग-पशुपति कुमार पारस, अखिलेश यादव-शिवपाल यादव, प्रकाश सिंह बादल-मनप्रीत बादल, बाला साहेब ठाकरे-राज ठाकरे का विवाद भी चर्चा में रहा। इसके अलावा, मां-बेटे में विजयाराजे-माधव राव सिंधिया की कलह भी छिपी नहीं है। भाइयों में स्टालिन-अलागिरी, तेजप्रताप और तेजस्वी में सियासी जंग देखने को मिली है। हरियाणा में चौटाला फैमिली और सोनिया-मेनका गांधी विवाद भी राजनीतिक गलियारों में है।

सबसे पहले महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पर बात करेंगे। 2 जुलाई को अजित पवार ने अचानक महाराष्ट्र की राजनीतिक हवाओं का रुख बदल दिया। वे अपने भरोसेमंद नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत अन्य विधायक-एमएलसी के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। अजित को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। छगन भुजबल मंत्री बने और प्रफुल्ल के केंद्र सरकार में शामिल होने के कयास हैं। इस बगावत से शरद पवार की 25 साल पुरानी पार्टी टूट गई और साढ़े तीन साल बाद घर की कलह फिर उभरकर सामने आ गई। इससे पहले नवंबर 2019 में भी अजित ने बगावत की थी और भाजपा से हाथ मिला लिया था। हालांकि, तब शरद पवार डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अजित को मना

फैमिली में पवार की वॉर



देवीलाल चौटाला की विरासत पर परिवार में जंग

हरियाणा में चौटाला परिवार के चाचा-भतीजे की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। चौधरी देवीलाल की विरासत की जंग में पूरा कुनबा बिखर गया। कहते हैं कि एक जमाने में हरियाणा में देवीलाल की राजनीति में तूती बोलती थी। करीब 4 दशकों तक इनके परिवार ने हरियाणा की राजनीति को तय किया है। आज भी राज्य में मजबूत पकड़ बना रखी है। इनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी राजनीतिक मैदान में है। ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला की सियासी राहें जुदा हो गई हैं। ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत की लड़ाई सड़क पर है। देवीलाल की राजनीतिक विरासत को एक समय उनके बेटे ओमप्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओमप्रकाश पहली बार 1989 से 91 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में देवीलाल लोकसभा चुनाव हारे और उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओमप्रकाश चौटाला ने भाजपा की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2001 में देवीलाल का देहांत हो गया।

लिया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन, इस बार हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। अब खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है और पार्टी-सिंबल पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है।

बिहार में लोक जन शक्ति पार्टी पर अधिकार की लड़ाई जून 2021 में सामने आई। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के एक साल के भीतर ही परिवार में पार्टी पर कब्जे की जंग देखने को मिली। दरअसल, जब रामविलास केंद्र की सियासत किया करते थे तो बिहार के राजनीतिक फैसले पशुपति पारस लिया करते थे। भाई के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस एक्टिव हुए और एलजेपी के छह में से पांच सांसदों को अपने पाले में किया और भतीजे चिराग पासवान का तख्तापलट कर दिया। पशुपति ने संसदीय दल के नेता के पद के साथ-साथ पार्टी पर भी कब्जा जमा लिया है। हालांकि, रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने चाचा के सामने संघर्ष का बिगुल फूँका है। फिलहाल, पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब चर्चा है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में चिराग का भी समायोजन किया जा सकता है। दरअसल, एलजेपी में बगावत की एक बड़ी वजह रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत पर कब्जे को लेकर परिवार का अंदरूनी विवाद भी था। यही वजह है कि चिराग के खिलाफ उनके चाचा

पशुपति और रामविलास पासवान के बड़े भाई के लड़के प्रिंस राज ने भी बागी रुख अपना लिया था। यहां तक कि रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर क्षेत्र पर दावे को लेकर दो गुट आमने-सामने हैं।

उप्र की पॉलिटिक्स में सुखियों में रहने वाला यादव कुनबा भी विवादों से नहीं बच सका। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत पर काबिज होने के लिए चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच 2016 के आखिर में जंग छिड़ गई थी। दरअसल, सपा की कमान जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ में रही तब तक शिवपाल यादव ही पार्टी के सर्वेसर्वा हुआ करते थे। संगठन से लेकर सरकार तक के तमाम फैसले वही किया करते थे। ऐसे में शिवपाल खुद को मुलायम का उत्तराधिकारी समझ रहे थे, लेकिन मुलायम ने अपनी सियासी विरासत भाई को देने के बजाय साल 2012 में बेटे को अखिलेश यादव को सौंप दी। शिवपाल ने 2017 के चुनाव से ठीक पहले भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। चाचा-भतीजे की लड़ाई घर से सड़क तक आ गई। 30 दिसंबर 2016 को ऐसी भी परिस्थिति बनी कि तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। वहीं, अखिलेश ने अगले 2 दिन बाद यानी 1 जनवरी 2017 को विशेष अधिवेशन बुला लिया, जहां मुलायम की जगह अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बाद में शिवपाल ने खुद की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। ऐसे में मुलायम सिंह कभी भाई तो कभी बेटे के साथ खड़े नजर आए।

पंजाब के कद्दावर नेता रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के परिवार में टूट राजनीतिक सुखियों में रही है। शिरोमणि अकाली दल में भी दोफाड़ हुआ था। पार्टी संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने बगावत कर दी थी। प्रकाश सिंह से नाराज होकर मनप्रीत अलग हो गए थे और अपनी अलग पार्टी



पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब बना ली थी। दरअसल, प्रकाश से भतीजे मनप्रीत के विद्रोह करने की वजह भी सत्ता की महत्वाकांक्षा ही थी। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का सवाल इतना बड़ा हुआ कि चाचा-भतीजे का रिश्ता छोटा पड़ गया। मनप्रीत के पिता गुरदास सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल सगे भाई थे। 1995 में पहली बार अकाली दल के टिकट पर मनप्रीत को विधायक चुना गया था। उसके बाद वो अकाली दल के टिकट पर 1997, 2002 और 2007 में भी गिद्दड़बाहा सीट से विधायक बने। उस समय की पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल और युवाओं के बीच मनप्रीत काफी लोकप्रिय थे। मनप्रीत 2007 की बादल सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। तब वह सरकार में मुख्यमंत्री के बाद नंबर-2 की हैसियत रखते थे। कहा जाता है कि नंबर-2 की हैसियत पर रखने वाले मनप्रीत जल्द ही नंबर-1 हो जाना चाहते थे। मनप्रीत भी प्रकाश सिंह बादल के बाद खुद को पंजाब के मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार मान रहे थे। इसी बीच, उन्हें भनक लग गई कि चाचा अकाली दल की कमान सुखबीर सिंह बादल के हाथ में सौंपने वाले हैं। कुछ ही समय में दोनों में दूरियां बढ़ हुईं। मनप्रीत का उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से विवाद

बढ़ने लगा। इस वजह से उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया। साल 2010 में मनप्रीत अकाली सरकार से बिल्कुल अलग हो गए।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम प्रमुख रहे एम करुणानिधि के 2018 में निधन के बाद राजनीतिक विरासत को लेकर घमासान देखने को मिला था। करुणानिधि के दो बेटे एमके अलागिरी और एमके स्टालिन में काफी समय तक अंदरखाने और बाहरी तौर पर संघर्ष चला। हालांकि, इस संघर्ष में छोटे बेटे स्टालिन हमेशा भारी पड़े। कहा जाता है कि स्टालिन, अलागिरी की तुलना में ज्यादा पढ़े-लिखे और कूटनीति में माहिर रहे हैं। इतना ही नहीं, करुणानिधि भी कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से अपनी विरासत स्टालिन को सौंपने का संकेत देते रहे। स्टालिन की चेन्नई इलाके में मजबूत पकड़ है, जबकि बड़े बेटे अलागिरी की मद्रुरै में। दोनों भाईयों के बीच विवाद की शुरुआत तो जनवरी 2014 में ही चरम पर पहुंच गई थी। तब द्रमुक प्रमुख ने अलागिरी को पार्टी से निकाल दिया था। 2016 में उन्होंने अपने छोटे बेटे एमके स्टालिन को सियासी वारिस घोषित कर दिया था। करुणानिधि पांच बार मुख्यमंत्री भी बने।

● इन्द्र कुमार

बिहार में तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल में भी पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कुनबा में भी विवाद और मतभेद उभरकर सामने आए थे। साल 2021 में लालू के दोनों बेटों तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच जगदानंद सिंह को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर घमासान हो गया था। दोनों भाईयों ने एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर माहौल को और गरमा दिया था। दरअसल, जगदानंद सिंह ने राजद के छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया था। जबकि आकाश को तेजप्रताप ने नियुक्त किया था। वहीं, तेजस्वी ने आकाश की जगह गगन यादव को छात्रसभा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसी बात को लेकर दोनों भाईयों में विवाद बढ़ा और घर में मतभेद बढ़ गया। बता दें कि जगदानंद सिंह को लालू का करीबी माना जाता है। वे तेजस्वी के भी उतने ही खास माने जाते हैं। जबकि तेजप्रताप की जगदानंद सिंह से नहीं बनती है। कहा जाता है कि लालू परिवार पर जब भी मुश्किलें आईं, तब जगदानंद सिंह साथ खड़े दिखे। लालू जब जेल में थे, तब तेजस्वी को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना किसी चुनौती से कम नहीं था और ये काम जगदानंद सिंह ने बखूबी निभाया। जगदानंद सिंह को लेकर विवाद में तेजस्वी ने तेजप्रताप को अनुशासनहीनता पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे दी थी। बाद में लालू ने दोनों बेटों को दिल्ली बुलाया और सुलह करवाई थी।

देशभर की राजनीति में महाराष्ट्र अनोखे राजनीति गठबंधनों वाला इकलौता राज्य बन गया है। वहां अब देश के दो बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन दो राजनीतिक दलों के दो गुटों के साथ हैं। भाजपा के साथ शिवसेना का शिंदे

गुट है, तो कांग्रेस के साथ उद्धव वाली शिवसेना का गुट। इसी तरह भाजपा के साथ अजित पवार वाली एनसीपी है, तो कांग्रेस के साथ शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी धड़ा।

शायद ही दुनिया की राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण मिले। महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जरूरतें पूरी करने के लिए शिवसेना के बाद भाजपा ने शरद पवार की एनसीपी में भी सेंध लगा दी और अजित पवार को शरद पवार जैसे अनुभवी नेता से 8 अन्य विधायकों के साथ छीन लिया। इसका नतीजा यह निकला है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। शिंदे अजित को कतई पसंद नहीं करते, लिहाजा अब उनके ही खेमे में हलचल मच गई है।

भाजपा ने हाल के वर्षों में चुनाव में हारकर सरकार नहीं बना पाने के बावजूद विपक्षी दल की सरकार बनने पर उसके सदस्यों को तोड़कर अपनी सरकार बना लेने की परंपरा कायम कर दी है। हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण दिखे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद भाजपा के लिए भी दिक्कतें पैदा हुई हैं, क्योंकि उसके अपने ही गठबंधन के बीच इससे दरार बन गई है। यही नहीं चाचा शरद पवार से अलग हुए भतीजे अजित पवार एनसीपी में दो-फाड़ करने के 20 दिन बाद भी अपने गुट को एनसीपी का असली धड़ा बना पाने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके लिए उन्हें 36 विधायकों की जरूरत है। पार्टी में टूट के बाद 82 साल के शरद पवार ने जिस तरह मैदान में डटे रहने का संकल्प लिया, उससे साफ है कि एनसीपी में शरद पवार को किनारे करना आसान काम नहीं है। अभी भी एक लोकसभा सदस्य को छोड़कर पूरा संसदीय दल शरद पवार के साथ है और पार्टी का अधिकांश हिस्सा भी उनके साथ खड़ा दिखता है। ऐसी स्थिति में भाजपा-शिंदे सरकार में मंत्री बन चुके अजित पवार के लिए राह उतनी आसान नहीं है। जनता अजित पवार के इस कदम को कैसे देखती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक जनता का जो रुख सामने आया है, उससे लगता है कि उसकी सहानुभूति शरद पवार के साथ ज्यादा है। बहुत-से जानकार मानते हैं कि भाजपा भले दूसरे दलों को तोड़कर खुद को मजबूत कर रही है, लेकिन जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जा रहा। इस तरह की राजनीति करने का चुनावों में उसे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।



अनोखे गठबंधनों वाली सरकार

शरद पवार की पावर

शरद पवार भारतीय राजनीति में चाणक्य वाली छवि रखते हैं। बेशक अजित पवार ने इस बार उन्हें अपने विद्रोह से हैरान किया, लेकिन शरद पवार को यह तो पता ही था कि भतीजा उनसे दगा कर सकता है। यही कारण था कि जब उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो उनके साथ अपने विश्वस्त प्रफुल्ल पटेल को भी यही पद दिया। यहां तक कि दिल्ली में इसके बाद जब एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब दीवार पर लगाए गए पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल की फोटो तो थी, अजित पवार की नहीं थी। हो सकता है, शरद पवार को यह उम्मीद न रही हो कि प्रफुल्ल भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। इसके बाद मुंबई में जब अजित पवार ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए बैठक बुलाई, तो उसमें उन्होंने सीधे शरद पवार पर हमला कर दिया। उन्हें यह भी सलाह दे डाली कि यह उनकी रिटायरमेंट का समय है। हालांकि शरद पवार ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि न मैं टायर्ड हूँ, न रिटायर्ड हूँ। जनता में भी अजित पवार की इस बात का कुछ अच्छा संदेश नहीं गया और यह माना गया कि अजित पवार उस व्यक्ति से यह गुस्ताखी कर रहे हैं, जिसने उन्हें बनाया और आगे बढ़ाया।

महाराष्ट्र लोकसभा की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम है; क्योंकि वहां 48 सीटें हैं। सन् 2019 के चुनाव में भाजपा ने 23 सीटें जीती थीं, जबकि अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटें। एक साल पहले शिवसेना में टूट हो गई और सदस्य भी बंट गए। एनसीपी को चार, जबकि कांग्रेस, एआईएमआईएम, निर्दलीय को एक-एक सीट मिली थी। अब सारा परिदृश्य बदल चुका है और शिवसेना और एनसीपी का एक-एक धड़ा क्रमशः भाजपा और कांग्रेस के साथ है। महाराष्ट्र की इस उठापटक के बाद कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी दल बन गई है, जिसके पास सबसे ज्यादा 45 विधायक हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास बड़े कद का कोई मराठा नेता नहीं है, जो उसको विधानसभा में

अपने दम पर बहुमत दिला सके। लिहाजा उसने पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़ने का रास्ता चुना, ताकि महाराष्ट्र में बिखरे रूप से उसको आधार मिल सके। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों के मुताबिक, अजित पवार महत्वाकांक्षी नेता हैं। लिहाजा उनकी नजर भाजपा के साथ रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगी। ऐसे में उनका शिंदे ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी टकराव होगा। उपमुख्यमंत्री तो वह महाविकास अघाड़ी सरकार में भी थे। सत्ता में आने के बाद अजित को अपने गढ़ पुणे में जिस शासन आपल्य दारी कार्यक्रम के तहत सरकार में दूसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाना था, वह कार्यक्रम भी शिंदे सरकार ने 13 जुलाई को स्थगित कर दिया। कार्यक्रम की अगली तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। लिहाजा इसे अजित पवार के लिए झटका ही माना जाएगा; क्योंकि उनके शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद ही सारी उथल-पुथल शुरू हुई है। भाजपा अब महसूस कर रही है कि अजित पवार के उसके साथ आने से कुछ ऐसी पेंचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जिन्हें निपटाना आसान नहीं होगा।

अजित पवार के सामने अब दोतरफा विरोध है, जिससे उन्हें पार पाना है। सरकार से बाहर उन्हें शरद पवार की जनता में पैठ से पार पाना होगा। दूसरे सरकार के भीतर मुख्यमंत्री शिंदे के विरोध से भी निपटना होगा, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होते समय कहा था कि वह अजित पवार के कारण उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं। अब जबकि अजित पवार उनके नेतृत्व वाले भाजपा के दबदबे वाली सरकार में ही शामिल हो चुके हैं, तो शिंदे का असहज होना समझ भी आता है। शिंदे की अजित के लिए कटुता आसानी से खत्म हो जाएगी, ऐसा दिखता नहीं है। दूसरे शिंदे पर अपने ही विधायकों का दबाव है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। शिंदे के लिए यह दिक्कत और विरोध अजित पवार के सरकार में शामिल होने से ही शुरू हुआ है, लिहाजा उनकी उनके प्रति तलखी और बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।

● बिन्दु माथुर

राजस्थान की राजनीति में इस बार भ्रष्टाचार से ज्यादा ओबीसी आरक्षण मुद्दा बन रहा है। इस कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने-अपने दावे कर रहे हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, वहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना की मोदी से मांग कर अपने को ओबीसी जातियों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा ने घोषणा की है कि राजस्थान में सत्ता आने पर राजस्थान के आठ आदिवासी जिलों में आरक्षण से वंचित 93 जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल भाजपा का मकसद राजस्थान की उन 90 से ज्यादा जातियों को साधना है जो ओबीसी वर्ग से आती हैं। भाजपा राजस्थान में ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए आरक्षण के मामले को तूल देने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान की आबादी में 55 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय की है। ओबीसी समुदाय का कम-ज्यादा प्रभाव राजस्थान की लगभग सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर है। सामान्य ही नहीं एससी-एसटी के लिए आरक्षित ज्यादातर सीटों पर भी ओबीसी मतदाता ही निर्णायक भूमिका में हैं।

दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मतदाताओं को याद दिला रहे हैं कि 1998 में जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी था। उन्होंने ही अनुसूचित जाति का आरक्षण 8 से बढ़ाकर 16 फीसदी किया और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 6 से बढ़ाकर 12 फीसदी किया था। गहलोत राजस्थान के ओबीसी मतदाताओं को यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर वह ओबीसी के लिए आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। भाजपा भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का भरोसा राजस्थान के ओबीसी मतदाताओं को दे रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने घोषणा पत्र में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का वादा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अशोक गहलोत भी राज्य में ओबीसी वोटर्स की ताकत को समझ रहे हैं इसलिए अशोक गहलोत ने कहा है कि ओबीसी जाति के हर पहलू



मुद्दा बना ओबीसी आरक्षण

प्रदेश में 59 सीटें हैं रिजर्व

राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन ज्यादातर सीटों पर चुनाव में ओबीसी वर्ग के वोट ही निर्णायक स्थिति में हैं। ओबीसी वर्ग का वोट एकतरफा जिस पार्टी को पड़ता है, जीत उसी की होती है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा गूज ओबीसी आरक्षण की सुनाई दे रही है। 2018 के चुनाव में भाजपा को 38 रिजर्व सीटों पर हार के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एससी और एसटी के लिए रिजर्व 59 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 59 में से केवल 21 सीटों पर ही जीत मिली। 2018 के चुनाव में भाजपा ने एससी रिजर्व सीटों में से सिर्फ 12 और एसटी रिजर्व सीटों में सिर्फ 9 सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस ने एससी की 19 और एसटी की 12 सीटों पर जीत हासिल की। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से 34 विधायक और 4 सांसद तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से 33 विधायक और 3 सांसद हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को लोकसभा और विधानसभा के साथ नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थानों में आरक्षण हासिल है। ओबीसी वर्ग को नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में 21 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इस वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को नगरीय निकायों और पंचायतहराज संस्थाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

पर वह बारीकी से विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण हो। अशोक गहलोत ने कहा है कि वो इस प्रयास में हैं कि ओबीसी का आरक्षण भी बढ़ जाए और अन्य वर्गों में असमानता का भाव भी न उत्पन्न हो।

इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की समस्या और बढ़ा दी है कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने में अनियमितता बरती जा रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भाजपा के **तमाम वरिष्ठ नेताओं** ने गहलोत सरकार पर निशाना साधकर ओबीसी वर्ग से भेदभाव के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में आदिवासी बहुल इलाकों के 8 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी) में शामिल हैं। टीएसपी क्षेत्र की जनसंख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है। इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था लागू है। यहां एसटी को सबसे ज्यादा 45 प्रतिशत और एससी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इन इलाकों में ओबीसी वर्ग के लोग भी रहते हैं लेकिन उनको टीएसपी आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी बहुल इलाके के 8 जिलों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू नहीं होने को भाजपा मुद्दा बना रही है और दावा कर रही है कि सरकार आने पर आदिवासी बहुल 8 जिलों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देगे। ओबीसी और आरक्षित इलाके भाजपा के लिए कितने महत्व के हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले छह महीने में इस क्षेत्र में तीन रैलियां कर चुके हैं।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

लो कसभा चुनाव से पहले उग्र में बहुत भारी उलटफेर हो रहा है। हालांकि विधानसभा चुनावों का लोकसभा चुनावों पर ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन उग्र विधानसभा चुनाव नतीजों से भाजपा सचेत हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भले ही उसका वोट 39 प्रतिशत से बढ़कर 41.29 और गठबंधन का 45 प्रतिशत हो गया था, लेकिन उसकी सीटें घटी हैं। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों बढ़े हैं। भाजपा बारीकी से अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि समाजवादी पार्टी को यादवों के साथ-साथ गैर यादव पिछड़ी जातियों का भी समर्थन मिला। इसकी बड़ी वजह थी जाति आधारित छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन और विधानसभा चुनावों के वक्त भाजपा के कई विधायकों और मंत्रियों का पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले जाना।

2017 में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी भाजपा के साथ थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह सपा के साथ थी। इसके अलावा केशव देव मौर्य के महान दल, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, कृष्णा पटेल के कमरावादी अपना दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ भी सपा ने गठबंधन किया था। इन सभी छोटी पार्टियों का कुछ-कुछ सीटों पर जातिगत आधार है। नतीजा यह निकला कि सपा गठबंधन को 36 प्रतिशत वोट और 125 सीटें मिलीं। इनमें से सपा को 111 सीटें और 14 सीटें गठबंधन के सहयोगियों को मिलीं।

सपा की सहयोगी सुहेलदेव समाज पार्टी ने छह और राष्ट्रीय लोकदल ने आठ सीटें जीती, कमरावादी अपना दल की एक उम्मीदवार सपा टिकट पर जीती, जबकि महान दल ने भी दो सीटों पर सपा टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह कोई सीट नहीं जीत पाई। भले ही सपा के सहयोगी दलों ने कुल मिलाकर सिर्फ 14 सीटें जीती थीं, लेकिन उनके साथ गठबंधन के कारण सपा को राज्यभर में गैर यादव पिछड़ों का समर्थन मिला। भाजपा का विश्लेषण यह था कि अगर यह गठबंधन लोकसभा चुनावों में भी बना रहता है, तो भाजपा को छह सात लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता था।

2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ सिर्फ संजय कुमार निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल था। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और संजय कुमार निषाद उग्र सरकार में मंत्री हैं। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ही इस बात को समझ लिया था, इसलिए इन दोनों दलों को अपने साथ गठबंधन में रखने के लिए भाजपा ने 14 सीटों पर अपने विधायकों का टिकट काट दिया था। नतीजे भी शानदार मिले थे, अनुप्रिया

भाजपा का ऑपरेशन लोटस



रंग बदलती रही है ओमप्रकाश राजभर की राजनीति

राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे कयासों को सुहेलदेव भासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सही साबित करते हुए एक बार फिर भाजपा का सहयोगी दल बनने का फैसला कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ओमप्रकाश राजभर का एनडीए का दामन थामना काफी अहम माना जा रहा है। जातीय दिग्गजों को साधकर भाजपा अब अपने पुराने वोटबैंक को साधने की कोशिश और एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। ओमप्रकाश राजभर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। राजभर ने एनडीए का हिस्सा होने के बाद कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है और हम दिल्ली में एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। ओमप्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत काशीराम के साथ की थी। 1981 में काशीराम से जुड़े और बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। हालांकि, भदोही जिले का नाम संत कबीर नगर रखे जाने पर मायावती के साथ विवाद होने पर 2001 में ओपी राजभर ने मायावती से अलग होकर भासपा का गठन किया लेकिन उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी। जहूराबाद सीट से राजभर तो जीतते रहे, लेकिन वोट कटवा के रूप में पहचाने जाने लगे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने के लिए महाराजा सुहेलदेव के नाम को जोड़कर पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रख दिया।

पटेल के अपना दल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 पर जीत हासिल की। जबकि निषाद पार्टी के भी छह विधायक जीते थे। अब भाजपा के सामने लक्ष्य साफ है कि समाजवादी पार्टी के साथ गैर यादव पिछड़े वर्ग को कैसे दोबारा एनडीए में लाया जाए। इसी लक्ष्य को साधकर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी को वापस लाया गया है। वह 2018 में नाराज होकर एनडीए छोड़ गए थे। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के साथ जाना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके लिए दूसरा झटका यह है कि महान दल ने भी सपा का साथ छोड़कर बसपा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।

भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले गैर यादव पिछड़ी जातियों को ज्यादा से ज्यादा अपने कुनबे में लाना चाहती है, ताकि 2019 में हुआ नुकसान 2024 में दोहराया न जाए। समाजवादी पार्टी के साथ जहां छोटी-छोटी पार्टियां जुड़ी थीं, वहीं भाजपा के कई गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेता

भी विधानसभा चुनावों के वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें भी वापस लाना शुरू कर दिया है, दारा सिंह चौहान से शुरुआत हो गई है। चुनाव के समय वह भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और वह समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए विधानसभा से ही इस्तीफा दे दिया है। गत दिनों वह अमित शाह से मिले और तुरंत विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरह योगी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बना दिया जाएगा। वह पिछली योगी सरकार में भी मंत्री थे, भाजपा उन्हें घोसी सीट से लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकती है। दारा सिंह 1996 से 2006 तक राज्यसभा और 2009 से 2014 तक बसपा के लोकसभा के सदस्य रहे हैं।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

चक्रव्यूह में नीतीश

आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कल तक भतीजे को आगे बढ़ाने की बात करने वाले नीतीश कुमार के सामने अब एक नई

चुनौती आ गई है। करप्शन, कम्यूनलिज्म और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में फंसने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराएंगे? क्या तेजस्वी

यादव से नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे? क्या तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाएगा?

2017 में महागठबंधन की सरकार थी तब तेजस्वी उपमुख्यमंत्री थे। उस समय रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार के यहां जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही थी। तेजस्वी का भी नाम इस घोटाले में आया था। तब नीतीश ने तेजस्वी को सफाई देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी। इसके बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दिया था। इसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई थी। अब फिर से वही परिस्थिति बनती दिख रही है। बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है। उसी के समर्थन से नीतीश मुख्यमंत्री हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि वह केंद्र की सियासत में जा सकते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आरजेडी में जेडीयू के विलय की भी चर्चा है। इन दिनों नीतीश अपने विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों से वन-टू-वन मीटिंग भी कर रहे हैं। इन सबको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2005 में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 1999 में जीतन राम मांझी लालू प्रसाद की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। उस समय एक डिग्री घोटाला हुआ था। उस घोटाले में उनका नाम आया था। इस्तीफे के बाद में वह इस मामले में आरोप मुक्त हो गए थे। तब नीतीश ने उन्हें दोबारा मंत्री बनाया था।



बिहार में सिर्फ एक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद...नीतीश कोई फैक्टर नहीं

उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा विपक्ष मानते हैं। उनका दावा है कि लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक तोड़ दिया तो लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबसे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से बिहार के लव-कुश, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भाजपा के साथ आ गए हैं। 2024 में देश और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। फिर बिहार आगे बढ़ेगा। वह कहते हैं कि भाजपा संगठन की पार्टी है। नेता-कार्यकर्ता को अलग-अलग काम दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता 24x7 वाले हैं। हमारे प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव हैं। लालू के वोट बैंक में संघमारी करेंगे तो लोकसभा की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार की इमेज थी। उनकी सुप्रीम पावर जबरदस्त थी। अब नीतीश कुमार की इमेज खराब हो गई है। वे बूढ़े हो गए हैं। बुढ़ापा साफ दिख रहा है। अब तो उन्हें याद भी नहीं रहता। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं रहे। इस बार उनका खाता नहीं खुलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, तब से बिहार के लव-कुश, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भाजपा के साथ आ गए हैं। इतना स्पष्ट है कि पहले 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। फिर 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। देश और बिहार में एक सरकार होगी तो बिहार दोगुनी गति से आगे बढ़ेगा।

2008 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। तब रामानंद सिंह मंत्री थे लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा था। मामला साल 1990 का था, तब निगरानी ब्यूरो ने उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी। एक समय आरएन सिंह मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूएल टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी की पाइप की खरीदारी थर्मल पावर स्टेशन के लिए की थी। इस्तीफा देने के बाद मामले में जांच हुई, जेल गए, रिहा हुए और मामला खत्म हुआ। फिर दोबारा बिहार सरकार में मंत्री बने थे। 2011 में भी बिहार में एनडीए की सरकार

थी। नीतीश मुख्यमंत्री थे व दूसरी बार एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 2011 में ही कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद मंत्री रामाधार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। चुनाव के समय उन पर दंगा फैलाने का आरोप था। मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था।

2015 में नीतीश सरकार में मंत्री रहे अवधेश कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते पकड़े गए थे। स्टिंग ऑपरेशन में चार लाख रुपए घूस लेते वह पकड़ाए थे। 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 बच्चियों से हुए यौनशोषण के मामले में सीबीआई जांच के खुलासे के बाद मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। 2020 में एनडीए सरकार बनने पर मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे उन्हें तीन दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। वह भर्ती घोटाले में आरोपी थे। मेवालाल चौधरी पर सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नियुक्ति घोटाले में मामला दर्ज हुआ था। उनके कुलपति रहते कृषि विश्वविद्यालय में साल 2012 में सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की बहाली हुई थी। बताया जाता है कि उस नियुक्ति में धांधली की गई थी। 2022 में महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिक मास्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा था। वे अपहरण केस को लेकर वारंट विवाद में घिरे थे। जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था उसी दिन उन्होंने राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। इतना ही नहीं कार्तिक कोर्ट की नजर में आठ साल से फरार थे।

● विनोद बक्सरी

सो वियत संघ के विघटन के बाद से रूस कमजोर होता गया और चीन आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। इस दौर में रूस और चीन के संबंध सुधरते गए परंतु रूस ने भारत की सहायता कर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का निरंतर प्रयास किया। यह स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने तक बनी रही। रूस ने भारत को एस-400 जैसी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दी है।

पिछले दिनों रूस में वैंगनर समूह के सैन्य विद्रोह की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया। जितनी तेजी से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की, उतनी ही तेजी से शांत भी हो गई। इस तत्काल शांति के पीछे सौदेबाजी की खबरें हैं। बाखमुट की लड़ाई में रूसी विजय के नायक रहे वैंगनर के मुखिया येगवेनी प्रिगोजिन ने इस विद्रोह के लिए रूसी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में खबरें आती रहीं कि पुतिन की बीमारी के दौरान ये दोनों अमेरिका से कोई समझौता चाहते थे। इसलिए अटकलें तेज हैं कि क्या प्रिगोजिन के विद्रोह को पुतिन का मौन समर्थन था ताकि क्रेमलिन में पुतिन की नीतियों से असहमत गुट को किनारे लगाया जा सके? चूंकि पुतिन लंबे समय तक खुफिया अधिकारी रहे हैं तो ऐसी अटकलों को बल मिलना स्वाभाविक है।

सच जो भी हो प्रिगोजिन के नाटकीय विद्रोह के दो प्रत्यक्ष परिणाम निकले। पहला यह कि वैंगनर समूह के खतरनाक लड़ाकों की बेलारूस में तैनाती से पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ गया। पोलैंड और लिथुआनिया ने इस खतरे को लेकर बयान जारी किए हैं। दूसरा यह कि रूसी सत्ता के गलियारों में सब कुछ सामान्य नहीं और गुटबाजी बढ़ रही है। पुतिन के लंबे कार्यकाल में रूस चेचन्या और दागोस्तान में विद्रोही आंदोलनों को शांत करने, जार्जिया से दक्षिण ओसेटिया और अबकाजिया को अलग कराने, क्रीमिया को रूस में शामिल करने जैसी सैन्य सफलताएं हासिल कर चुका है। हालांकि, पश्चिम द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सैन्य-वित्तीय मदद से यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने पर रूस में एक राजनीतिक धड़ा सहज नहीं है।

प्रिगोजिन के विद्रोह का कुछ घंटों में भले ही नाटकीय पटाक्षेप हो गया हो, परंतु इसने रूस जैसे अनुशासित देश की आंतरिक स्थिरता पर प्रश्न चिह्न अवश्य लगा दिया है। अगर रूसी सरकार में कुछ तत्व पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हैं तो यह और भी गंभीर विषय है, क्योंकि यह रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों को विद्रोह एवं आंदोलन के माध्यम से अस्थिर करने की पश्चिमी देशों की नीति और क्षमता दोनों का परिचायक है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो के भारी दखल के चलते रूस के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ाते जाने के अलावा कोई चारा नहीं



रूस पर निर्भरता की समीक्षा का समय

अमेरिका का साथ भी जरूरी

अमेरिका महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार देशों के आंतरिक मामलों पर प्रवचन देने की अपनी आदत से भी बाज नहीं आ रहा। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर शरारत भरा एक सवाल पूछने वाली एक पत्रकार की भारतीयों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर आलोचना होने पर व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक कड़वा बयान है। यह समझना भी आवश्यक है कि अमेरिका में वोक कल्चर के नाम पर उपज रही एक अपसंस्कृति, जो छोटे बच्चों को भी यौन वस्तु की तरह देखती-दिखाती है, सांस्कृतिक रूप से उतना ही बड़ा एक खतरा है जितना कि चीन हमारे लिए सैन्य खतरा है। पुतिन के नेतृत्व में रूस इस अपसंस्कृति के विरोध में खड़ा है और उसका पतन अमेरिका की इस सांस्कृतिक विकृति को बेलगाम कर देगा। रूस-चीन का मजबूत होता गटजोड़ अमेरिका को भारत पर सामरिक रूप से अधिक निर्भर बनाता जाएगा। यदि रूस को यूक्रेन युद्ध में असफलता मिलती है तो पुतिन का पतन तय है। इन स्थितियों में भारत का सामरिक महत्व और कद बढ़ेगा। इसके बावजूद भारतीय नीतिकारों के समक्ष शक्ति संतुलन बनाए रखने को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं।

बचा। दोनों के संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसने एशिया के पारंपरिक भू-राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ दिया है। जब से माओ ने सोवियत संघ से टकराव का रास्ता अपनाकर कम्युनिस्ट चीन की नीतिगत स्वायत्तता पर जोर डाला था तब से चीन-रूस के संबंध तनावपूर्ण ही रहे थे। 1971 में चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सेना इसीलिए नहीं भेज पाया था, क्योंकि उत्तर से रूसी हमले का खतरा था।

सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस कमजोर होता गया और चीन आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। इस दौर में रूस और चीन के संबंध सुधरते गए, परंतु रूस ने भारत की सहायता कर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का निरंतर प्रयास किया। यह स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने तक बनी रही। रूस ने भारत को एस-400 जैसी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दी, जिसकी तैनाती चीनी सेना की रॉकेट फोर्स की भारत के ऊपर बढ़त को संतुलित करने के लिए की गई। गलवन में भारत-चीन सैन्य झड़प के बाद रूस द्वारा भारत को शीघ्रता से जरूरी सैन्य साजोसामान उपलब्ध कराया गया, पर बाइडन प्रशासन की आक्रामक नीतियों ने रूस को पूरी तरह चीनी खेमे में धकेल दिया है। स्थिति यह हो गई है कि रूसी युद्धपोत ताइवान के पास चीनी युद्धपोतों के साथ आक्रामक गश्त लगा रहे हैं।

आज यह एक बड़ा प्रश्न उभर रहा है कि भारत आपात स्थितियों विशेषकर चीन से टकराव की स्थिति में रूस पर कितना निर्भर रह सकता है? सामान्य स्थितियों में भी रूस से आने वाले सैन्य साजोसामान के भारत पहुंचने को लेकर विलंब की शिकायतें रही हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी रक्षा उत्पादक क्षेत्र पहले से ही दबाव में है। वहीं, चीन से भारत का तनाव घट नहीं रहा है। अमेरिका से हमारे सैन्य रिश्ते अवश्य सुधर रहे हैं, किंतु उनकी प्रकृति सामरिक महत्व की दूरगामी सैन्य परियोजनाओं पर अधिक केंद्रित है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता है। यह स्थिति रातोंरात नहीं बदली जा सकती। चीन के बढ़ते खतरे को लेकर अमेरिका बवाड जैसे मंच को सक्रिय बनाने के अलावा भारत के साथ सामरिक साझेदारी पर गंभीरता से काम भी कर रहा है, लेकिन संकल्प के स्तर पर अभी भी वह कहीं न कहीं पसोपेश में है।

● ऋतेन्द्र माथुर

भारत-फ्रांस के रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह रही है कि दोनों देशों ने इस मित्रता को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने में तत्परता दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का कई वैश्विक मुद्दों पर एक जैसा दृष्टिकोण इसकी पुष्टि करता है। भारत की किसी भी महत्वपूर्ण पहल पर फ्रांस का अक्सर अविलंब मिलने वाला समर्थन भी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है।

इस समय अंतरराष्ट्रीय ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे अनिश्चितता भी बढ़ रही है। इस बढ़ती अनिश्चितता में विभिन्न देशों के बीच नई-नई साझेदारियां और नए-नए मंच आकार ले रहे हैं। इसमें भारत विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज दुनिया का लगभग हर छोटा-बड़ा देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यस्त कार्यक्रम से भी इसका अनुमान लगता है कि दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपने संबंधों को नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के ऐतिहासिक रूप से सफल राजकीय दौर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी सप्ताह के अंत में फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। दो कारणों से इस दौरे की महत्ता और बढ़ गई है। एक तो मोदी को फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय दिवस-बास्टील डे के अवसर पर आमंत्रित किया। ऐसा आमंत्रण विरले ही राष्ट्राध्यक्षों को मिलता है और दूसरा यही कि यह द्विपक्षीय **रणनीतिक साझेदारी** की रजत जयंती वर्ष में आयोजित हुआ।

भारत और फ्रांस के संबंध अतीत से ही मधुर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे से लेकर परमाणु शक्ति जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित एवं विभाजित विषयों पर भी फ्रांस भारत के रुख का समर्थन करता रहा। वीटो शक्तिसंपन्न देशों में फ्रांस ही वह पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। पिछली सदी के अंतिम दशक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी ने गति पकड़ी। परमाणु परीक्षणों के बाद जब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने भारत को प्रतिबंधों से लाद दिया, तब उस दौर में भी फ्रांस भारत के प्रति अपेक्षाकृत नरम बना रहा। भारत-फ्रांस के रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह रही है कि दोनों देशों ने इस मित्रता को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने में तत्परता दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का कई वैश्विक मुद्दों पर एक जैसा दृष्टिकोण इसकी पुष्टि करता है। दोनों ही नेता किसी भी साझेदारी में रणनीतिक स्वायत्तता को खासी महत्ता देते हैं। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद फ्रांस ने रूस को लेकर बहुत व्यावहारिक रुख दिखाया। भारत का रवैया भी ऐसा ही रहा। भारत की किसी भी महत्वपूर्ण पहल पर फ्रांस का अक्सर अविलंब मिलने वाला



मित्रता की मिसाल

विभिन्न पक्षों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी उद्योग जगत के दिग्गजों से मिले और उनसे भारत की विकास गाथा साझा करते हुए उसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया। फ्रांस की कई कंपनियां पहले से ही भारत में सक्रिय हैं, जिनका दायरा आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिख सकता है। पिछले कुछ समय से भारत ने विभिन्न पक्षों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर बात आगे बढ़ाई है। इसमें यूरोपीय संघ यानी ईयू को भी एक संभावित साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। सौर गठबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद के विरुद्ध अभियान को तेज करने जैसे मुद्दों पर पहले से चली आ रही सहमति को इस दौरे पर और विस्तार मिला है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों के लिए वीजे का दायरा भी बढ़ा दिया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भारी संख्या में पढ़ने के लिए जा रहे भारतीय छात्रों से मिलने वाला लाभ उठाने में अब यूरोपीय देश भी पीछे नहीं रहना चाहते। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी का यह रिश्ता रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मनाने के जश्न का अवसर बना और इसमें दोनों देशों के आगामी 25 वर्षों के रिश्तों की रूपरेखा भी तैयार हुई।

समर्थन भी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी भरा रवैया भी फ्रांस के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ।

फ्रांस भारत का एक अहम रक्षा साझेदार है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से इस साझेदारी को नया विस्तार भी मिला। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारत को यह

विचार करने पर विवश किया है कि किसी एक देश पर अतिशय सामरिक निर्भरता उचित नहीं। इसलिए भारत विभिन्न देशों के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें फ्रांस जैसे देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो न केवल अत्याधुनिक अचूक रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, बल्कि उन्हें उनकी तकनीक साझा कर भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने में भी कोई संकोच नहीं।

द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को और गहराई प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री के इस दौरे पर फ्रांस के साथ 24 से 30 राफेल-एम (मरीन) विमानों और तीन स्कापीन पनडुब्बियों के सौदे पर सहमति भी बनी। अमेरिका के सुपर हार्नेट से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद राफेल-एम भारतीय नौसेना की पसंद बने हैं तो इसके पीछे भी कुछ तार्किक वजह हैं। निसंदेह, अमेरिकी सुपर हार्नेट बहुत सक्षम विमान है, लेकिन राफेल चूँकि पहले से ही भारतीय सैन्य प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं तो उस शृंखला के विमानों की कंपैटिबिलिटी, प्रशिक्षण और रखरखाव अपेक्षाकृत आसान होगा। साथ ही अमेरिकी तकनीक की तुलना में फ्रांसीसी उपकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में भी कहीं अधिक सक्षम हैं तो यह सौदा हमारी नौसेना के लिए उपयुक्त है।

आइएनएस विक्रांत पर इन विमानों की तैनाती भारतीय नौसैन्य बेड़े की मारक क्षमताओं को बढ़ाएगी तो स्कापीन पनडुब्बियां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाएंगी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत और फ्रांस की साझा चिंता का मोर्चा है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के हितों को देखते हुए वे अलग-अलग मंचों पर साझेदारी भी बढ़ा रहे हैं। जहां फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर एक मोर्चा मजबूत कर रहा है तो अरब सागर में अपने हितों को देखते हुए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की तिकड़ी अपना रंग जमा रही है।

● कुमार विनोद

पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आकर हिंदू बन चुकी सीमा गुलाम हैदर अली के लिए हर शख्स के पास अपनी थ्योरी है। किसी के लिए जासूस, किसी के लिए अय्याश, किसी के लिए बेवफा बीवी, किसी के लिए काफिर, किसी के लिए खराब मां, और किसी के लिए प्यार में डूबी एक लड़की। आगे न जाने और क्या-क्या होंगी सीमा हैदर अली। वैसे भी औरतें तमाम उम्र किसी न किसी कसौटी पर परखी जाती ही हैं। आइए आज देखते हैं उन सभी कसौटियों को जिन पर परखी जा रही हैं सीमा हैदर अली-

एक सीमा कई रूप

जासूस- पाकिस्तान से कोई भारत के तीन आधार कार्ड, चार-पांच मोबाइल सिम, एक-दो टूटे-फूटे फोन के साथ भारत नेपाल के रास्ते होकर आए तो उसे बहू या दामाद नहीं माना जाएगा देश का। वो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। ऐसे कैसे कोई बिना वीजा के भारत में आकर रहने लग जाएगा और देश की मीडिया उसे स्टार बना देगी। जबकि अगर यही मामला पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी मीडिया उस शख्स को **स्टार नहीं बल्कि** सरबजीत बना देंगे। एक औरत जो जहीनियत से बात करती है, हिंदी-अंग्रेजी सब बोल लेती है, कम्प्यूटर चला लेती है, जिसका चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी में काम करता हो, उसकी बातों पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। जो बीमार बच्चों का वास्ता देकर भारत में घुसी हो उसे जासूस नहीं तो क्या बहू मान लेंगे! एक औरत जिसके चार बच्चे हों लेकिन जो उन चार बच्चों के होने के बाद भी, किसी और के प्यार के चक्कर में अपने शौहर को छोड़ दे उसे अय्याश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जिसे पति, बसी-बसायी गृहस्थी, घर-बार से कहीं ज्यादा अपने अरमानों की चिंता हो उसका चरित्र सही नहीं हो सकता। जो अपने पति को यूँ छोड़कर घर से भाग जाए उसे अय्याश औरत नहीं तो क्या सती सावित्री कहेंगे!

काफिर/मूर्तिपरस्त- एक सच्चे मुसलमान के लिए हाराम है मूर्ति को पूजना, तुलसी के पौधे



में जल चढ़ाना, राम नाम का जाप करना। सीमा हैदर अली जो मुस्लिम से हिंदू हो चुकी हैं वो अब वही सब करने लगी हैं जिसकी मनाही इस्लाम में है। पाकिस्तान की फेमिनिस्ट्स जो खुद को महिलाओं की मसीहा कहती हैं वो सब सीमा हैदर के हिंदू हो जाने से नाराज हैं। उनके लिए भी एक औरत का यूँ अपनी मर्जी से जीने का फैसला लेना कायराना हरकत से ज्यादा कुछ भी नहीं है।

बदचलन मां- हर समाज के कुछ तय नियम कायदे होते हैं। उनमें से जो सबसे अहम हैं वो हैं एक औरत का मां बन जाने के बाद बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना। अपनी तमाम कामनाओं को भूलकर बच्चे के लिए सोचना, उनके भविष्य को संवारना। अब सीमा जो अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर भारत आ गई हैं, वो भी एक शख्स के लिए जो सही से कमा नहीं रहा है, जो अमीर नहीं है, जिसके पास बड़ा मकान भी नहीं है वो उन चार बच्चों को कैसा भविष्य देगा? उन बच्चों को शायद उनका बाप एक बेहतर जिंदगी देता क्योंकि वो दुबई में नौकरी कर रहा है लेकिन सीमा ने अपनी खुशियों के सामने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा और वो सबकुछ छोड़ कर यूँ भारत आ गई, क्या ये एक अच्छी मां होने की

निशानी है?

प्रेमिका- पबजी खेलते हुए किसे लगा होगा कि उनको उनका सोलमेट यूँ इस एप्प पर मिल जाएगा। हिंदुस्तानी सचिन या पाकिस्तानी सीमा ने भी ये नहीं सोचा होगा लेकिन दिल को दिल की राह पता होती है। प्यार के आगे दुनिया की कौन सी दीवार टिकी है जो सीमा के आगे टिकती। दिल जब दिल को पुकारता है तो इंसान सिर्फ दिल की सुनता है, उसे दुनिया की रस्मों-रिवाज, दुनियादारी की आवाज नहीं सुनाई देती। उसे सिर्फ महबूब का साथ चाहिए होता है। सीमा को भी धन-दौलत नहीं बल्कि सचिन का प्यार से भरा दिल चाहिए और जो उसे आखिर मिल ही गया। सचिन के प्यार के रंग में वो कुछ इस कदर रंगी कि मुस्लिम से हिंदू हो गईं। अब वो खुद को सचिन से अलग सोच भी नहीं पाती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है- आई एम सचिन्स वाइफ, नॉट एनिवन एल्स!

आपके लिए सीमा हैदर अली और क्या हैं, बताइए। क्या आपको भी लगता है औरतें चाहे पाकिस्तानी हों या हिंदुस्तानी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेते ही उसकी जिंदगी उसकी नहीं होकर, टीआरपी और चटखारेदार खबर हो जाती है!

● ज्योत्सना अनूप यादव

जासूसी की दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहां

किसी कथित जासूस ने स्वयं के चलते जांच एजेंसियों का काम आसान किया हो। यहां तो सीमा हैदर ने स्वयं ही आवेदन दिया था। ऐसे में इतना तो तय है कि यदि सीमा हैदर जासूस है तो या तो उसकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई या ऐसा करके उसने जासूसी की दुनिया में कुछ अनोखा ही करने की ठानी है। सीमा हैदर के मामले में लूपहोल्स बहुत से हैं किंतु अभी तक जासूसी के ठोस प्रमाण हासिल करने में भारतीय जांच एजेंसियां विफल ही मानी जाएंगी। इस पूरे मामले में ऐसा प्रतीत

सवालोंने से भरा है सीमा हैदर का मामला

सामने लाए जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीमा हैदर का जो पीपली लाइव किया, उससे भी जांच एजेंसियों की भद पिटी है। सीमा हैदर भी जिस बेफिक्री से मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने उत्तर दे रही है, उससे उसके जासूस और माशूका होने पर जनता की राय बंटी हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाएंगी ही किंतु सीमा हैदर का भारत में प्रवेश करना ही सबसे बड़ा सवाल है जो अब तक अनसुलझा है।

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

D-10™ Hemoglobin Testing System For HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/F/A₂ testing using primary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 ✉ **Email : shbple@rediffmail.com**
☎ **Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687**

इस वर्ष अधिक मास या मलमास का महीना सावन के बीचों बीच पड़ रहा है। मलमास या अधिक मास के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि बारह महीनों के बीच तेरहवां महीना कहां से आया? इसकी शुरूआत कैसे हुई? इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? ऐसे प्रश्नों के साथ लोगों की धारणा है कि यह मास शुभ कार्य के आयोजन हेतु ठीक नहीं है। इसमें पूजा-पाठ या धार्मिक कथाओं का श्रवण किया जाता है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि कालगणना के हिसाब से भारतीय कैलेंडर में यह तेरहवां महीना क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या है?

अधिक मास का इतिहास पुराना है। यह मास मानव कृत व्यवस्था नहीं है बल्कि इसके पीछे ज्योतिष शास्त्रीय और प्राकृतिक योजना है। विश्व साहित्य के सर्वाधिक पुरातन ग्रंथ ऋग्वेद में अतिरिक्त मास का उल्लेख है। वेदांग ज्योतिष ने भी प्रत्येक पांच वर्षों में दो मास यानी ढाई-ढाई साल के अंतराल में एक-एक अधिक मास जोड़ दिया है। प्राचीन काल में मासों की गणना चंद्र से व वर्ष की गणना सूर्य से होती थी। चंद्र वर्ष में 354 दिन ही होते हैं, जो सौर वर्ष के 365 दिनों की तुलना में 11 कम पड़ते हैं। अतः यदि केवल चंद्र वर्ष की ही अभियोजना हो तो ऋतुओं को पीछे हटाना पड़ जाएगा। इससे ही कई देशों में अधिक मास की अभियोजना निश्चित हुई।

अधिक मास या मलमास के कई नाम हैं। काठक संहिता में इस मास को मलिम्लुच और वाजसनेयी संहिता में संसर्प या अहंसपति कहा गया है। कालांतर में पुराणों ने इस मास को भगवान विष्णु के नाम से पुरुषोत्तम मास की संज्ञा देकर मान्यता दी पर वैदिक साहित्य में तेरहवें मास के साथ जो भावना थी, वही भावना पुराणों के पुरुषोत्तम मास के साथ भी जुड़ी रही है। गृह्यपरिशिष्ट ने हर तीन संवत्सर बाद पड़ने वाले तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम दिया है कि मलिम्लुच मास मलिन है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है। इसलिए यह सभी कार्यों के लिए गर्हित (वर्जित) है। यहां तक कि यह देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए भी त्याज्य है।

सभी देशों में काल की मौलिक अवधियां प्रायः एक-सी होती हैं, जैसे- दिन, मास और वर्ष, जिसमें ऋतुएं भी हैं। यद्यपि काल की अवधियां समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अंतर पाया जाता है। दिनों की अवधियों, दिन के आरंभ और अंत के काल, ऋतुओं और मासों में वर्षों का विभाजन, प्रत्येक मास व वर्ष में दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मासों में अंतर है। वैज्ञानिक तथ्य है कि धुरी पर पृथ्वी के घूमने से दिन बनते हैं, जिसमें सूर्य के साथ पृथ्वी के जिस भाग का



मलमास क्यों आता है... ?

सभी देशों में काल की मौलिक अवधियां प्रायः एक-सी होती हैं, जैसे- दिन, मास और वर्ष, जिसमें ऋतुएं भी हैं। यद्यपि काल की अवधियां समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अंतर पाया जाता है।

जुड़ाव होता है, वहां दिन का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्र काल के बड़े मापक हैं। मास प्रमुखतः चंद्र अवस्थिति है और वर्ष सूर्य की प्रत्यक्ष गति है पर वास्तव में यह सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का भ्रमण है। कालगणना के इस क्रम को व्यवस्थित करने का भारत में वैज्ञानिक साधन अधिक मास है, जो प्रायः हर तीन साल बाद आता है।

मुसलमानों ने सूर्य अयनवृत्तीय वर्ष के विस्तार पर ध्यान न देकर और चंद्रमा को ही काल का मापक मानकर अपने हिसाब से समाधान कर लिया। उनका वर्ष विशुद्ध चंद्र वर्ष है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लामिक वर्ष केवल 354 दिन का हो गया और लगभग 33 वर्षों में उनके सारे त्योहार वर्ष के सभी मासों में घूम जाते हैं। दूसरी ओर प्राचीन मिस्र वालों ने चंद्र को काल के मापक के रूप में नहीं माना और उनके वर्ष में 365 दिन थे। मिस्र के लोगों

ने 30 दिनों के बारह मास में पांच अतिरिक्त दिन और स्वीकार किए हैं। उनके पुरोहित 3,000 वर्षों तक यही विधि मानते रहे। इस कारण उनके यहां अतिरिक्त वर्ष या मलमास नहीं होता। भारत में सभी संवत्तों में अधिक मास परिकल्पित है। 33 ईसा पूर्व में रचित एक पश्चात्कालीन रचना ज्योतिर्विदाभरण में कलियुग के उन छह व्यक्तियों के नाम आए हैं, जिन्होंने संवत चलाए। ये हैं- धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन एवं कल्कि।

श्राद्धविवेक की टीका में श्रीकृष्ण तर्कालंकार का कथन है कि जिस मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, ऐसा चंद्र मास ही मल मास कहलाता है। उत्तर भारत में मास में कृष्ण पक्ष पहले और शुक्ल पक्ष बाद में आता है। मास का अंत पूर्णिमा से होता है। पर अधिक मास में इससे ठीक विपरीत होता है। इसमें शुक्ल पक्ष पहले और कृष्ण पक्ष बाद में आता है और मास का अंत अमावस्या से होता है।

अधिक मास में धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने विभिन्न धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया है। काठक गृह्यसूत्र का कथन है कि चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत व विवाह सहित अन्य कृत्य अधिक मास में नहीं करने चाहिए। अधिक मास में न तो किसी नए व्रत का आरंभ होता है और न ही उद्यापन। पर नित्य और नैमित्तिक कृत्य, जैसे तीर्थस्नान और मृतक के लिए प्रेत श्राद्ध अधिक मास में भी किए जाते हैं। शव को श्मशान तक ले जाकर अंत्येष्टि करना, पिंडदान और अस्थि संचय अधिक मास में भी किया जाता है। नित्य किए जाने वाले पूजा-पाठ भी अधिक मास में होते रहते हैं। अधिक मास या मलमास में विष्णु सहस्रार्चन करना सर्वाधिक प्रशस्त है।

● ओम

सरकारी नौकरी



ऊ पर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और समय से पहले तथा भाग्य से अधिक न कभी किसी को मिला है और न मिलेगा। ये बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए ही नहीं हैं। अब रामलाल को ही देख लीजिए।

सरकारी नौकरी की आस लिए अपने जीवन के चौतीस बसंत पार कर चुके एमएससी प्रथम श्रेणी में पास पीएचडी उपाधिधारक डॉ. रामलाल चौधरी पिछले दिनों डूबे मन से तथा नहीं मामा से काना मामा भला सोचकर के कॉलेज में भृत्य के पद हेतु आवेदन पत्र भर दिया था। कुछ दिन बाद संविदा सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए भी आवेदन मंगाया गया। जब तक सांस है, तब तक आस है वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए डॉ. रामलाल ने

उसमें भी फार्म भरकर जमा कर दिया।

अप्रत्याशित ढंग से क्रमशः दोनों जगह से साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र रामलाल को मिला। साक्षात्कार आशानुरूप रहा। दोनों ही पदों के लिए उसका चयन हो गया।

परंतु हाय री किस्मत! सरकार और सरकारी नियमों के कारण डॉ. रामलाल चौधरी ने सहायक प्राध्यापक की बजाय उसी कॉलेज में भृत्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया क्योंकि यह पद स्थायी था और एक निश्चित वेतनमान पर नियुक्त था, जबकि सहायक प्राध्यापक का पद संविदा आधार पर था और सालभर बाद फिर से सड़क पर आ जाने का खतरा था।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था



जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था,
लव एट फर्स्ट साइट था।
नजरे उठने-झुकने में शराफत थी,
नूर सादगी संग ब्राइट था।
जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था,
जर्मी से जुड़े रहकर भी
आसमा औ चांद की हाईट थी,
सख्ती में दुआ औ स्नेह था,
फालतू खर्च में हाथ टाइट था।
जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था,
घर का खाना ही भाता था,
हर कोई रहता आता-जाता था,
पैसे कम संयुक्त परिवार था,
ज्यादा काम खाना हैल्थी डाइट था।
जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था,
एक चारपाई पर बैठ पड़ोस के,
सुलझ जाते थे सारे उलझे किस्से,
हर छोटे को बड़े का लिहाज था,
पड़ोसी मदद को हाजिर डे-नाइट था।
जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था,
हल्की-फुल्की जिंदगी सादगी भरी थी,
मेहमानों का आना खुशी की घड़ी थी,
खट्टी थोड़ी खुशियां मीठी थोड़ी फाइट थी,
लाइट सोच रख जीवन भी लाइट था।
जमाना पहले ब्लैक एन व्हाइट था...

- भावना अरोड़ा 'मिलन'

म धु! आज मैं तुम्हारे निर्णय को ही प्राथमिकता दूंगा। पापा अस्पताल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए मुझे बैंक में जमा एफडी तोड़ना है। यह तुम क्या कहते हो। कितने कष्ट से हम दोनों ने पैसे जमाकर भविष्य में मुन्ने की पढ़ाई के लिए एफडी खोला है और तुम।

मुन्ने की पढ़ाई के लिए धीरे-धीरे रुपए जमा कर लूंगा लेकिन इलाज के बगैर पिताजी अगर...। दीपक की आंखों में पानी भर आया। आज मां जीवित होती

खुद्दारी



तो...!

अरे रुको, मुझे मालूम है जब तुम तीन चार साल के थे और गीता दीदी छह साल की तभी मम्मी जी की मृत्यु हो गई थी बीमारी से।

तुम्हारे बक्से में रखा वह स्केच गवाह है तुम्हारे पिताजी ने कैसे तुम दोनों भाई-बहन की परवरिश की थी। मुझे भी एक खुद्दार पति की पत्नी की भूमिका निभानी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

- निर्मल कुमार दे

जै से-जैसे खेल जगत को अहमियत मिलने लगी, खिलाड़ियों के दिन फिर गए। अब खेल जगत अरबों-खरबों का साम्राज्य बन गया है और खिलाड़ी माया के स्वामी। हाल ही में फोर्ब्स ने खिलाड़ियों की आमदनी की जो सूची जारी की, उसके अनुसार विदेश में खिलाड़ियों ने खेल और विज्ञापन से इतनी कमाई की कि उनकी आमदनी की बराबरी, उद्योगपतियों की आमदनी के बराबर हो गई है। भारतीय खिलाड़ियों ने भी कमाया मगर विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले वे अभी भी उनीस ही हैं। आइए आज विश्व के कुछ सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची देखते हैं।

लियोनेल मेसी- अर्जेंटीना से आने वाले 35 वर्षीय लियोनेल मेसी को विश्व फुटबॉल जगत में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में एक गिना जाता है। वर्तमान में लियोनेल मेसी की ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड कमाई मिलाएं तो यह आंकड़ा कुल 1066.05 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। दिसंबर में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जीत दिलाने वाले मेसी फोर्ब्स की सूची में रोनाल्डो के बाद दूसरे स्थान पर हैं। विभिन्न ब्रांड से आकर्षक कमाई के साथ मेसी ने अक्टूबर में प्ले टाइम नाम से अपनी एक निवेश फर्म भी लॉन्च की है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो- वर्तमान में विश्व फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक। पुर्तगाल से आने वाले 38 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बाद जनवरी में सऊदी अरब के अल नासर क्लब में शामिल हुए रोनाल्डो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। 2017 के बाद पहली बार और कुल मिलाकर तीसरी बार रोनाल्डो 1115.30 करोड़ रुपए के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं।

किलियन म्बापे- फुटबॉल जगत में उभरता नाम किलियन म्बापे। केवल अपनी उत्कृष्ट खेल क्षमता और प्रतिभा में ही नहीं यह दुनिया भर में छाए हुए हैं, बल्कि पिछले साल कमाई सूची में 35वें नंबर पर रहने वाले म्बापे इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। सूची में 30 वर्ष से कम उम्र वाले एकमात्र सदस्य हैं। लगभग 820 करोड़ रुपए पारिश्रमिक वाले म्बापे की कमाई 984.05 करोड़ रुपए है। वे 2022 में फ्रांस की टीम में लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब से एक कदम दूर रह गए थे।

कैनलो आल्वरेज- मैक्सिको के मुक्केबाज। फोर्ब्स सूची में पांचवा स्थान। 902.05 करोड़ के साथ सूची में अकेले मुक्केबाज। रिंग में उतरते ही लाखों डॉलर कमाते हैं। रिंग के अंदर

सबसे अमीर खिलाड़ी



कमाई 820.03 करोड़ रुपए जबकि रिंग के बाहर वह करीब 82 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। बॉक्सर, स्पोर्ट्स ड्रिंक निर्माता याओका, फिटनेस ऐप आई कैन और गैस स्टेशन श्रृंखला जैसे ब्रांड से कैनलो जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी कपड़ों की लाइन और ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी हैं। सितंबर में, उन्होंने वीएमसी (एक डिब्बाबंद कॉकटेल ब्रांड) भी लॉन्च किया है।

स्टीफेन करी- अमेरिकी के 35 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफेन करी फोर्ब्स सूची में आठवें स्थान पर हैं। पिछले वर्ष जून में अपनी चौथी एनबीए चैंपियनशिप में, करी ने पहली बार एक वर्ष में 820.03 करोड़ का आंकड़ा छुआ। उनका 394.43 करोड़ रुपए का वेतन इस सीजन में एनबीए का उच्चतम वेतन था। बड़े ब्रांड्स के साथ साझेदारी और खुद के अच्छे निवेश के कारण करी की ऑन फील्ड (394.43 करोड़ रुपए) और ऑफ फील्ड (426.41 करोड़ रुपए) कमाई में खास बड़ा अंतर नहीं है, जो कि कम ही देखने को मिलता है।

लेब्रोन जेम्स- अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी, फोर्ब्स सूची में 979.95 करोड़ के साथ चौथे पायदान पर हैं। 38 वर्षीय जेम्स को बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता है। प्रभावशाली पोर्टफोलियो के शीर्ष पर,

लॉस एंजेलिस जेम्स आज के समय के शीर्ष एथलीट, सफल संस्थापक और निवेशक भी हैं। शायद इसीलिए, जेम्स को उद्यमशीलता की भावना का बेहतरीन प्रतीक भी माना जाता है।

फिल मिक्लसन- 52 वर्षीय गोल्फ खिलाड़ी इस सूची में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 869.23 करोड़ के साथ फोर्ब्स सूची में सातवें पायदान पर हैं। हालांकि, एलआईवी गोल्फ में शामिल होने के बाद से प्रायोजकों को छोड़ दिया है। फॉर वेलनेस के सह-संस्थापक मिक्लसन अमेरिका से हैं और उनकी कमाई का बड़ा माध्यम गोल्फ का मैदान ही है।

डस्टिन जॉनसन- गोल्फ के बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले डस्टिन जॉनसन ने फोर्ब्स की सूची में छठा स्थान हासिल किया है। 877.43 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष 10 की सूची में स्थान पाने वाले जॉनसन साल 2022 के 50 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में भी जगह नहीं बना सके थे। अमेरिका से आने वाले 38 वर्षीय जॉनसन की मदद एलआईवी के नो-कट प्रारूप से गार्टीशुदा नकदी ने भी की। साल 2023 की बात करें तो उन्होंने पांच एलआईवी आयोजनों में 27.06 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

● आशीष नेमा



...जब रेखा को झेलने पड़े थे दुनिया के ताने

फिल्म अभिनेत्री रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रही हैं। एक दौर में रेखा की पर्सनल लाइफ अक्सर बी-टाउन में चर्चा का विषय बनी रहती थी।

कभी किसी एक्टर संग उनके रिलेशनशिप की खबरें हों या फिर उनके पिता जेमिनी गणेशन संग उनके रिश्ते, एक्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। लेकिन फिर इस एवरग्रीन एक्ट्रेस की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई हैं।

रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही एक्ट्रेस के पति ने आत्महत्या कर ली। पति की मौत की खबर फैलने के बाद रेखा रातों-रात आम और खास सभी की नजरों में खलनायिका बन गईं। लोग उन्हें अलग-अलग नामों से पुकारने लगे। यहां तक कि बॉलीवुड में जो लोग पहले उनके आगे-पीछे घूमते थे, वह भी उनसे मुंह फेरने लगे।

बताया गया इंडस्ट्री पर कलंक

एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म मेकर सुभाष घई ने रेखा को इंडस्ट्री पर कलंक बता दिया था। इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके बाद शायद कोई भी किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। इतना ही नहीं फिल्ममेकर ने एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी अपनी राय साझा की थी। उन्होंने कहा था कि इस हादसे के बाद शायद कोई फिल्म मेकर अब उनके साथ काम भी न करना चाहे।

9 साल में पिता को खोया, 11 की उम्र में स्कूल छोड़ा...आज हैं देश के सबसे बड़े संगीतकार

ए आर रहमान आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में नाम कमा चुके हैं। वे आज म्यूजिक की दुनिया के रॉकस्टार हैं और दशकों से अपनी गायकी, गानों और संगीत से दिल जीत रहे हैं। वे देश की शान हैं, लेकिन जब वे 11 साल के थे, उन्हें मां के कहने पर पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि



पिता के निधन के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उनके नन्हे कंधों पर आ गई थी। वे प्योर टैलेंट हैं। उनके जब खेलने-कूदने के दिन थे, तब उन्होंने फिल्म रोजा के लिए ऐसा गाना तैयार किया, जिसने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया था। दुनियाभर के करोड़ों लोगों के दिलों में उनका संगीत बसता है। वे संगीत की दुनिया के सुपरस्टार हैं, जिनके गीत-संगीत का कोई मुकाबला नहीं है, हालांकि संगीतकार के बचपन के दिन खुशगवार नहीं थे। पिता को 9 साल की उम्र में खोने के बाद, उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। वे पढ़ाई छोड़कर 11 साल की उम्र में काम करने लगे थे। उनकी मां करीमा बेगम और बहन ने एक इंटरव्यू ये बातें बताई थीं।

कभी पेट्रोल पंप पर करती थीं काम, महज 100 रुपए में किया गुजारा, कंगना और प्रियंका की ब्लॉकबस्टर से मिली पहचान

मुग्धा गोडसे बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्हें कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन में दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। ये मुग्धा की डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद वह बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों में नजर आईं।

अपने बिंदास अंदाज से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली मुग्धा गोडसे भले ही इंडस्ट्री में अच्छी-खासी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुग्धा कभी पेट्रोल पंप पर काम किया करती थीं जहां उन्हें दिन के केवल 100 रुपए मिलते थे। प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही मुग्धा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। 18 साल बड़े एक्टर राहुल देव संग उनका रिलेशनशिप अक्सर चर्चा में रहता है। ये कपल बीते 9 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। हालांकि, अपने बेटे के चलते राहुल देव ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया है।

मिस इंडिया में लिया था हिस्सा...

ग्लैमर की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत मुग्धा ने मॉडलिंग से की थी। साल 2002 मुग्धा की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम साल रहा। इस साल ने उनका पूरी जिंदगी ही बदल दी। दरअसल, इसी साल मुग्धा ने बेस्ट मॉडल और मिड इंडिया में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब जीता। साल 2004 में मुग्धा फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सेमी-फाइनलिस्ट भी रहीं।



जहां कांवड़, वहां सावन

इन दिनों देशभर में सावन की मदमस्ती और भोले बाबा की आराधना का दौर पूरे परवान पर है। हर कहीं कांवड़ यात्रा का धरम सिर चढ़कर बोलने लगा है। ज्योतिर्लिंगों से लेकर गांव-शहरों और ढाणियों तक के शिवालयों तक कांवड़ियों की भरमार यही बता रही है। कांवड़ और सावन का रिश्ता शाश्वत है। यह श्रद्धा से लेकर श्रद्धा तक और शासन से लेकर प्रशासन के गलियारों तक अमरबेल की तरह छाया हुआ है। पीएम से लेकर सीएम तक, और मंत्री से लेकर संतरी तक और आका से लेकर अंधानुचरों तक कांवड़ किसी न किसी रूप में अपना वजूद बनाए हुए है। जहां कांवड़ का जितना ज्यादा जोर, उतनी ही मस्ती और खुशी। शासन-प्रशासन के भोलेनाथ तो खुश ही होते हैं कांवड़ से। जिधर देखो उधर किसी न किसी भार से या कृत्रिम विनम्रता का लबादा ओढ़े हर आदमी कांवड़ की शकल में नजर आता है। आलाकमान के आगे नेता और साहब के आगे करमचारी, ये सारे कांवड़ का धर्म ही तो निभा रहे हैं सर-सर, मैम-मैडम, मेम-मेम का मूल मंत्र जपते हुए मेमनों को भी लज्जित करते रहे हैं।

लोकतंत्र के महाराजाओं-महारानियों, आत्मघोषित जननायकों के आगे दरबारी, शाही नौकरी का मजा लूट रहे नौकरशाह, मंत्री के सामने सैक्रेट्री, सीएस के आगे आईएएस, आरएएस और विभिन्न प्रजातियों के हाकिम कांवड़ बने हुए अपना कद बढ़ाने के जतन में भिड़े हुए हैं। कई-कई जमातों तो कांवड़ की तर्ज पर झुककर चापलूसी और जी हुजुरी में इतनी माहिर हो चली हैं कि बस। इनके लिए तो पूरा साल भर सावन होता है मौज-मस्ती भरा। राग-दरबारियों के बाड़ों में जो कांवड़ की तरह विनम्रता के रिकार्ड कायम कर रहे हैं वे ही आमजन के सामने धनुष की तरह तने रहकर ऐसे दिखते रहे हैं जैसे कि अभी प्रत्यंचा चढ़ाने की तैयारी हो। इस जहां में हर आदमी कांवड़ बना फिर रहा है। सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक। कोई फाइलों के बोझ से कांवड़ बना हुआ है तो कोई अपने आका या आला अफसर को खुश करने की टेंशन से। जितनी भारी कांवड़ उतनी ज्यादा मन्तें पूरी। फिर अब तो कांवड़ के नाम पर लचीली, मजेदार और गुदगुदाने वाली आकृतियों को समर्पित करने का शगल भी बढ़ता जा रहा है।

आजकल दान-दक्षिणा भरी कांवड़ों का चलन कुछ ज्यादा ही है। जितना बड़ा सूटकेस उतनी कांवड़ियों की आवभगत। वे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं जिनमें पानी नहीं रहा। टाट को छिपाने के लिए पगड़ी-साफों और टोपियों का इस्तेमाल करने वाले खूब सारे हैं जिनके सर पर पानी की बूंद तक ठहर पाना मुश्किल है। वे सारे के सारे बहुरूपियों की तरह पानी का पैगाम गूँजाते हुए चरित्र, संस्कार और मानवता की बातें करने चले हैं। अफसरों और कर्मचारियों की कई-कई जमातें



आजकल दान-दक्षिणा भरी कांवड़ों का चलन कुछ ज्यादा ही है। जितना बड़ा सूटकेस उतनी कांवड़ियों की आवभगत। वे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं जिनमें पानी नहीं रहा। टाट को छिपाने के लिए पगड़ी-साफों और टोपियों का इस्तेमाल करने वाले खूब सारे हैं जिनके सर पर पानी की बूंद तक ठहर पाना मुश्किल है।

तो कांवड़ पूजा में माहिर हो चली हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं का उद्धोष लगाते हुए ये ही तो हैं कांवड़ यात्री, जो पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने मकाम तक पहुंचाने में दिन-रात लगे हुए हैं। यों तो कम से कम चार-पांच लोग चाहिए होते हैं ठेठ तक पहुंचाने के लिए। अब एक-दो ही काफी हैं। किसम-किसम के कांवड़ियों की भीड़ में बेचारे असली कांवड़िये तो वे हैं जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्वों को पूरा करते हुए खुद झुककर कांवड़ की शकल पा चुके हैं। इन बेचारों के भरोसे ही चल रही है इन दुष्टनाथों की सत्ता।

राजनीति से लेकर सत्ता और शासन की वीथियों में रोजाना कांवड़ यात्रा निकलती लगती है। कांवड़िये भर-भर कर लाते हैं और अपने इन भोलेनाथों को अर्पित कर खुश होते हैं। इसकी एवज में इन्हें जो मिलता है उसे हर कांवड़ यात्री अच्छी तरह जानता है। इसकी महिमा का बखान शब्दों में भला कौन कर सकता है। शासन-

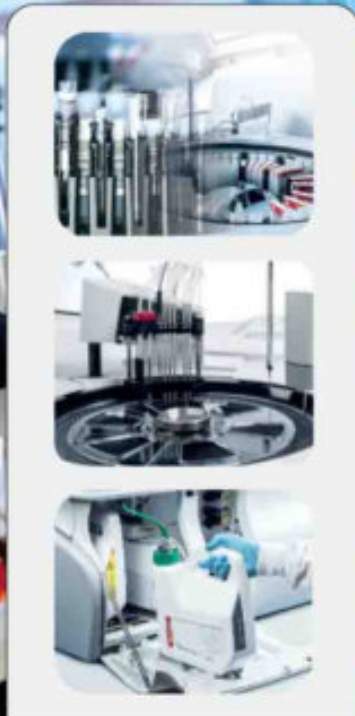
प्रशासन के लूटनाथ किन द्रव्यों से भरी कांवड़ से खुश होते हैं, यह आजकल किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, इनकी हरकतों, करतूतों और कारनामों के कच्चे चिट्ठे रोजाना सभी के सामने आते रहे हैं। इन्हीं से पता चल जाता है इनके शौक, प्रवृत्ति और विलक्षण रुचियों का।

लाल-नीली-पीली बत्तियों वाली गाड़ियों, सरकारी व्हील चेयर्स और एसी रूमस में धंसे जात-जात के इन कांवड़ियों ने आजादी के बाद से जाने कितने आकाओं को नहला दिया है। ये कांवड़िये ही बताते हैं सावन का पता। दो-तीन दशकों से इन कांवड़ियों ने पूरी हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। हर कांवड़ भरी रहने लगी है। कोई सूटकेस के भार से तो कोई फाइलों के बोझ से। सरकार के बजरंगी मंत्रीजी से लेकर भगवा मंत्री और आजकल वोट बैंक के जुगाड़ में नकली धार्मिकता ओढ़े, कपड़ों पर जनेऊ पहनकर पूजा का दिखावा करने वाले, नदियों का पूजन करने वाले, धार्मिकता के जरिये मतदाताओं को लुभाने हिंदुत्व के बाड़ों में घुसपैठ कर अपने आपको धार्मिक एवं भक्त के रूप में पेश करने वाले ढोंगियों ने तो कमाल ही कर दिया है। इनमें से खूब सारे तो खुद कांवड़ यात्रा में शामिल होकर बता चुके हैं कि कांवड़ कितना दखल रखती हैं भक्ति भाव की पूर्णता में। अपनी आंखें खुली रखें, आपको हर कहीं दिखाई देंगे ये कांवड़िये। इनसे सीखिए और खुश करिये अपने आकाओं को। क्योंकि जहां कांवड़ है वहीं सावन है। हम पूरे सालभर पा सकते हैं सावन की मौज मस्ती। फिर हर कहीं लगेगा सावन का हरा-हरा और सब तरफ भरा-भरा।

● डॉ. दीपक आचार्य

ANU SALES CORPORATION

We Deal in
Pathology & Medical
Equipment



Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प



इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है



कोयला इण्डिया लिमिटेड

विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है